रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-128/91 REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 25, 1991/ज्येष्ठ 4, 1913
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 25, 1991/JYAISTHA 4, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

सूचनाएं

नई दिल्ली 26 अप्रैल, 1991

का. आ. 1412.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री के. एल. सिंघल, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे केन्द्रीय शासित क्षेत्र दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्षा इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(19)/91—न्या.]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTICES

New Delhi, the 26th April, 1991

S.O. 1412.—Notices is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority under rule 4 of the said Rules, by Shri K. L. Singhal, Advocate for appointment as a Notary to practise in the Union Territory of Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of his Notice.

[No. F. 5(19)/91-Judl.]

नई दिल्ली 3 मई, 1991

का. आ. 1413—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री दुष्यन्त कुमार त्यागी ने उक्त

प्राधिकारी की उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे शाहदरा दिल्ली व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(23)/91-न्याय अनुभाग]

New Delhi, the 3rd May, 1991

S.O. 1413.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Dushyant Kumar Tyagi for appointment as a Notary to practise in Shahdara, Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(24)/91-Judl.]

नई दिल्ली, 10 मई, 1991

का.आ. 1414.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री पी.वी. सुगमार ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे तांम्बरम, मद्रास व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं- फ. 5(24)/91न्या]
पी.सी. काण्णन, सक्षम अधिकारी

New Delhi, the 10th May, 1991

S.O. 1414.—Notice is hereby givn by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri P. B. Sugumar for appointment as a Notary to practise in Tambaram, Madras.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in wriing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

P. C. KANNAN, Competent Authority

[No. F. 5(24)/91-Judl.]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 3 मई, 1991

का. आ. 1415:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अभिदायी भविष्य निधि (भारत) संशोधन नियम, 1991 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत, 1962 में,—

(i) नियम 16 में, उपनियम (1) मे, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"अधिवर्षिता पर अभिदाता की सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व बारह माह के भीतर, निधि में उसके नाम जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम में से किसी प्रयोजन से जोड़े बिना"

(ii) नियम 17 में, उप नियम (1) में, निम्नलिखित परन्तुक दूसरे परन्तुक के पश्चात अन: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि नियम 16(1) (ग) के अधीन अनुज्ञेय निकाली जाने वाली रकम निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम और उस पर ब्याज की रकम के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(सं. 20/26—पी एण्ड पी डब्ल्यू 88-ई]

स्वर्ण दास, उप सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. AND PENSIONS

(Department of Pension and P.W.)

New Delhi, the 3rd May, 1991

S.O. 1415.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in Indian Audit and Accounts Department the President hereby makes the following rules further to amend the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Contributory Provident Fund (India) Amendment Rules, 1991.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Contributory Provident Fund Rules (India) 1962,—

(i) In rule 16, in sub-rule (1) for Clause (C), the following shall be substituted, namely :—

"within twelve months" before the date of subscriber's retirement on superannuation from the

amount of subscription and interest thereon standing to the credit in the fund without linking to any purpose."

(ii) In rule 17, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted after second proviso, namely :—

"Provided further that the withdrawal admissible under rule 16(1)(C) shall not exceed 90% of the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the fund."

[No. 20(26)-P&PW/88-E (CPF)]

SWARN DASS, Dy. Secy.

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 9 मई, 1991

का. आ. 1416.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थान अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्र संख्या 60/91/90—सी एक्स 7, तारीख 4-4-1991 के पत्र द्वारा प्राप्त की गई उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार निम्नलिखित अपराधों के अन्वेषण के लिए सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है, अर्थात्:—

(क) 1990 के दौरान नासिक रोड, महाराष्ट्र से फैजाबाद, उत्तर प्रदेश तक अभिवहन में न्यायिकेतर स्टाम्पों के गम हो जाने से संबंधित भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं० 45) की धारा 409 के अधीन दण्डनीय अपराध ।

(ख) ऊपर वर्णित अपराधों के संबंध में या उनसे संसक्त प्रत्यत्न दुष्प्रेरण और षड्यंत्र तथा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किया गया था या किए गए कोई अन्य अपराध ।

[सं 228/10/91—ए वी डी II]

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 9th May, 1991

S.O. 1416.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946) the Central Government, with the consent of the State Government of Uttar Pradesh vide its letter No. 60/91/90-CX-7 dated 4-4-1991 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttar Pradesh for investigation of offences as hereunder :—

(a) Offences punishable under Section 409 IPC of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) relating to missing of non-judicial stamps in transit from Nasik Road, Maharashtra to Faizabad, Uttar Pradesh during 1990.

(b) Attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the offences mentioned above and any other offence or offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/10/91-AVD. II]

का० आ 1417.—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अहमदाबाद स्थित विचारण, अपील और पुनरीक्षण न्यायालयों में श्री ईश्वर लाल केशव लाल धनानी और ग्यारह अन्य के विरुद्ध विशेष पुलिस स्थापना मामला संख्या आर० सी 3/82 एस.आई. यू II एस आई सी-1, नई दिल्ली के विचारण का संचालन करने के प्रयोजन के लिए श्री जैड एन शेख अधिवक्ता अहमदाबाद को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[संख्या 225/26/89—ए वी डी-II]

ए सी शर्मा, अवर सचिव

S.O. 1417.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of the Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1947) the Central Government hereby appoints Sri Z. N. Shaikh, Advocate Ahmedabad as Special Public Prosecutor for conducting the trial of Delhi Special Police Establishment Case No. R.C. 3/82-SIU. II/SIC. I, New Delhi against Sri Ishwarlal Keshavlal Dhanani and others in the court of Magistrates and Sessions at Ahmedabad and also in other proceedings arising out of this case in appellate and revisional courts at Ahmedabad.

[No. 225/26/89-AVD-II]

A. C. SHARMA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1991

का आ 1418.—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 68 ढ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना का आ सं 385 (अ) तारीख 29 मई, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की मद (3) में, "श्री जी आर पटवरधन अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "श्री एन पी भट्ट अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा सं. 1/46 यू एस (कोर्ड)/90—एन सी बी/11761/4016]

एल सी० मीहनाथन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NARCOTICS CONTROL BUREAU

New Delhi, the 22nd January, 1991

S.O. 1418.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 68-N of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Department of Revenue S.O. No. 385(E) dated the 29th May, 1989, namely :—

In the said notification in item (3) for the letters and words "Shri G. R. Patwardhan" the letters and words "Shri N. P. Bhat" shall be substituted.

[F. No. I/46/US (Coord)/90-NCB/11761/4016]

M. C. MEHANATHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1991

आयकर

का. आ. 1419.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23) के उपखण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "दि लेट इर्वेड डी० बी मेहताज जोराष्ट्रियन अंजुमन अश् अदारण, कलकत्ता को कर निर्धार वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रखते हुए उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात :—

(i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्ष से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रुप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रुप मे हो जब कि तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती उद्देश्यों की प्राप्त के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग सें लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[सं. 8864 फा. सं./197/44/91—आयकर नि. I]

New Delhi, the 9th April, 1991

(INCOME-TAX)

S.O. 1419.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23-C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Late Ervad D. B. Mehta's Zeroastrian Anjuman Atash Adaran, Calcutta" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11 ;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objective of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[No. 8864/F. No. 197/44/91-IT (AI)]

आयकर

का. आ. 1420.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा भारत से श्रम संघ, कलकत्ता को कर-निर्धारिण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात:—

(i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई हैं।

(ii) कर-निर्धारिती ऊपर उलिलखित कर-निर्धारत वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवराहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसे आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबारों से प्राप्त तथा अभिलाभ से रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्त के लिए प्रसंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखीं जाती हों।

[सं०8862/फा स. 197/46/91-आ.क (नि. 1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1420.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Bharat Sevashram Sangha, Calcutta" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11 ;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objective of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[No. 8862/F. No. 197/46/91-IT (AI)]

आयकर

का.आ. 1421.— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23-ग) के उपखण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 'गुजरात मुख्य मंत्री राहत निधि, गांधीनगर' को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

(3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[सं. 8863/फा. सं. 197/265/89—आयकर नि. I]

(INCOME-TAX)

S.O. 1421.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Gujarat Chief Minister's Relief Fund, Gandhinagar" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1989-90 to 1991-92 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11 ;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objective of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[No. 8863/F. No. 197/265/89-IT (AI)]

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1991

(आयकर)

का.आ. 1421.— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23-ग) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "कलकत्ता जोरास्ट्रियन कम्युनिटीज रिलीजियस एंड चैरिटी फंड्स" को कर-निर्धारण वर्ष 1990—91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर जवाहिरात, फर्नीचर आदि रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

(3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[सं. 8873 फा. सं. / 197/45/91—आयकर नि. I]

New Delhi, the 19th April, 1991

(INCOME-TAX)

S.O. 1422.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Calcutta Zorastrian Community's Religious and Charity Funds" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditons, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11 ;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objective of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[No. 8873/F. No. 197/45/91-IT (AI)]

(आयकर)

का. आ. 1423.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "दि म्यूजिक ऐकेडेमी, मद्रास," को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

(i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतय उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;

(ii) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि कारोबार उक्त कर निरधारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं है नहीं रखी जाती हों।

[सं. 8872/फा.सं. 197/36/91-आयकर नि.-I]
दलीप सिंह, विशेष कार्य अधिकारी

(INCOME-TAX)

S.O. 1423.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Calcutta Zorastrian Community's Religious and the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11 ;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objective of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[No. 8872/F. No. 197/36/91-IT (AI)]
DALIP SINGH, Officer on Special Duty

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 6 मई, 1991

का. आ. 1424.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में फार्म 'क' के परिशिष्ट के रूप में लगी टिप्पणी (इ०) के उपबन्ध 31 मार्च 1991 को स्थिति के अनुसार निम्नलिखित बैंकों पर उनके तुलन-पत्र के संबंध में लागू नहीं होंगे :—

1. यूको बैंक
2. पंजाब नेशनल बैंक,
3. इलाहाबाद बैंक
4. देना बैंक
5. इंडियन ओवरसीज बैंक
6. बैंक आफ इंडिया
7. बैंक आफ बड़ौदा

[सं० 15/2/91-बैंका]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 6th May, 1991

S.O. 1424.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Note (f) appended to the Form 'A' in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the following banks in respect of their balance sheet as at 31st day of March, 1991 :

1. UCO Bank
2. Punjab National Bank

3. Allahabad Bank
4. Dena Bank
5. Indian Overseas Bank
6. Bank of India
7. Bank of Baroda

[No. 15(2)/91/Accts]

नई दिल्ली, 7 मई, 1991

का.आ. 1425 —यतः बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार ने नेशनल बैंक आफ लाहौर, लि. दिल्ली के भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय के लिए 20 फरवरी, 1970 को एक योजना मंजूर की थी।

यतः उक्त योजना के खण्ड 6 के उपखण्ड (ix) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नेशनल बैंक आफ लाहौर लि., दिल्ली की परिसम्पत्तियों का अन्तिम रूप से मूल्याकन नियत तारीख से बारह वर्षों की समाप्ति के पश्चात अपेक्षित था जो कि नियत तारीख को अनन्तिम रूप से मूल्यांकित कर लिया गया है।

यतः भारतीय स्टेट बैंक ने यह अभ्यावेदन किया है कि बड़ी संख्या में परिसम्पत्तियां अन्तर्ग्रस्त होने और बैंक के प्रयासों के बावजूद अधिकांश मदों की वसूलियां अभी बाकी होने के कारण बैंक, विलय योजना के खण्ड 6 के उपखंड (ix) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर परिसम्पत्तियों का अन्तिम रूप से मूल्यांकन करने में असमर्थ रहा है।

और यतः केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद इस बात से संतुष्ट है कि विलय योजना को लागू करने में कठिनाई पैदा हो गई है और उतना समय बढ़ाकर जितने में परिसम्पत्तियों का अन्तिम रूप से मूल्यांकन अपेक्षित है, उक्त कठिनाई को दूर करना जरूरी है।

अतः अब नेशनल बैंक आफ लाहौर लि. दिल्ली के के भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय को 20 फरवरी, 1970 की विलय योजना के खण्ड 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा उसके अनुमोदन से नेशनल बैंक आफ लाहौर लि. दिल्ली को उन परिसम्पत्तियों का, जिनकी वसूली और मूल्यांकन नहीं हुआ है, नियत तारीख से बाईस वर्षों की अवधि के भीतर मूल्यांकन कर लेगा।

[सं. 17/6/82-बी.ओ.-III]

New Delhi, the 7th May, 1991

S.O. 1425.—Whereas on 20th February, 1970 a scheme of amalgamation of the National Bank of Lahore Ltd., Delhi with the State Bank of India was sanctioned by the Central Government in exercise of the powers conferred by and in accordance with Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949.

Whereas under Sub-clause (ix) of Clause 6 of the said Scheme, the State Bank of India was required to make a final valuation of the assets of the National Bank of Lahore Ltd., Delhi, which have been provisionally valued on the prescribed date on the expiry of twelve years from the prescribed date.

Whereas the State Bank of India has represented that in view of the large number of assets involved and the recovery of most of the items yet to be realised inspite of its efforts, it has not been able to make the final valuation within the time specified in sub-clause (ix) of Clause 6 of the Scheme of amalgamation.

And whereas the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India is satisfied that a difficulty has arisen in giving effect to the scheme of amalgamation which it is necessary to remove by extending the time within which the final valuation of assets is required to be made.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause 21 of the Scheme of amalgamation dated 20-2-1970 of the National Bank of Lahore Ltd., Delhi with the State Bank of India, the Central Government hereby directs that the State Bank of India shall in consultation with and with the approval of the Reserve Bank of India value the assets of the National Bank of Lahore Ltd., Delhi which have not been realised and valued, within a period of twenty two years from the prescribed date.

[No. 17/6/82-B.O. III]

का.आ. 1426 — बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में फार्म 'क' के साथ संलग्न टिप्पणी (च) के उपबंध निम्नलिखित बैंकों पर जहां तक उनका सम्बन्ध 31 मार्च, 1990 को उनके तुलन पत्रों से है, लागू नहीं होंगे :

1. द साउथ इंडियन बैंक लि.
2. द यूनाइटिड वैस्टर्न बैंक लि.
3. द लक्ष्मी विलास बैंक लि.

[सं. 15/4/91-बी. ओ.-III]

S.O. 1426.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Note (f) appended to the form 'A' in the Third Schedule to the said Act not apply to the following banks in respect of their balance sheet as at 31st day of March, 1991.

1. The South Indian Bank Limited,
2. The United Western Bank Limited,
3. The Lakshmi Vilas Bank Limited.

[No. 15/4/91-B.O. III]

नई दिल्ली, 10 मई, 1991

का.आ. 1427.—बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में फार्म 'क' के परिशिष्ट के रूप में लगी टिप्पणी (ङ) के उपबंध 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित बैंकों पर उनके तुलन पत्रों के संबंध में लागू नहीं होंगे :—

1. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
2. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया
3. बैंक आफ महाराष्ट्र
4. यूनियन बैंक आफ इंडिया
5. सिंडीकेट बैंक

[सं. 15(2) 91-लेखा]

के. के. मंगल, अवर सचिव

New Delhi, the 10th May, 1991

S.O. 1427.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Note (f) appended to the Form 'A' in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the following banks in respect of their balance sheet as at 31st day of March, 1991 :

1. Central Bank of India,
2. United Bank of India,
3. Bank of Maharashtra,
4. Union Bank of India,
5. Syndicate Bank.

[No. 15(2)91[Accts.]

K. K. MANGAL, Under Secy.

समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क

अधिसूचना सं. 78/1991

इन्दौर, 3 मई, 1991

का.आ. 1428.—समाहर्तालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इन्दौर के निम्नलिखित अधिकारीगण निवर्तन आयु प्राप्त करने पर अधीक्षक समूह 'ख', केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के ग्रेड में उनके नाम के आगे दर्शाई गयी तिथि से शतकीय सेवा से निवृत्त हो गये।

सर्वश्री	
1. एन.बी. सनस	31-01-1991
2. आर.के. झा	31-03-1991

[प.सं. 11(3) 8-गोप/89/1999]

बालकृष्ण अग्रवाल, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

NOTIFICATION NO. 78/1991

Indore, the 3rd May, 1991

S.O. 1428.—The following Superintendents, Central Excise, Gr. 'B' of Indore Collectorate having attained the age of superannuation, retired from Government service on the dates shown against their names :

1. Shri N. B. Sanas	31-01-91
2. Shri R. K. Jha	31-03-91

[C. No. II (3)/8-CON/89/1999]

B. K. AGARWAL, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1991

का.आ. 1429 :—मैसर्स समतेल कलर लि., ग्राम-छपरौला, तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) को मुक्त विदेशी मुद्रा के तहत 70,00,000 रु. के मूल्य के डिफलैक्शन याक के 50,000 नग के आयात के लिए आयात लाइसेंस सं. पी/डी/2280381 दिनांक 7-5-90 जारी किया गया था।

फर्म ने उपर्युक्त आयात लाइसेंस की सीमा शुल्क और विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि इस आधार पर जारी करने के लिए आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क और विनिमय नियंत्रण प्रति उनसे गुम हो गई है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मूल लाइसेंस अपर सीमाशुल्क समाहर्ता, एयरकार्गो यूनिट, नई दिल्ली में पंजीकृत था और इसका आंशिक रूप से इस्तेमाल किया गया था। जिस बकाया मूल्य और मात्रा के लिए अनुलिपि लाइसेंस की आवश्यकता है—वह निम्नानुसार है :—

मूल्य 44,35,080 – रुपए और मात्रा 46,000 नग।

अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक दिल्ली के समक्ष विधिवत रूप से शपथ लेकर रसीदी कागज पर शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं. पी.डी. 2280381 दिनांक 7-5-90 की मूल सीमाशुल्क और विनिमय प्रयोजन प्रतियां फर्म से खो गई हैं/गुम हो गई हैं। यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9(गग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स समतेल कलर लि. को जारी किए गये मूल लाइसेंस सं. पी/डी/2280382 दिनांक 7-5-90 की मूल सीमाशुल्क और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. पार्टी को सीमाशुल्क और विनिमय नियंत्रण प्रतियों की अनुलिपि प्रतियां अलग से जारी की जा रही हैं।

[सं. सप्ली/एनएस/18/2625/डीजीटीडी/एम 90/एसएलएस/534]

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 25th April, 1991

S.O. 1429.—M/s. Samtel Color Ltd., Village Chhapraula, Tehsil Dadri, Distt. Ghaziabad (U.P.) were granted an import licence No. P/D/2280381 dated 7-5-90 for import of 50,000 Nos. of Deflction Yoke valued at Rs. 70,00,000. under Free Foreign Exchange.

The firm has applied for issue of Duplicate Copy of Customs and Exchange Copy of the above mentioned Import Licence On the grounds that the Original Customs and Exchange Control Copy of the licence has been misplaced. It has further been stated that the Original Licence have been registered with the Additional Collector of Customs, Air Cagro Unit, New Delhi and utilised Partly. The balance Value and Qty for which the Duplicate Licence is required is stated to be as under :—

Value Rs. 44,35,080 and Qtv. 46,000 pcs.

In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on Stamped paper duly sworn in before a Notary Public Delhi. I am accordingly satisfied that the Original Customs and Exchange Purpose Copies of Import licence No. P|D|2280381 dt. 7-5-90 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under Sub. Clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dt. 7-12-1955 as amended the said Original Customs and Exchange Copy of the Licence No. P|D|2280381 dt. 7-5-90 issued to M|s. Samtel Color Ltd. is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs and Exchange Purpose Copies of the said licence is being issued to the party Separately.

[No. SUPPI |NS|-18|2625|DGTD|AM'90|SLS|534]

नई दिल्ली, 6 मई, 1991

का.आ. 1430 मैसर्स आर्मर कैमिकल्स लि. 126/1 जी आई डी सी इंडस्ट्रियल एरिया, अंकलेश्वर, गुजरात-393002 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अंतर्गत पैन्सलीन जी पोटाशियम फर्स्ट क्रिस्टल के 20.47 एम एम यू के आयात के लिए 71,64,000 रुपये मात्र (इकहत्तर लाख और चौसठ हजार रुपए मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस सं पी/डी 2280644 दिनांक 29-8-90 दिया गया था।

फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन है कि मूल लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति गुम हो गई/खो गई है। यह भी कहा गया है कि उपर्युक्त लाइसेंस किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी, बम्बई के पास पंजीकृत कराया गया था और इस प्रकार सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का केवल 51,36,503 रुपये तक इस्तेमाल नहीं किया गया है।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक महाराष्ट्र के समक्ष विधिवत शपथ लेकर रसीदी कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं. पी डी 2280644. दिनांक 29-8-90 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति फर्म से गुम हो गई/खो गई है। अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9(गग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स आर्मर कैमिकल्स लि. को जारी की गई मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतिसं. पी/डी/2280644 दिनांक 29-8-90 एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. पार्टी को उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है।

[सं. सप्ली./एनएस/202/डीजीटीडी/एम 91-एस एलएस]

अनीता पथेजा, उप-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

New Delhi, the 6th May, 1991

S.O. 1430.—M/s. Armour Chemicals Ltd., 126/1, GIDC Industrial Area, Ankleshwar, Gujarat-393002 were granted an import licence No. P|D|2280644 dated 29-8-90 for Rs. 71,64,000 only, (Rupees seventy one lakhs and sixty four thousand only) for import of 20.47 mmu of penicillin G. potassium first crystals under GCA.

The firm has applied for issue of Duplicate copy of Customs purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs purposes copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Customs purposes copy of the licence was registered with Customs Authority, Bomoay and as such the value of Customs Purpose copy has not been utilised to the extent of Rs. 51,36,503 only.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duty sworn in before a notary public Maharashtra. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of import licence No. P|D|2280644 dt. 29-8-90 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order 1955 dt. 7-12-1955 as amended the said original Customs Purposes copy No. P/D/2280644 dated 29-8-90 issued to M|s. Armour chemicals Ltd., is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. Suppl.|Ns.|202|DGTD|AM-91|SLS.]

ANITA PATHEJA, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

आदेश

नई दिल्ली, 8 मई, 1991

का.आ. 1431.—मैसर्स पंजाब रिकार्डर्स लिमिटेड, बी-99 फेज-8, एस.ए.एस. नगर, पंजाब को निर्मुक्त विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत इन्डक्शन टाईप वोल्टेज रेग्युलेटर (3 फेज 380 वाल्ट ± 25%)-01 आदि के आयात के लिए 5,93,188/- (पांच लाख तिरानवे हजार एक सौ अठ्ठासी रुपए मात्र) का एक आयात लाइसेंस संख्या I/सी जी 2045196 दिनांक 1-6-90 दिया गया था।

फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा नियंत्रण प्रयोजन प्रति की एक अनुलिपि जारी करने का इस आधार पर अनुरोध किया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि गुम हो गई अथवा खो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की मुद्रा नियंत्रण प्रति किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी के साथ पंजीकृत नहीं है और इस प्रकार मुद्रा नियंत्रण प्रति के मूल्य का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है।

अपनी दलील के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक चण्डीगढ़ के समक्ष विधिवत रूप से शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा दाखिल किया है। तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस संख्या I/सी जी/ 2045196 दिनांक 1-6-90 की मूल मुद्रा नियंत्रण प्रति खो गई अथवा गुम हो गई है। यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 का उपधारा 9(गग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं० पंजाब रिकार्डर्स लि., एस.ए.एस. नगर, पंजाब को जारी की गई उक्त मूल मुद्रा नियंत्रण प्रति संख्या I/ सी जी/ 2045196 दिनांक 1-6-90 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

उक्त लाइसेंस की मुद्रा नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[फा.सं. सी जी II/I डी/9/90-91/135]

सूर्य शर्मा, उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

ORDER

New Delhi, the 8th May, 1991

S.O. 1431.—M/s. Punjab Recorders Ltd., B-99, Phase VIII, S.A.S. Nagar, Punjab were granted an import licence No. I|CG|2045196 dated 1-6-90 for Rs. 5,93,188 (Rupees Five lakhs Ninety Three thousand one hundred and eighty eight only) for import of induction type voltage regulator (3 phase 380V ± 25 per cent)-1 etc. under Free Foreign Exchange.

The firm has applied for issue of Duplicate copy of Exchange Control purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original Exchange Control copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Exchange Control copy of the licence was not registered with any Customs Authority and as such the value of Exchange Control copy has not been utilised at all.

In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Chandigarh. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control copy of import licence No. I|CG|2045196 dt. 1-6-90 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (control) Order, 1955 dt. 7-12-1955 as amended the said original Exchange Control copy No. I|CG|2045196 dated 1-6-90 issued to M/s. Punjab Recorders Ltd., S.A.S. Nagar, Punjab is hereby cancelled.

A duplicate Exchange Control copy of the said licence is being issued to the party separately.

[F. No. CGII/ID/9/90-91/135]

S. SHARMA, Dy. Chief Controller of Imports and Exports

खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1991

का.आ. 1432 :—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 6 के उपविनियम (3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा नीचे अनुसूची में दिए गए उत्पादों को मुहरांकन फीस अधिसूचित करता है।

अनुसूची

क्र.सं.	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	इकाई	प्रति इकाई मुहरांकन फीस	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गेंद वाल्व के लिए पॉलीइथाइलीन के फ्लोट	आईएस : 9762-1982	100 नग	रु. 2.00	1990-10-01

[संख्या के प्रवि/ 13 :10]

S.O. 1432.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby, notifies the marking fee(s) for the products given in the schedule:

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and year of Indian Standard	Unit	Marking fee per unit	Date of Effect
1	2	3	4	5	6
1.	Polyethylene floats for ball valves	IS : 9762—1982	100 Pieces	Rs. 2.00	1990-10-01

[No. CMD/13 : 10]

का.आ. 1433:- भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) दिनांक .....में प्रकाशित (भारतीय मानक ब्यूरो) अधिसूचना संख्यां .....में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि .....के मानक मुहर के डिजाइन में अनुसूची में दिए अनुसार परिशोधन किया गया है ।

अनुसूची

क्र.सं.	मानक मुहर का डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	संबद्ध भारतीय मानक की संख्यां और वर्ष	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS: 9762	पॉलीइथाईलीन के फलोट	आई एस : 9762-1982	1990-10-01

[सं. केप्रवि/13:9]

S.O.1433.—In pursuance of Sub-rule (1) of the rule 9 of Bureau of the Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the Standard Mark(s), for the Indian Standards given in the schedule:

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and year of the Indian Standard	Date of Effect
1	2	3	4	5
1.	IS : 9762 IS: 9762	Polyethylene floats for ball valves	IS : 9762—1982	1990-10-01

[No. CMD/13 : 9]

का.आ. 1434.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड-3 उपखण्ड (2), दिनांक 1984-08-30 की का.आ.सं. 2992 दिनांक 19840922 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना के क्रम में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा नीचे अनुसूची में दिए गए 15,9020-1979 संबंधी मानक मुहर का प्रतिरिक्त डिजाइन अधिसूचित करता है ।

क्र.सं.	मानक मुहर का डिजाइन	अनुसूची उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	संबद्ध भारतीय मानक की संख्यां और वर्ष	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS:9020 SAFETY ONLY	पावर थ्रेशर की सुरक्षा अपेक्षाएं	आई एस : 9020-1979	1991-03-01

[सं. के प्रवि/13:9]

S.O.1434...In supersession of the then Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Civil Supplies (Indian Standards Institution) notification number S.O. 2992 dated 1984-08-30 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) dated 1984-09-22, the Bureau of Indian Standards, hereby, notifies that the design of the Standard Mark for IS : 9020-1979 has been revised as given in the Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of product	No. & Year of the Relevant Indian Standard	Date of Effect
1	2	3	4	5
1.	IS:9020 SAFETY ONLY	Safety requirements for power threshers	IS : 9020—1979	1991-03-01

[No. CMD/13 : 9]

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1991

का.आ. 1435.– भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) की खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिस/जिन भारतीय मानक/मानकों का/के विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है/दिए गए हैं, वह/वे दिनांक ——————को स्थापित हो गया है/हो गए हैं ।

अनुसूची

क.स.	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नए भारतीय मानक द्वारा प्रतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की सं. और वर्ष	टिप्पणी यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 1861 (भाग 1)–1990 चूने का निर्माण-उर्ध्व मिश्रित भरणनुमा भट्टियों द्वारा मार्गदर्शिका भाग 1 चूना पत्थर से (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस : 1861 (भाग V) खंड 1–1975	19990-12-31
2.	आई एस : 1916–1989 क्रकीट आस्तर और लेपन वाले इस्पात सिलिंडर-विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)—	आई एस : 1916–1963	1991-01-31
3.	आई एस : 2455-1990 इमारती लकड़ी के परीक्षण के लिए मॉडल पेड़ों और लट्ठों तथा रुपान्तरण के नमूने लेने की विधि (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस : 2455 1974	—वही—
4.	आईएस :3357-1991 मटका रेशमी कपड़े—विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	आई एस : 3357-1963	1991-01-31
5.	आई एस : 3688-1990 पावर प्रेषण शॉफ्ट-बेलनाकार और 1/10 शक्वाकार शैफ्ट सिरों के आयाम (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस : 3688-1977	1990-11-30
6.	आई एस : 3711-1990 पिटवां इस्पात यांत्रिक परीक्षणों के लिए नमूने और परीक्षण नग चुनना और तैयार करना (पहला पुनरीक्षण)	आई एस :3711 1966	1990-12-31
7.	आई एस : 5137-1990 सीमेंट-भरण के लिए रबड़ के होज-विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस : 5137-1982	1991-01-31
8.	आई एस :5182 (भाग 13)-1991 वायु प्रदूषण मापन की विधि भाग 13 परिवेश—वायु में फ्लोराइड	--	—वही—
9.	आई एस : 5553 (भाग 8)-1990 रिएक्टर विशिष्टि भाग 8 स्मूथिंग रिएक्टर (पहला पुनरीक्षण)	आई एस . 5553 (भाग 2)–1970	—वही—
10.	आई एस : 5626-1990 चेन संवाहक के शैकल प्रकार की संयोजक इकाइयां-विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	आई एस : 56 26 1970	1990-11-30
11.	आई एस : 6909-1990 आतिसल्फेटकृत सीमेंट-विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	आई एस : 6909-1973	1991-01-31
12.	आई एस : 7155 (भाग 4)- 1990 वाहक सुरक्षा के लिए अनुशासित रीति संहिता भाग 4 कंपनकारी/फीडर (पहला पुनरीक्षण)	आई एस : 7155-1974 1974	1991-01-31
13	आई एस : 7368-1990 खांचेदार पिन-सम्पूर्ण लम्बाई की टेपर खांचे वाली विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	आई एस : 7368-1974	—वही—
14.	आई एस : 7396 (भाग 3)-1990 सर्ज टंकियों की जलीय डिजाइन की कसौटी भाग 3 विशेष सर्ज टंकियां	—	—वही—
15.	आई एस : 8052-1990 बोल्हयूट, कुण्डलीनुमा और परतदार कमानियों के उत्पादन के लिए (रेलगाड़ियां के लिए) इस्पात के इंगट, बिलेट और सिल्लियां-विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	आई एस : 8052-1976	1990-12-31
16.	आई एस : 8271 (भाग 5/खंड 12)-1990 आवृत्ति नियंत्रण और चयन में प्रयुक्त क्वाट्ज क्रिस्टल इकाइयां-विशिष्टि भाग 5 दोलकों के लिए सी-एक्स श्रेणी खंड 12 क्वाट्ज क्रिस्टल इकाई टाइप सी एक्स-12	—	1991-01-31
17.	आई एस : 8271 (भाग 5/खंड 13) -1990 आवृत्ति नियंत्रण और चयन में प्रयुक्त क्वाट्ज क्रिस्टल इकाइयां-विशिष्टियां भाग 5 दोलकों के लिए सी-एक्स श्रेणी खंड 13 क्वाट्ज क्रिस्टल इकाई सी एक्स-13	—	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	आई एस : 8271 (भाग 5/खंड 14)-1990 आवृत्ति नियंत्रण और चयन में प्रयुक्त क्वार्टस क्रिस्टल इकाइयां-विशिष्टियां भाग 5 दोलकों के लिए सी एक्स श्रेणी खंड 14 क्वार्टस क्रिस्टल इकाई सी एक्स-14	—	1991-01-31
19.	आई एस : 8271 (भाग 5/खंड 15)-1990 आवृत्ति नियंत्रण और चयन में प्रयुक्त क्वार्टस क्रिस्टल इकाइयां-विशिष्टि भाग 5 दोलकों के लिए सी एक्स श्रेणी खंड 15 क्वार्टस क्रिस्टल इकाई सी एक्स15	—	—वही—
20.	आई एस : 8638 (भाग 1 से 3) 1989 पोत निर्माण— वर्ग ए चुम्बकीय दिक्सूचक कम्पास बक्स और दिगंशी पठन युक्तियां-परीक्षण और प्रमाण की संहिता (पहला पुनरीक्षण)	आई एस : 8638 (भाग 1, 2 और 3)-1977	1990-07-31
21	आई एस : 10216-1988 पाइप चूड़ी जहां चूड़ियों पर दाबरुद्ध जोड़ नहीं बनाए गए है लिमिट गेज युक्ति द्वारा सत्यापन (पहला पुनरीक्षण)	आई एस : 10216—1982	1990-12-31
22.	आईएस : 10242 (भाग 3) खंड 5)—1990 जहाजों में विद्युत संस्थापन भाग 3 उपस्कर खंड 5 संचायक (भंडारण) बैटरियां -विशिष्टि	—	—वही—
23	आई एस : 10738 (भाग 2 खंड 1)— 1990 तरंगपथकों के लिए फ्लेंज विशिष्टि भाग 2 साधारण आयताकार तरंग पथकों के फ्लैंज खंड 1 सामान्य	—	1991-01-31
24	आई एस : 12327 (भाग 2)—1988 सूचना प्रक्रमण हर पार्श्व पर 80 ट्रैक के ऊपर, 13262 फुट प्रति रेडियन पर रूपान्तरित आवृत्ति मॉड्यूलेशन रिकार्डिंग का प्रयोग करते हुए 130 मिमी (5.25 इंच) नम्य चक्रती कार्टिज पर आंकड़ा परिवर्तन भाग 2 ट्रैक फार्मेट ए 77 ट्रैक के लिए	—	1990-10-31
25.	आई एस : 12260-1989 सूचना प्रक्रमण-सूचना अन्त परिवर्तन के लिए चुम्बकीय टेप कैसेट और कार्टिज लेबलिंग और फाइल रचना	—	1990-12-31
26.	आई एस : 1271—31989 अल्प वोल्टता पावर और सिग्नल लाइनों पर अल्पावधि ट्रांसिट की मापन विधियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत ।	—	1990-10-31
27.	आईएस : 12771-1989 नाभिकीय रिएक्टर मापयंत्रण के सामान्य लक्षण	—	1990-12-31
28.	आईएस : 12772-1989 नाभिकीय रिएक्टर मापयंत्रण और नियंत्रण के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग	—	—वही—
29	आईएस : 12879 (भाग 1) -1990 तकनीकी ड्राइंग और अन्य ड्राइंग कार्यालय प्रलेखों की माइक्रोफिल्मिंग भाग 1 प्रचालन प्रक्रिया	—	1990-07-31
30.	आई एस : 12879 (भाग 2)—1990 तकनीकी ड्राइंग और अन्य ड्राइंग कार्यालय प्रलेखों की माइक्रोफिल्मिंग भाग 2 गुणता की कसौटी और नियंत्रण	—	1990-11-30
31.	आई एस : 12940-1990 प्रलेखन-पुस्तकालय सांख्यिकी-मार्गदर्शिका	—	1991-01-31
32.	आई एस : 12941-1990 अधिक्षमता वाले डोल उत्पादकों के चयन और प्रयोग की रीति संहिता ।	—	1991-01-31
33.	आई एस : 12943-1990 पोत्रीसी केबलों के लिए पीतल के ग्लैंड-विशिष्टि	—	—वही—
34.	आई एस : 12948-1990 टंगस्टन हैलोजन लैम्प (गैर वाहन)-विशिष्टि	—	1990-11-30
35.	आई एस : 12960-1990 पेंच प्रभरकों (स्क्रू फीडर) की पावर संबंधी आवश्यकता ज्ञात करने के लिए सामान्य अपेक्षाएं	—	—वही—
36.	आई एस : 12961-1990 माटी उत्पादकों के लिए U कड़ीदार जंजीर-विशिष्टि	—	1990-12-31
37.	आई एस : 12971-1990 सड़क पर चलने वाले वाहन-व्यापारिक वाहन-पावर टेक आफ (पोटीओ) के लिए मुक्तांतर खोल	—	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)
38.	आई एस : 12972-1990 सड़क पर चलने वाले वाहन-व्यापारिक वाहन-टीपर माउन्टेड पावर टेकआफ (पीटीओ) के लिए कनेक्शन	—	—वही—
39.	आई एस : 12973-1990 सड़क पर चलने वाले वाहन-व्यापारिक वाहन-ट्रक पावर टेक आफ (पीटीओ) के लिए पार्श्व छिद्र	—	1990-01-31
40.	आई एस : 12979-1990 रैखिक संकुलन सांचों का विशिष्टि	—	—वही—
41.	आई एस : 12982-1991 पिन और स्प्रिंगदार पिन अपरूपण परीक्षण	—	—वही—
42.	आई एस : 12997 (भाग 1) 1989 टेलीविज़न सिग्नल बूस्टर—विशिष्टि भाग 1 चौड़े बैंड, वीएच एफ रेंज	—	1990-12-31
43.	आई एस : 13003-1991 वस्त्रादि इंटरलॉक बुना (निट्-टेड) सूती कपड़ा—विशिष्टि	—	1991-01-31
44.	आई एस : 13004 (भाग 1) 1990 अन्तःदेशीय जलयान के फेयरलीड विशिष्टि भाग 1 ट्रू-लिप फेयर लीड	—	—वही—
45.	आई एस : 13005-1991 सांड के वीर्य के विकल्पी रोगाणुजनक सूक्ष्मजीवों की पहचान विधि	—	—वही—

इन मानकों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली और क्षेत्रीय कार्यालयों बम्बई, कलकत्ता चंडीगढ़ और मद्रास तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना और त्रिवेन्द्रम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[सं. के.प्र.वि./13 : 2]

New Delhi, the 26th April, 1991

S.O. 1435—In pursuance of clause (b) of Sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules 1987. The Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standard(s), Particulars of which is/are given in the Schedule hereto annexed, has/have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Year and Title of the Indian Standard(s) Established	No. and year of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard	Date of Establishment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 1861 (Part 1)—1990 Manufacture of lime in vertical mixed-feed type kilns—Guide Part 1 From limestone (Second Revision)	IS : 1861 (Part 1/Sec 1)—1975	1990-12-31
2.	IS : 1916—1989 Steel cylinder pipes with concrete lining and costing—Specification (First Revision)	IS : 1916—1963	1991-01-31
3.	IS : 2455—1990 Method of sampling of model trees and logs and their conversion for timber testing (Second Revision)	IS : 2455—1974	-do-
4.	IS : 3357—1991 Matka silk fabrics—Specification (First Revision)	IS : 3357—1965	-do-
5.	IS : 3688—1990 Power transmission-shafts, dimensions for cylindrical and 1/10 conical shaft ends (Second Revision)	IS : 3688—1977	1990-11-30
6.	IS : 3711—1990 Wrought steel-selection and preparation of samples and test pieces for mechanical test (First Revision)	IS : 3711—1966	1990-12-31
7.	IS : 5137—1990 Rubber hose for cement grouting—Specification (Second Revision)	IS : 5137—1982	1991-01-31
8.	IS : 5182 (Part 13)—1991 Methods of measurement of air pollution Part 13 Total fluorides in ambient air	—	-do-
9.	IS : 5553 (Part 8)—1990 Reactors—Specification Part 8 Smoothing reactors (First Revision)	IS : 5553 (Part 2)—1970	-do-
10.	IS : 5626 –1990 Chain conveyors- connector units, shackle type—Specification (First Revisoin)	IS : 5626 –1970	1990-11-30

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	IS : 6909—1990 Supersulsulphated cement — Specification (First Revision)	IS : 6909—1973	1990-01-31
12.	IS : 7155 (Part 4)—1990 Code of recommended practice for conveyor safety Part 4 Vibrating conveyor/feeder (First Revision)	IS : 7155—1974	-do-
13.	IS : 7368 —1990 Grooved pins-full-length taper grooved —Specification (First Revision)	IS : 7368—1974	-do-
14.	IS : 7396 (Part 3)—1990 Criteria for hydraulic design of surge tanks Part 3 Special surge tanks	—	-do-
15.	IS : 8052—1990 Steel ingots, billets and blooms for the production of volute, helical and laminated springs (Railway rolling stock) —Specification (First Revision)	IS : 8052—1976	1990-12-31
16.	IS : 8271 (Part 5/Sec 12)— 1990 Quartz crystal units used for frequency control and selection—Specification Part 5 Series CX for oscilators Section 12 Quartz crystal unit type CX-12	—	1991-01-31
17.	IS : 8271 (Part 5/Sec 13)— 1990 Quartz crystal units used for frequency control and selection—Specification Part 5 Series CX for Oscilators Section 13 Quartz crystal unit type CX-13	—	-do-
18.	IS : 8271 (Part 5/Sec 14)— 1990 Quartz crystal units used for frequency control and selection —Specification Part 5 Series CX for Oscillators Section 14 Quartz crystal unit type CX-14	—	-do-
19.	IS : 8271 (Part 5/Sec 15)— 1990 Quartz crysial units used for frequency control and selection—Specification Part 5 Series CX for Oscillators Section 15 Quartz crystal unit type CX-15	—	-do-
20.	IS : 8638 (Parts 1 to 3) — 1989 Shipbuilding —class a magnetic compasses, binnacles and azimuth) reading devices-code for testing and certification (First Revision)	IS : 8638 (Parts 1, 2 and 3)— 1977	1990-07-31
21.	IS : 10216—1988 pipe threads where pressure - tight joints are not made on the thr ads —verification by means of limits gauges (First Revision)	IS : 10216—1982	1990-12-31
22.	IS : 10242 (Part 3/Sec 5)— 1990 Electrical installations in ships Part 3 Equipment Section 5 Accumulator (Storage) Batteries— Specification	—	-do-
23.	IS : 10738 (Part 2/Sec. 1) —1990 Flanges for waveguides—Specification Part 2 Flanges for ordinary rectangular waveguides Section 1 General	—	1991-01-31
24.	IS : 12327 (Part 2)—1988) Information processing-data interchange on 130 mm (5.25 in) flexible dsik cartridges using modified frequency modulation recording at 13262 ft prad. on 80 tracks on each side Part 2 Track format a for 77 Tracks	—	1990-10-31
25.	IS : 12660 —1989 Information processing-magnetic tape cassette and cartridge labelling and file structure for information interchange	—	1990-12-31
26.	IS : 12743—1989 Guide on methods of measurement of short duration transients on low voltage power and signal lines	—	1990-12-31
27.	IS : 12771 —1989 General characteristics of nuclear reactor instrumentation	—	1990-12-31
28.	IS : 12772—1989 Application of digital computers to nuclear reactor instrumentation and control	—	-do-
29.	IS : 12879 (Part 1)—1990 Microfilming of technical drawings and other drawing office documents Part 1 Operating procedures	—	1990-07-31

(1)	(2)	(3)	(4)
30.	IS : 12879 (Part 2)—1990 Microfilming of technical drawings and other drawing office documents Part 2 Quality criteria and control	—	1990-11-30
31.	IS : 12940—1990 Documentation - library statistics—guide	—	1991-01-31
32.	IS : 12941—1990 Code of practice for selection and use of super capacity bucket elevator	—	1991-01-31
33.	IS : 12943—1990 Brass glands for PVC cables—Specification	—	-do-
34.	IS : 12948—1990 Tungsten halogen lamps (non-vehicle) Specification	—	1990-11-30
35.	IS : 12960—1990 Determination of power requirement of screw feeder—General requirements	—	-do-
36.	IS : 12961 -1990 U-link for chains for bucket elevators –Specification	—	1990-12-31
37.	IS : 12971—1990 Road vehicles--commercial vehicles—clearance envelope for power take-offs (PTO)	—	-do-
38.	IS : 12972—1990 Commercial road vehicles connections for rear-mounted power take-offs (PTO)	—	-do-
39.	IS : 12973—1990 Commercial road vehicles—side openings for truck power take-offs (PTO)	—	1991-01-31
40.	IS : 12979—1990 Mould for determination of linear shrinkage—Specification	—	-do-
41.	IS : 12982—1991 Pins and grooved pins –shear test	—	-do-
42.	IS : 12997 (Part 1)—1989 Television signal booster—Specification Part 1 Wide band, VHF range	—	1990-12-31
43.	IS : 13003—1991 Textiles—fabric, cotton, interlock knitted—Specification	—	1991-01-31
44.	IS : 13004 (Part 1)—1990 Inland vessels—fairleads—Specification Part 1 Two-lip Fairleads	—	-do-
45.	IS : 13005—1991 Detection of facultative pathogenic micro-organisms of bull semen –Method	—	1991-01-31

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi and Regional Offices: Bombay, Calcutta, Chandigarh and Madras and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13 : 2]

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1991

का.आ. 1436.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) की खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिस/जिन भारतीय मानक/मानकों का/के विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है दिए गए हैं, वह/वे निम्न दिनांक को स्थापित हो गया है/हो गए हैं ।

अनुसूची

क्र. सं.	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नए भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की सं. और वर्ष	लागू होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस : 747-1991 हथकरघा निर्मित सूती कपड़ा, रंजित--विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस : 747 -1982	1991-01-31
2.	आई एस : 1244-1990 हथकरघे का सूती लट्ठा--विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	आईएस : 1244-1958	1990-11-30
3.	आई एस : 1245-1990 हथकरघा निर्मित पाजामें का सूटी कपड़ा—विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	आई एस:1245-1958	1991 01-31
4.	आई एस : 1849 (भाग V/सैक 1)-1990 उर्ध्व मिश्रित भरण चूना भट्टी का डिजाइन और संस्थापन मार्गदर्शिका भाग 1 चूना पत्थर के लिए खंड 1 चिनाई प्रकार शैफ्ट (दूसरा पुनरीक्षण)	आईएस : 1849 (भाग V/सैक1))-1976	1991-01-31

(1)	(2)	(3)	(4)
5	आई एस : 1954-1990 सूत वस्त्रों की लम्बाई और चौड़ाई नापने की विधि (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस : 1954-1969	1990-12-31
6.	आई एस : 2316-1990 कलरीमिति और आयतनमिति विश्लेषणों के लिए मानक विलयन तैयार करने की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	आईएस : 2316-1968	1990-12-31
7.	आई एस : 2720 (भाग 10) 1991 मृदा परीक्षण विधियां भाग 10 अपरिबद्ध संपीडन सामर्थ्य ज्ञात करना (दूसरा पुनरीक्षण)	आईएस2720 (भाग 10)- 1973	1991-01-31
8.	आई एस : 2985-1990 जहाज संरचना के लिए इस्पात ढलाइयां-विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	आई एस : 2985-1982	1990-11-30
9.	आई एस . 2986-1990 समुद्री इंजनों और बायलरों के लिए इस्पात की ढलाइयां (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस : 2986-1980	1990-12-31
10.	आई एस : 3358-1991 लुपिओन रेशम का कपड़ा-विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	आईएस : 3358-1965	1991-01-31
11.	आई एस : 3663-1991 कार्यालय प्रयोजनों के लिए मेज और कुर्सियों के आयाम (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस :3363-1991	1991-01-31
12.	आई एस : 4378 (भाग 1) चिमटियां-विशिष्टि भाग 1 त्रिकणी कर्तन चिमटियां (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस: 4378-1973	—वही—
13.	आई एस: 4838-1990 स्कूली बच्चों आयु वर्ग 5-17 के लिए मानमिति आयाम (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस: 4848 (भाग 1) 1969 आई एस : 4838 (भाग 2) 1979	1990-12-31
14.	आई एस : 7383-1990 खांचेदार पिन-तीसरी लम्बाई केन्द्र खांचा विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	आई एस : 7383-1974	1991-02-28
15.	आई एस : 7384-1990 खांचेदार पिन-पूरी लम्बाई की समानान्तर खांचे वाली पायलट सहित-विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	आई एस:7384-1974	1991-01-31
16.	आई एस : 7386-1990 खांचेदार पिन-आधी लम्बाई की विपरीत टेपर खांचे वाली विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	आई एस : 7386-1974	1991-02-20
17.	आई एस : 7624-1990 डीजल इंजनों और रेलकारों के लिए सीसा अम्ल स्टार्टर बेटरियां-विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	आई एस:7624	1990-12-31
18.	आई एस : 7669-1990 शैम्पू साबुन से बना विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	आई एस :7669-1975	1990-11-30
19.	आई एस : 8271(भाग 5/सैक-II) 1990 आवृत्ति नियंत्रण और चयन में प्रयुक्त क्वार्टज क्रिस्टल इकाइयां—विशिष्टि भाग 5 दोलकों के लिए सीएक्स श्रेणी खंड II क्वार्टज क्रिस्टल टाइप सीएक्स श्रेणी खंड II क्वार्टस क्रिस्टल टाइप सीएक्स-II	—	1990-12-31
20.	आई एस : 8890-1991 अक्ष शल्य क्रिया उपकरण-क्लैम्प, श्वसनी, प्ररूप, आकार एवं आयाम (पहला पुनरीक्षण)	आई एस: 8890 1978	1991-01-31
21.	आई एस : 10738-(भाग 2/सैक 3)-1990 तरंग पथकों के लिए फ्लैंज की विशिष्टि भाग 2 साधारण आयताकार तरंग पथकों के लिए फ्लैंज भाग 3 फ्लैंज टाइप सी	—	1990-12-31
22.	आई एस :12572 (भाग II)-1990 जैविक खतरों के लिए चिकित्सा युक्तियों के मूल्यांकन की मार्गदर्शिका भाग II नेत्र क्षोभ की परीक्षा विधि	—	1990-11-?0
23.	आई ए : 12922(भाग I)-1989—7928 फीट प्रेय पर 80 ट्रैक पर रुपान्तरित आवृत्ति रिकार्डिंग का प्रयोग करते हुए 90 मिमी नम्य भाग 1 आयाम, भौतिक और चुम्बकीय		—वही—
24.	आई एस : 12922 (भाग 2)-1989-7958 फीट प्रेड पर 80 ट्रैक पर दूर ओर रुपान्तरित आवृत्ति रिकार्डिंग का प्रयोग करते हुए 90 मिमी नम्य चक्री कार्टिज की विशिष्टि भाग 2 ट्रैक फार्मेट	—	1990-10-31

(1)	(2)	(3)	(4)
25.	आई एस : 12933(भाग 2)-1990 सौर संग्राहक की सपाट पट्टी भाग 2 घटक	—	1990-12-31
26.	आई एस: 12933 (भाग 3) 1990 सौर संग्राहक की सपाट पट्टी भाग 3 मापन उपकरण	—	—वही—
27.	आई एस : 12947-1990 नेत्र शल्य क्रिया उपकरण-तनाव मापी-विशिष्टि	—	1991-02-28
28.	आईएस : 12957-1990 तरल नमूने ग्रहस्तान तंत्र की कार्यकारिका अभिव्यक्ति	—	1991-01-31
29.	आई एस : 12965-1990 विद्युत चुम्बकीय (भैवर धारा) परीक्षण में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली	—	1990-12-31
30.	12977-1990 आर्क भट्टी ट्रांसफार्मर विशिष्टि	—	1991-02-28
31.	आई एस : 12980-1990 अतिशबाजी हवाई विशिष्टि	—	1990-11-30
32.	आई एस : 12981-1991 सामान्य सभक लोहतत्व अधिवाले विशिष्टि	—	1991-02-28
33.	आई एस : 13006-1990 हिमीयन ग्रिल विशिष्ट	—	1991-01-31

इन मानकों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो के मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और क्षेत्रीय कार्यालयों, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, और मद्रास और शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना और त्रिवेन्द्रम में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं ।

[सं. के.प्र.वि/13 : 2]

New Delhi, the 29th April, 1991

S. O. 1436.—In pursuance of clause (b) of Sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules 1987, The Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standard(s), Particulars of which is/are given in the Schedule hereto annexed, has/have been established in the date indicated against each:

SCHEDULE

Sl. No.	No. Year and Title of the Indian Standard(s) Establishment	No. and year of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard	Date of Establishment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 747—1991 Handloom cotton bunting cloth, dyed—Specification (Second Revision)	IS : 747—1982	1991-01-31
2.	IS : 1244—1990 Handloom cotton long cloth—Specification (First Revision)	IS : 1244—1958	1990-11-30
3.	IS : 1245—1990 Handloom cotton pyjama cloth, grey—Specification (First Revision)	IS : 1245 —1958	1991-01-31
4.	IS : 1849 (Part 1/Sec 1).—1990 Design and installation of vertical mixed feed lime kiln—Guide Part 1 For limestone Section 1 Masonry type shaft (Second Revision)	IS : 1849 (Part 1/Sec 1)—1976	-do-
5.	IS : 1954—1990 Determination of length and width of woven fabrics—Methods (Second Revision)	IS : 1954—1969	1990-12-31
6.	IS : 2316—1990 Methods of preparation of standard solutions for colormetric and volumetric analysis (Second Revision)	IS : 2316—1968	1990-12-31
7.	IS : 2720 (Part 10)—1991 1991 Methods of test for soils Part 10 Determination of unconfined compressive strength (Second Revision)	IS : 2720 (Part 10)—1973	1991-01-31
8.	IS : 2985—1990 Steel castings for ship's structure Specification (Third Revision)	IS : 2985—1982	1990-11-30
9.	IS : 2986—1990 Steel castings for marine engines and boilers—Specification (Second Revision)	IS : 2986—1980	1990-12-31
10.	IS : 3358 —1991 Dupion silk fabrics—Specification (First Revision)	IS : 3358—1965	1991-01-31
11.	IS : 3663—1991 Dimensions of tables and chairs for office purposes (Second Revision)	IS : 3663—1981	-do-
12.	IS : 4378 (Part 1)—1990 Nippers—Specification Part 1 Diagonal cutting nippers (Second Revision)	IS : 4378—1973	-do-
13.	IS : 4838—1990 Anthropometric dimensions for school children age group 5-17 years (Second Revision)	IS : 0838 (Part 1)—1969 IS : 4838 (Part 2)—1979	1990-12-31
14.	IS : 7383—1990 Grooved pins-third length centre grooved —Specificaton (First Revision)	IS : 7383—1974	1991-02-28

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	IS : 7384—1990 Grooved pinsfull—length parallel grooved, with pilot—Specification (First Revision)	IS : 7384—1974	1991-01-31
16.	IS : 7386—1990 Grooved pinshalf length reverse taper grooved—Specification (First Revision)	IS : 7386—1974	1991-02-28
17.	IS : 7624—1990 Lead-acid starter batteries for diesel locomotives and railcars—Specification (First Revision)	IS : 7624—1975	1990-12-31
18.	IS : 7669—1990 Shampoo, soap based—Specification (First Revision)	IS : 7669—1975	1990-11-30
19.	IS : 8271 (Part 5/Sec 11)—1990 Quartz crystal units used for frequency control and selection—Specification Part 5 Series CX for Oscillators Section 11 Quartz Crystal Unit Type CX-11	—	1990-12-31
20.	IS : 8890—1991 Thoracic surgery instruments—clamps, bronchus-types, shapes and dimensions (First Revision)	IS : 8890—1978	1991-01-31
21.	IS : 10738 (Part 2/Sec 3) 1990 Flanges for wave guides—Specification Part 2 Flanges for ordinary rectangular waveguides Section 3 Flange Type *B*	—	1990-12-31
22.	IS : 12572 (Part 11)—1990 Guide for evaluation of medical devices for biological hazards Part 11 Method of test for Eye irritation)	—	1990-11-30
23.	IS : 12922 (Part 1)—1989 Specification for 90 mm flexible disk cartridge using modified frequency recording at 7958 ftprad ON 80 tracks on each side Part 1 Dimensional, physical and magnetic characteristics.	—	-do-
24.	IS : 12922 (Part 2)—1989 Specification for 90 mm flexible disk cartridge using modified frequency recording at 7 958 ftoprad ON 80 tracks on each side Part 2 Track format	—	1990-10-31
25.	IS : 12933 (Part 2)—1990 Solar flate plate collector Part 2 Components	—	1990-12-31
26.	IS : 12933 (Part 3)—1990 Solar flat plate collector Part 3 Measuring instruments	—	-do-
27.	IS : 12947—1990 Eye surgery instruments—tonometers—Specification	—	1991-02-28
28.	IS : 12957—1990 Expression o f performance of sample handling systems for fluids	—	1991-01-31
29.	IS : 12965—1990 Glossary of terms used in electromagnetic (Eddy current) testing	—	1990-12-31
30.	IS : 12977—1990 ARC furnace transformers—Specification	—	1991-02-28
31.	IS : 12980—1990 Fireworks rockets—Specification	—	1990-11-30
32.	IS : 12981—1991 Common salt-iron fortified—Specification	—	1991-02-28
33.	IS : 13006—1990 Free grill—Specification	—	1991-01-31

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices: Bombay, Calcutta, Chandigarh and Madras and also Branch Office: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13 : 2]

का.आ. 1437.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 5 के उपविनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिस/जिन लाइसेंस (सों) का/के विवरण नीचे दिया गया है/दिए गए हैं, उसे/उन्हें उसके/उनके आगे दी गई तिथि से रद्द कर दिया गया है/ दिए गए हैं।

अनुसूची

क्र.सं.	लाइसेंस संख्या तथा दिनांक	लाइसेंसधारी का नाम व पता	रद्द लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु/प्रक्रम तथा सम्बद्ध भारतीय मानक	रद्द किए जाने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2102321	मै. राव इंसुलेटिंग कं. प्रा.लि., व्हाइट फील्ड मेन रोड, बंगलोर-560066	टंगस्टन तंतु बिजली के बल्ब के लिए टोपी, बी 22/25× 28 (IS:9206-1979)	1990-04-16

[सी एम डी /65/2102321]

एस. सुब्रह्मण्यन, अपर महानिदेशक

S.O. 1437.— In pursuance of sub-regulation (6) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulation 1988, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the licence(s) particulars of which is/are given below has/ have been cancelled with effect from the date indicated:

SCHEDULE

Licence No. (CM/L—)	Name and Address of the licensee	Article/Process with relevant Indian Standard covered by the licence cancelled	Date of Cancellation
1	2	3	4
21023 21	M/s Rao Insulating Co. Pvt. Ltd., Whitefield Main Road, Whitefield, Bangalore—560066	Caps for tungsten filament general electric lamps B22/25 x 26 (IS: 9206 —1979)	1990-04-16

[No. CMD/55 : 21023 21]

S. SUBRAHMANYAN, Addl. Director General

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

(Office of the Director General of Meteorology)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd May, 1991

S.O. 1438.—In the notification of the Government of India in the department of India Meteorological Department (Office of the Director General of Meteorology) notification No. 790, dated 4-3-91 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 16-3-91 :—

1. Relating to the post of Assistant Meteorologist, Senior Personal Assistant in India Meteorological Service-Group 'B' Gazetted—

(i) at page 1312 under column 3 (Authority Competent to impose penalties) line 3 for the words "Additional Director of Meteorology" read "Additional Director General of Meteorology";

(ii) at page 1314 under column 3 (Authority Competent to impose penalties) line 26 for the words "Director or Meteorological working as Head Office" read "Director or Meteorologist working as Head of Office".

[V-00101 Part IV(A)]

S. M. KULSHRESTHA, Director General of Meteorology

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 मई, 1991

का.आ. 1439.—उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा 2 की उप-धारा (ङ) के अनुसरण में केन्द्र सरकार श्री के.जी. कृष्णा-मूर्ति, संयुक्त सचिव (उर्वरक) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) को श्री रवि मोहन सेठी के स्थान पर दिनांक 19-4-91 से उर्वरक नियंत्रक नियुक्त करती है।

[सं. 1-6/91-उर्वरक विधि]

अर्जुन प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 13th May, 1991

S.O. 1439.—In pursuance of sub-clause (e) of clause 2 of the fertiliser (Control) Order, 1985, the Central Government hereby appoints, with effect from 19-4-1991, Shri K. G. Krishnamoorthy, Joint Secretary (Fertiliser), Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) as Controller of Fertilisers vice Shri R. M. Sethi.

[No. 1-6/91-Fert. Law]

ARJUN PRASAD, Under Secy.

(ग्रामीण विकास विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, 8 मई, 1991

का.आ. 1440.—साधारण श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन नियमावली, 1988 के अधीन मुझको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर दिनांक 25-4-75 के कार्यालय आदेश सं. 7(15) 73-सामान्य डी-3 में आंशिक संशोधन करते हुए, मैं, श्री.पी.बिहारी, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, एतद्द्वारा, स्तम्भ (1) में उल्लिखित नियमों के अनुसरण में जैसा कि स्तम्भ (2) में शक्तियों के प्रयोग के अधिकार विनिर्दिष्ट है, स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार के अधिकारियों को राजस्थान राज्य में घरेलू मंडी के लिए कृषि उपज (श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) के अधीन निर्धारित श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन नियमों तथा श्रेणी अभिधानों के अनुसार कृषि तथा अन्य उत्पादों के श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन के बारे में अधिकार देता हूं।

साधारण श्रेणीकरण चिन्हांकन नियमावली, 1988 के नियम का संदर्भ	प्रत्यायुक्त शक्तियां	राज्य के अधिकारी का पदनाम
1	2	3
नियम 3(4)	घरेलू श्रेणीकरण के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु आवेदन प्राप्त करना।	निदेशक, कृषि विपणन राजस्थान

1	2	3
नियम 3(5)	आवेदक की सक्षमता के सत्यापन तथा परिसरों, प्रयोगशाला, संसाधन एककों के निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा घरेलू श्रेणीकरण के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु सिफारिश करना।	उप निदेशक (श्रेणीकरण) कृषि विभाग, राजस्थान
नियम 4	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के बारे में प्राधिकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करना।	निदेशक, कृषि विपणन राजस्थान
नियम 8(2)	एगमार्क श्रेणीकरण के लिए प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला के अनुमोदन की सिफारिश करना।	—वही—
नियम 12	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के बारे में श्रेणी अभियान चिन्हों को जारी करना अथवा प्रयोग को रोकना।	—वही—
नियम 14	किसी भी अनुसूचित वस्तु के बारे में सूचना, रिपोर्ट, विवरणकी प्राप्त करना।	—वही—
नियम 3(3)(ख)	प्राधिकृत श्रेणीकरण परिसरों का निरीक्षण करना तथा यह पता लगाना कि विकेन्द्रीकरण वस्तुओं का श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन सही रूप से किया गया है।	रसायनज्ञों को उनके अपने अपने क्षेत्राधिकार में
नियम 3(8)(ग)	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के प्राधिकृत पैकरों द्वारा रखे गए रिकार्ड की जांच करना।	—वही—
नियम 3(8)(घ)	श्रेणी अभियान चिन्ह लगे हुए किसी पैकेज को खोलना तथा निरीक्षण करना तथा किसी भी श्रेणीकृत उपज के नमूने लेना परन्तु सभी नमूनों के लिए संवाय किया जाएगा।	रसायनज्ञों को उनके अपने अपने क्षेत्राधिकार में
नियम 3(8)(ङ)	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के अधीन आने वाली किसी भी श्रेणीकृत वस्तु का श्रेणी अभिधान चिन्ह रद्द करना या उसे हटाना यदि वह विहित श्रेणी विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है।	—वही—

[सं. एफ-11011/2/90 एफ सी 3]

(Department of Rural Development)

Directorate of Marketing and Inspection

Faridabad, 8th May, 1991

S.O. 1440.—In exercise of the powers conferred on me under the General Grading and Marking Rules, 1988 and in partial modification of this office order No. 7(15)/73-Gen. D. III dated 25-4-75 on the subject, I, O.P. Behari, Agricultural Marketing Adviser to the Government of India hereby delegate, in pursuance of the rules cited in column (1), authority to exercise the powers, as specified in column (2), to the officers of the State Government, specified in column (3), in respect of grading and marking of agricultural and other produce in accordance with the grade designations and the Grading and Marking Rules prescribe under the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) for domestic market in the State of Rajasthan.

Reference rule of the GGM Rules 1988	Powers delegated	Desgination of the State Officer
1	2	3
Rule 3(4)	To receive the application for grant of Certificate of Authorisation for domestic grading.	Director, Agricultural Marketing Rajasthan.

1	2	3
Rule 3(5)	To arrange for verification of bonafides of the applicant and inspection of the premises Laboratory, processing units and to recommend grant of C.A. for domestic grading.	Deputy Director (Grading) Agricultural Marketing Department Rajasthan.
Rule 4	To renew the certificate of Authorisation in respect of de-centralised grading;	Director, Agricultural Marketing Rajasthan.
Rule 8(2)	To recommend approval of private commercial laboratory for Agmark grading.	-do-
Rule 12	To withhold issue or use of grade designation marks in respect of de-centralised grading;	-do-
Rule 14	To obtain information, report return in respect of any of the Scheduled articles;	-do-
Rule 3(8)(b)	To inspect the authorised grading premises and to ascertain that grading and marking of de-centralised commodities is correctly performed.	Chemist in their respective jurisdiction.
Rule 3(8)(c)	To examine the record maintained by the authorised packers of de-centralised grading;	-do-
Rule 3(8)(d)	To open and inspect any package bearing grade designation mark and to take samples of any graded produce provided all samples shall be paid for.	-do-
Rule 3(8)(e)	To cancel or to remove the grade designation mark from any graded article covered under decentralised grading if, found not conforming to the prescribed grade specification.	-do-

[No. Q-11011/2/90-QC-III]

का.आ. 1441.—साधारण श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन नियमावली, 1988 के अधीन मुझको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर दिनांक 25-4-75 के कार्यालय आदेश संख्या 7(15) 73-सामान्य डी-3 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं, ओ पी बिहारी, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, एतद्वारा, स्तम्भ (1) में उल्लिखित नियमों के अनुसरण में जैसा कि स्तम्भ (2) में शक्तियों के प्रयोग के अधिकार विनिर्दिष्ट हैं, स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार के अधिकारियों को आन्ध्र प्रदेश राज्य में घरेलू मंडी के लिए कृषि उपज (श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) के अधीन निर्धारित श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन नियमों तथा श्रेणी अभिधानों के अनुसार कृषि तथा अन्य उत्पादों के श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन के बारे में अधिकार देता हूं।

साधारण श्रेणीकरण चिन्हांकन नियमावली 1988 के नियम का संदर्भ	प्रत्यायुक्त शक्तियां	राज्य के अधिकारी का पदनाम
1	2	3
नियम 3(4)	घरेलू श्रेणीकरण के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु आवेदन प्राप्त करना।	संयुक्त विपणन निदेशकों को उनके अपने अपने क्षेत्राधिकार में।
नियम 3(5)	आवेदक की सदाशयता के सत्यापन तथा परिसरों, प्रयोगशाला, संसाधन एककों के निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा घरेलू श्रेणीकरण के लिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु सिफारिश करना।	राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशालाओं के मुख्य रसायनज्ञों को उनके अपने अपने क्षेत्राधिकार में।

1	2	3
नियम 4	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के बारे में प्राधिकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करना।	संयुक्त विपणन निदेशकों को उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में।
नियम 8(2)	एगमार्क श्रेणीकरण के लिए प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला के अनुमोदन की सिफारिश करना।	–वही–
नियम 12	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के बारे में श्रेणी अभिधान चिन्हों को जारी करना अथवा प्रयोग को रोकना।	–वही–
नियम 14	किसी भी अनुसूचित वस्तु के बारे में सूचना, रिपोर्ट, विवरणी प्राप्त करना।	–वही–
नियम 3(8)(ख)	प्राधिकृत श्रेणीकरण परिसरों का निरीक्षण करना तथा यह पता लगाना कि विकेन्द्रीकरण वस्तुओं का श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन सही रूप में किया गया है।	राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशालाओं के कनिष्ठ रसायनज्ञों, रसायनज्ञों तथा मुख्य रसायनज्ञों को उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में।
नियम 3(8)(ग)	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के प्राधिकृत पैकरों द्वारा रखे गए रिकार्ड की जांच करना।	राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशालाओं के कनिष्ट रसायनज्ञ, रसायनज्ञों तथा मुख्य रसायनज्ञों को उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में।
नियम 3(8)(घ)	श्रेणी अभिधान चिन्ह लगे हुए किसी पैकेज को खोलना तथा निरीक्षण करना तथा किसी भी श्रेणीकृत उपज के नमूने लेना परन्तु सभी नमूनों के लिए संदाय किया जाएगा।	–वही–
नियम 3(8)(ङ)	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के अधीन आने वाली किसी भी श्रेणीकृत वस्तु का श्रेणी अभिधान चिन्ह रद्द करना या उसे हटाना यदि वह विहित श्रेणी विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं है।	राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशालाओं के मुख्य रसायनज्ञों को उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में।

[सं. क्यू. 11011/2/90-क्यू सी 3]

S.O. 1441.—In exercise of the powers conferred on me under the General Grading and Marking Rules, 1988 and in partial modification of this office order No. 7 (15)/73-Gen. D.III dated 25-4-75 on the subject, I, O.P. Behari, Agricultural Marketing Adviser to the Government of India hereby delegate, in pursuance of the rules cited in column (1), authority to exeriee the powers, as specified in column (2), to the officers of the State Government, specified in column (3), in respect of grading and marking of agricultural and other produce in accordance with the grade designations and the Grading and Marking Rules prescribed under the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (I of 1937) for domestic market in the State of Andhra Pradesh.

Reference rule of the GGM Rules 1988	Powers delegated	Designation of the State Officer
1	2	3
Rule 3(4)	To receive the application for grant of certificate of Authorisation for domestic grading.	Joint Directors Marketing in their respective jurisdiction.
Rule 3(5)	To arange for verification of bonafides of the applicant and inspection of the premises laboratory, processing units and to recommend grant of C.A. for domestic grading;	Chief Chemist of State Grading Laboratories in their respective jurisdiction.
Rule 4	To renew the certificate of Authorisation in respect of de-centralised grading;	Joint Directors Marketing in their respective jurisdiction.

1	2	3
Rule 8(2)	To recommend approval of private commercial laboratory for Agmark grading;	Joint Directors Marketing in their respective jurisdiction
Rule 12	To with hold issue or use of grade designation marks in respect of de-centralised grading;	-do-
Rule 14	To obtain information, report return in respct of any of the Scheduled articles;	-do-
Rule 3(8)(b)	To inspect the authorised grading premises and to ascertain that grading and marking of de-centralised commodities is correctly performed.	Junior chemists, chemist s and chief chemists of the State Grading Laboratories in their respective jurisdiction.
Rule 3(8)(c)	To examine the record maintained by the authorised packers of de-centralised grading;	-do-
Rule 3(8)(d)	To open and inspect any package bearing grade designation mark and to take samples of any graded produce provided all samples shall be paid for.	-do-
Rule 3(8)(e)	To cancel or to remove the grade designation mark from any graded article covered under decentralisd grading if found not conforming to the prescribed grade specifications.	Chief chemists of the State Grading Laboratories in their respective jurisdiction.

[No. Q. 11011/2/90-QC-III]

का.आ. 1442—साधारण श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन नियमावली, 1988 के अधीन मुझको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर दिनांक 25-4-75 के कार्यालय आदेश सं. 7(15) 73-सामान्य डी-3 में आंशिक संशोधन करते हुए, मैं, ओ.पी. बिहारी, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार एतद्वारा स्तम्भ (1) में उल्लिखित नियमों के अनुसरण में जैसा कि स्तम्भ (2) में शक्तियों के प्रयोग के अधिकार विनिर्दिष्ट हैं, स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार के अधिकारियों को उत्तर प्रदेश राज्य में घरेलू मंडी के लिए कृषि उपज (श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) के अधीन निर्धारित श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन नियमों तथा श्रेणी अभियानों के अनुसार कृषि तथा अन्य उत्पादों के श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन के बारे में अधिकार देता हूं।

साधारण श्रेणीकरण चिन्हांकन नियमावली 1988 के नियम का संदर्भ।	प्रत्यायुक्त शक्तियां	राज्य के अधिकारी का पदनाम
1	2	3
नियम 3(4)	घरेलू श्रेणीकरण के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु आवेदन प्राप्त करना।	राज्य कृषि विपणन अधिकारी, लखनऊ, उ.प्र.
नियम 3(5)	आवेदक की सक्षमता के सत्यापन तथा परिसरों, प्रयोगशाला, संसाधन एककों के निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा घरेलू श्रेणीकरण के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु सिफारिश करना।	सहायक कृषि विपणन अधिकारियों को उनके अपने अपने क्षेत्राधिकार में।
नियम 4	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के बारे में प्राधिकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करना।	राज्य कृषि विपणन अधिकारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
नियम 8(2)	एगमार्क श्रेणीकरण के लिए प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला के अनुमोदन की सिफारिश करना।	—वही—
नियम 12	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के बारे में श्रेणी अभिधान चिन्हों को जारी करना अथवा प्रयोग को रोकना।	—वही—
नियम 14	किसी भी अनुसूचित वस्तु के बारे में सूचना, रिपोर्ट, विवरणी प्राप्त करना।	—वही—

1	2	3
नियम 3(8)(ख)	प्राधिकृत श्रेणीकरण परिसरों का निरीक्षण करना तथा यह पता लगाना कि विकेन्द्रीकरण वस्तुओं का श्रेणीकरण तथा चिह्नांकन सही रूप में किया गया है।	सहायक कृषि विपणन अधिकारियों को उनके अपने अपने क्षेत्राधिकार में।
नियम 3(8)(ग)	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के प्राधिकृत पैकरों द्वारा रखे गए रिकार्ड की जांच करना।	—वही—
नियम 3(8)(घ)	श्रेणी अभिधान चिन्ह लगे हुए किसी पैकेज को खोलना तथा निरीक्षण करना तथा किसी भी सेवाकृत उपज के नमूने लेना परन्तु सभी नमूनों के लिए संवाय किया जाएगा।	—वही—
नियम 3(8)(ङ)	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के अधीन आने वाली किसी भी श्रेणीकृत वस्तु का श्रेणी अभिधान चिन्ह रद्द करना या उसे हटाना यदि वह विहित श्रेणी विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं है।	—वही—

[सं. क्यू-11011/2/90-क्यू सी-3]

S.O. 1442—In exercise of the powers conferred on me under the General Grading and Marking Rules, 1988 and in partial modification of this office order No. 7(15)/73-Gen. D-III dated 25-4-75 on the subject, I, O.P. Behari, Agricultural Marketing Adviser to the Government of India hereby delegate, in pursuance of the rules cited in column (1), authority to exercise the powers, as specified in column (2), to the officers of the State Government, specified in column (3), in respect of grading and making of agricultural and other produce in accordance with the grade designations and the Grading and Marking Rules prescribed under the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (I of 1937) for domestic market in the state of UTTAR PRADESH.

Reference rule of the GGM Rules 1988	Powers delegated	Designation of the state officer
1	2	3
Rule 3(4)	To receive the application for grant of Certificate of Authorisation for domestic grading.	State Agricultural Marketing Officer Lucknow, U.P.
Rule 3(5)	To arrange for verification of bonafides of the applicant and inspection of the premises Laboratory, processing units and to recommend grant of C.A. for domestic grading.	Assistant Agricultural Marketing Officers in their respective jurisdiction.
Rule 4	To renew the certificate of Authorisation in respect of de-centralised grading;	State Agricultural Marketing Officer Lucknow, U.P.
Rule 8(2)	To recommend approval of private commercial laboratory for Agmark grading	-do- -do-
Rule 12	To with hold issue or use of grade designation marks in respect of de-centralised grading;	-do-
Rule 14	To obtain information, report return in respect of any of the Scheduled articles;	-do-
Rule 3(8)(b)	To inspect the authorised grading premises and to ascertain that grading and marking of de-centralised commodities is correctly performed;	Assistant Agricultural Marketing officers in their respective jurisdiction.

1	2	3
Rule 3(8)(c)	To examine the record maintained by the authorised packers of de-centralised grading;	Asstt. Agricultural Marketing officers in their respective jurisdiction.
Rule 3(8)(d)	To open and inspect any package bearing grade designation mark and to take samples of any graded produce provided all samples shall be paid for.	-do-
Rule 3(8)(e)	To cancel or to remove the grade designation mark from any graded article covered under decentralised grading if found not conforming to the prescribed grade specifications.	-do-

[No. Q/11011/2/90-QC-III]

का.आ. 1443.—साधारण श्रेणीकरण तथा चिह्नांकन नियमावली, 1988 के अधीन मुझको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर दिनांक 25-4-75 के कार्यालय आदेश सं.-7(15)/73-सामान्य डी.-3 में आंशिक संशोधन करते हुए, मैं, ओ. पी. बिहारी, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, एतद्द्वारा, स्तम्भ (1) में उल्लिखित नियमों में अनुसरण में जैसा कि स्तम्भ (2) में शक्तियों के प्रयोग के अधिकार विनिर्दिष्ट है, स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार के अधिकारियों को पंजाब राज्य में घरेलू मंडी के लिए कृषि उपज (श्रेणीकरण तथा चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) के अधीन निर्धारित श्रेणीकरण तथा चिह्नांकन नियमों तथा श्रेणी अभिधानों के अनुसार कृषि तथा अन्य उत्पादों के श्रेणीकरण तथा चिह्नांकन के बारे में अधिकार देता हूं।

सामान्य श्रेणीकरण चिन्हांकन नियमावली 1988 के नियम का संदर्भ	प्रत्यायोजित शक्तियां	राज्य के अधिकारी का पदनाम
1	2	3
नियम 3 (4)	घरेलू श्रेणीकरण के लिए प्राधिकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु (आवेदन प्राप्त करना)	निदेशक विपणन, पंजाब ।
नियम 3 (5)	आवेदक की सदाशयता के सत्यापन तथा परिसरों, प्रयोगशाला, संसाधन एककों के निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा घरेलू श्रेणीकरण के लिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु सिफारिश करना।	कृषि निरीक्षक विपणन अपने अपने क्षेत्राधिकार में
नियम 4	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के बारे में प्राधिकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करना।	निदेशक विपणन, पंजाब ।
नियम 8 (2)	एगमार्क श्रेणीकरण के लिए प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला के अनुमोदन की सिफारिश करना ।	--वही--
नियम 12	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के बारे में श्रेणी अभिधान चिन्हों को जारी करना। अथवा प्रयोग को रोकना	--वही--
नियम 14	किसी भी अनुसूचित वस्तु के बारे में सूचना रिपोर्ट, विवरणी प्राप्त करना	--वही--
नियम 3 (8) (ख)	प्राधिकृत श्रेणीकरण परिसरों का निरीक्षण करना तथा यह पता लगाना कि विकेन्द्रीकरण वस्तुओं का श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन सहीरूप में किया गया है ।	सहायक कृषि विपणन अधिकारी अपने अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में।
नियम 3(8)(ग)	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के प्राधिकृत पैकरों द्वारा रखे गए रिकार्ड की जांच करना।	कृषि विभाग के सहायक विपणन अधिकारियों का उनके अपने-अपने जिलों में।
नियम 3(8)(घ)	श्रेणी अभिधान चिह्न लगे हुए किसी पैकेज को खोलना तथा निरीक्षण करना तथा किसी भी श्रेणीकृत उपज के नमूने लेना परन्तु सभी नमूनों के लिए संदाय किया जाएगा।	-वही-
नियम 3(8)(ङ)	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के अधीन आने वाली किसी भी श्रेणीकृत वस्तु का श्रेणी अभिधान चिह्न रद्द करना या उसे हटाना यदि वह विहित श्रेणी विनिर्देशनों के अनरूप नहीं है।	--वही--

[सं. क्यू 11011/2/90-क्यू. सी-3]

S.O. 1443—In exercise of the powers conferred on me under the General Grading and Marking Rules, 1988 and in partial modification of this office Order No. 7 (15)/73-Gen. D-III dated 25-4-1975 on the subject, I, O.P. Behari, Agricultural Marketing Adviser to the Government of India hereby delegate in pursuance of the rules cited in column (1), authority to exercise the powers, as specified in column (2) to the officers of the State Government, specified in column (3), in respect of grading and marking of agricultural and other produce in accordance with the grade designations and the Grading and Marking Rules prescribed under the Agicultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937(I of 1937) for domestic market in the State of UTTAR PRADESH.

Reference rule of the GGM Rules 1988	Powers delegated	Designation of the State Officer
1	2	3
Rule 3 (4)	To receive the application for grant of Certificate of Authorisation for domestic grading.	Director of Marketing Punjab
Rule 3 (5)	To arrange for verification of bonafides of the applicant and inspection of the premises Laboratory, processing units and to recommend grant of C.A. for domestic grading.	Agricultural Inspectors (marketing) in their respective jurisdiction.
Rule 4	To renew the certificate of Authorisation in respect of decentralised grading;	Director of Marketing Punjab
Rule 8 (2)	To recommend approval of private commercial laboratory for Agmark grading.	-do-
Rule 12	To withhold issue or use of grade designation marks in respect of decentralised grading	-do-
Rule 14	To obtain information, report return in respect of any of the Scheduled articles;	-do-
Rule 3(8)(b)	To inspect the authorised grading premises and to ascertain that grading and marking of decentralised commodities is correctly performed;	Assistant Marketing Officers, Deptt. of Agriculture in their respective districts.
Rule 3(8)(c)	To examine the record maintained by the authorised packers of decentralised grading;	-do-
Rule 3(8)(d)	To open and inspect any package bearing grade designation mark and to take samples of any graded produce provided all samples shall be paid for.	-do-
Rule 3(8)(e)	To cancel or to revmove the grade designation mark from any graded article covered under decentralised grading if found not conforming to the prescribed grade specifications.	Assistant Marketing Officers, Department of Agriculture in their respective districts.

[No. Q-11011/2 90-QC-III]

का. आ. 1444 .—साधारण श्रेणीकरण तथा चिह्नांकन नियमावली, 1988 के अधीन मुझको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर दिनांक 25-4-75 के कार्यालय आदेश सं.7(15) 73-सामान्य डी.-3 में आंशिक शोधन करते हुए मैं, ओ. पी. बिहारी, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार एतद्द्वारा स्तम्भ (1) में उल्लिखित नियमों के अनुसरण में जैसा कि स्तम्भ (2) में शक्तियों के प्रयोग के अधिकार विनिर्दिष्ट हैं, स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट, राज्य सरकार के अधिकारियों को बिहार राज्य में घरेलू मंडी के लिए कृषि उपज (श्रेणीकरण तथा चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) के अधीन निर्धारित श्रेणीकरण तथ चिह्नांकन नियमों तथा श्रेणी अभिधानों के अनुसार कृषि तथा अन्य उत्पादों के श्रेणीकरण तथा चिह्नांकन के बारे में प्राधिकार देता है।

साधारण श्रेणीकरण चिह्नांकन नियमावली, 1988 के नियम का संदर्भ	प्रत्यायुक्त शक्तियां	राज्य के अधिकारी का पदनाम
1	2	3
नियम 3(4)	घरेलू श्रेणीकरण के लिए प्राधिकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन प्राप्त करना।	विपणन निदेशक, बिहार, राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
नियम 3(5)	आवेदक की सक्षमता के सत्यापन तथा परिसरों प्रयोगशाला, संसाधन एककों के निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा घरेलू श्रेणीकरण के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु सिफारिश करना ।	राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशालाओं के प्रभारी के अधिकारियों रसायनज्ञ प्रभारियों को उन अपने-अपने क्षेत्राधिकार में।
नियम 4	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के बारे में प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण करना।	विपणन निदेशक बिहार राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
नियम 8(2)	एगमार्क श्रेणीकरण के लिए प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला के अनुमोदन की सिफारिश करना।	—वही—
नियम 12	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के बारे में श्रेणी अभिधान चिह्नों का जारी करना अथवा प्रयोग को रोकना।	—वही—
नियम 14	किसी भी अनुसूचित वस्तु के बारे में सूचना, रिपोर्ट, विवरणी प्राप्त करना।	—वही—
नियम 3(8)(ख)	प्राधिकृत श्रेणीकरण परिसरों का निरीक्षण करना तथा यह पता लगाना कि विकेन्द्रीकरण वस्तुओं का श्रेणीकरण तथा चिह्नांकन सही रूप में किया गया है।	प्रमुख श्रेणीकरण एवं मानकीकरण बिहार राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशालाओं के रसायनज्ञ प्रभारियों को उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में।
नियम 3(3)(ग)	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के प्राधिकृत पैकरों द्वारा रखे गए रिकार्ड की जांच करना।	प्रमुख श्रेणीकरण एवं मानकीकरण, बिहार राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशालाओं के रसायनज्ञ प्रभारियों को उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में।
नियम 3(8)(घ)	श्रेणी अभिधान चिह्न लगे हुए किसी पैकेज का खोलना तथा निरीक्षण करना तथा किसी भी श्रेणीकृत उपज के नमूने लेना परन्तु सभी नमूनों के लिए संदाय किया जाएगा।	—वही—
नियम 3(8)(ङ)	विकेन्द्रीकरण श्रेणीकरण के अधीन आने वाली किसी भी श्रेणीकृत वस्तु का श्रेणी अभिधान चिह्न रद्द करना या उसे हटाना यदि वह विहित श्रेणी विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं है।	—वही—

[सं. क्यू.-11011/2/90-क्यू-सी-3]

ओ. पी. बिहारी, कृषि विपणन सलाहकार

S.O. 1444—In exercise of the powers conferred on me under the General Grading and Marking Rules, 1988 and in partial modification of this office order No. 7(15) 73-Gen. D.-III dated 25-4-75 on the subject I, O.P. Behari, Agricultural Marketing Adviser to the Government of India hereby delegate, in pursuance of the rules cited in column (1), authority to exercise the powers, as specified in column (2), to the officers of the State Government, specified in column (3) in respect of grading and marking of agricultural and other produce in accordance with the grade designations and the Grading and Marking Rules pres-

cribed under the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) for domestic market in the state of BIHAR.

Reference rule of the GGM Rules, 1988	Powers delegated	Designation of the State Officer
1	2	3
Rule 3(4)	To receive the application for grant of Certificate of Authorisation for domestic grading;	Director of Marketing Bihar State Agriculture Marketing Board.
Rule 3(5)	To arrange for verification of bonafides of the applicant and inspection of the premises Laboratory, processing units to recommend grant of C.A. for domestic grading;	Officer incharge/Chemist in charge of the State Grading Laboratories in their respective jurisdictions.
Rule 4	To renew the certificate of Autherisation in respect of de-centralised grading;	Director of Marketing Bihar State Agricultural Marketing Board.
Rule 8(2)	To recommended approval of private	-do-
Rule 12	To with hold issue or use of grade designation marks in respect of de-centralised grading;	-do-
Rule 14	To obtain information, report return in respect of any of the Scheduled articles;	-do-
Rule 3(8)(b)	To inspect the authorised grading premises and to ascertain that grading and marking of decentralised commodities is correctly performed;	Chief, Grading and Standardisation BSAMB and chemist in charge of the State Grading Laboratories in their respective jurisdictions.
Rule 3(8)(c)	To examine the record maintained by the authorised packers of decentralised grading;	-do-
Rule 3(8)(d)	To open and ispect any package bearing grade designation mark and to take sample of any graded produce provided all samples shall be paid for;	-do-
Rule 3 8)(e)	To cancel or to remove the grade designation mark from any graded article covered under decentralised grading if found not conforming to the prescribed grade specifications.	Chief, Grading and Standardisation, BSAMB & Chemists Incharge of the State Grading Labs. in their respective jurisdiction.

[No. Q-11011/2/90-QC-III]

O.P. BEHARI, Agricultural Marketing Adviser

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मई, 1991

का.आ. 1445.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में जल संसाधन मंत्रालय के निम्नलिखित दो कार्यालयों को अधिसूचित करती है, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है :—

(1) लेखा नियंत्रक का कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(2) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, सामुदायिक विकास केन्द्र, साकेत, नई दिल्ली।

[सं. 1/1/88-हिन्दी]

अवतार सिंह चौहान, उप सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 7th May, 1991

S.O. 1445.—In pursuance of rule 10(4) of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rules 1976, the Central Government hereby notifies the following two offices of the Ministry of Water Resources where more than 80% staff has acquired working knowledge of Hindi :

1. Office of the Controller of Accounts, Shastri Bhavan, New Delhi.
2. National Water Development Agency, Community Development Centre, Saket, New Delhi.

[No. 1|1|88-Hindi]

AVTAR SINGH CHAUHAN, Dy. Secy.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग)

नई दिल्ली, 3 मई, 1991

का.आ. 1446.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अधीन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून, जिसके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।

[सं. ई.-11011/31/88-का.हि.-II]

उदयराम ध्यानी, उप निदेशक (रा.भा.)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment, Forests and Wildlife)

New Delhi, the 3rd May, 1991

S.O. 1446.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purpose of the Union) Rule, 1976 the Central Government hereby notifies the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun under the administrative control of the Department of Environment, Forests & Wildlife, the staff whereof have acquired a working knowledge of Hindi.

[No. E-11011|31|88 Ka Hindi II]

U. R. DHYANI, Dy. Director (OL)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, 15 मई, 1991

(पुरातत्व)

का.आ. 1447.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि संरक्षित संस्मारकों के समीप और पार्श्वस्थ क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उनसे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन संक्रियाओं और सन्निर्माण के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र घोषित किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त क्षेत्रों को प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है। यह फतेहपुर सीकरी, महाबलिपुरम; गोलकोंडा का किला, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश); हजार स्तंभ मंदिर, हनामकोंडा, जिला वारंगल (आंध्र प्रदेश); शेरशाह का मकबरा, ससराम (बिहार); अशोक की प्रस्तर राजाज्ञा, कोपबल, जिला रायचूर (कर्नाटक); फोर्ट वाल, बीजापुर (कर्नाटक); श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति; जिला हसन, (कर्नाटक), एलिफेंटा की गुफाएं, धरापुरी, जिला कोलाबा (महाराष्ट्र) में स्थित संस्मारकों के संबंध में की गई समरूप घोषणाओं के अतिरिक्त होगी और इससे इन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर उक्त क्षेत्र में हितबद्ध किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आक्षेप पर विचार करेगी। आक्षेप, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजे जा सकेंगे।

[सं० 8/2/90 संस्मा]

एम० सी० जोशी, महानिदेशक

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 15th May, 1991

(ARCHAEOLOGY)

S.O. 1447.—Whereas the Central Government is of the opinion that the areas upto 100 metres from the protected limits and further beyond it upto 200 metres near or adjoining protected monuments be declared to be prohibited and regulated area respectively for purposes of both mining operations and construction;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 31 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, the Central Government hereby given notice of its intention to declare the said areas as prohibited and regulated areas. This shall be in addition to and shall not in any way prejudice the similar declarations made in respect of monuments at Fatehpur Sikri, Mahabalipuram; Golconda Fort, Hyderabad (Andhra Pradesh); Thousand Pillared Temple, Hanamkonda, District Warangal (Andhra Pradesh); Sher Shah's Tomb, Sasaram (Bihar); Rock Edict of Ashoka, Kopbal, District Raichur (Karnataka), Fort Wall Bijapur (Karnataka), Gomatesvara Statue at Sravanbelgola, District Hassan (Karnataka); Elephanta Caves, Gharapuri, District Kolaba (Maharashtra).

Any objection made within one month of this date of issue of this notification by any person interested in the said area will be considered by the Central Government. The objection may be addressed to the Director General, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi-110011.

[No. 8|2|90-M]

M. C. JOSHI, Director General

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1991

का.आ. 1448.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपना आशय की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखांक सं. एस.ई.सी.एल./बी.एस.पी./ए.सी.एम.ई./एल.ई आर./भूमि/80 तारीख 10 नवम्बर, 1990 का निरीक्षण साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (राजस्व अनुभाग) सीपत रोड, बिलासपुर (मध्य प्रदेश)-495001 के कार्यालय में या कलक्टर सरगुजा (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, उप मुख्य संपदा प्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., सीपत रोड, बिलासपुर को भेजेंगे ।

अनुसूची

पश्चिम चिरीमिरी कोलियरी का उत्तर ब्लाक

चिरीमिरी क्षेत्र

(जिला सरगुजा (मध्य प्रदेश)

प्लान सं. एस.ई.सी.एल./बी.एस.पी./ए.सी.एम.ई.एल.ई.आर. भूमि/80 तारीख 10 नवम्बर, 1990

(पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शाते हुए)

राजस्व भूमि

क्र. सं.	ग्राम	पटवारी हल्का सं	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणी
1.	चितझोर	16	बैकुंठपुर	सरगुजा	11.39	भाग
2.	सरभोका	17	मानेन्द्रगढ़	सरगुजा	19.06	भाग
				कुल	30.45 हैक्टर	

वन भूमि

क्र. सं.	कम्पार्टमेंट सं.	रेंज	प्रभाग	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणी
1	536 (भाग), 538 (भाग),	सुरसिया	कोरिया	142.53	भाग

कुल योग : 172.98 हैक्टर

लगभग या

427.43 एकड़

(लगभग)

सीमा वर्णन :

क-ख रेखा सरभोका ग्राम में "क" बिन्दु से आरंभ होती है और सरभोका वन कम्पार्टमेंट सं. 538, 536 से होकर गुजरती है और "ख" बिन्दु पर मिलती है ।

ख-ग-घ रेखा चितझोर ग्राम में वन कम्पार्टमेंट सं 536 538 से गुजरती है और "घ" बिन्दु पर मिलती ।

घ-क रेखा ग्राम चितझोर, सरभोका ग्राम से गुजरती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[फा सं. 43015/23/90—एस एम डब्ल्यू]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 19th April, 1991

S.O. 1448—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan bearing No. SECL/BSP/ACME/LER/LAND/80 dated the 10th November, 1990 of the area covered by this notification can be inspected at the Office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495001, District Bilaspur (Madhya Pradesh) or at the Office of the Collector, Surguja (Madhya Pradesh) or at the office of the Coal Controller, 1 Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Deputy Chief Estate Manager, South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur, District Bilaspur (Madhya Pradesh) within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

NORTH BLOCK OF WEST CHIRIMIRI COLLIERY CHIRIMIRI AREA

DISTRICT-SURGUJA (MADHYA PRADESH)

Plan No. SECL/BSP/ACME/LER/LAND/80

dated 10th November, 1990

(Showing the land notified for prospecting).

Revenue Land

Sl. No.	Village	Patwari Halka Number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Chitajhore	16	Baikunthpur	Surguja	11.39	part
2.	Sarbhoka	07	Manendragarh	Surguja	19.06	part
				Total:-	30.45	hectares

Forest Land

Sl. No.	Compartment Number	Range	Division	Area in hectares	Remarks
1.	536 (part) 538 (part).	Khurasia	Korea	142.53	part
				Total :- 142.53	
			Grand Total:-	172.98 hectares (approximately) OR 427.93 acres (approximately)	

Boundary D scription :-

A—B Line starts from point 'A' in village saronoka and passes through village Sarbhoka forest compartment Nos. 538, 536 and meets at point 'B'.

B—C—D Line passes through forest compartment Nos. 536, 538, Chitajhore village and meets at point 'D'.

D—A Line passes through villages Chitajhore, Sarbohoka and meets at the starting point 'A'.

[No. 43015/23/90-LSW]

नई दिल्ली, 8 मई, 1991

का.आ. 1449 :—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7, उपधारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) पृष्ठ संख्यांक 64 से 67 में प्रकाशित भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना का.आ. 88 तारीख 20 दिसम्बर, 1990 द्वारा इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का अधिग्रहण के अपने आशय की सूचना दी थी।

और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई कि राजपत्र में प्रकाशित उपरोक्त अधिसूचना में मुद्रणमुद्रण की कुछ गलतियां हैं।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

पृष्ठ क्रमांक 65 पर :—स्पष्टीकरण में,

पंक्ति 1 में—"करनी" के स्थान पर "करना" पढ़ें।

अनसूची में, क्षेत्र (हैक्टेयर) स्तंभ के नीचे।

क्रम संख्या 3,········"130.016" के स्थान पर "180.016" पढ़ें।—पृष्ठ क्रमांक 67 पर : —सीमा वर्णन में,

रेखा—ई-ई 1-ई-2-च के स्थान पर "ड. ई-1-ई-2-च" पढ़ें।

रेखा ड. ई 1-ई 2-च में,

पंक्ति 2 में—"234" के स्थान पर "231" पढ़ें।

रेखा—च-छ में,

पंक्ति 2 में—"कम्पार्टमेंट संख्या" के स्थान पर "कम्पार्टमेंट" पढ़ें।

रेखा छ-क में,

पंक्ति 8 में—"1146" के स्थान पर "1445" पढ़ें।

ऐसी भूमि में, जिसकी बाबत उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है, हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर उक्त भूमि के संपूर्ण या किसी भाग के, या उक्त ऐसी भूमि में या उस पर किसी अधिकार के अर्जित किए जाने के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के निबन्धनों के अनुसार आक्षेप कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :— केवल इस अधिसूचना के द्वारा संशोधित प्लाट संख्याओं की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 8(1) के निबन्धनों के अनुसार तीस दिन की उक्त अवधि यह अधिसूचना जारी की जाने की तारीख से प्रारंभ होगी।

[फा.सं. 43015/9/90—एल.एस.डब्ल्यू.]

New Delhi, the 8th May, 1991

S.O. 1449.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Depaitment of Coal) No. S.O. 88, dated the 20th December, 1990, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands described in the Schedule appended to that notification;

And whereas, it has been brought to the notice of the Central Government that certain errors of printing nature have occured in the publication of the said notification in the Official Gazette;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act the Central Government hereby amends the Schedule appended to the said notification as follows :—

at page 68, in the Schedule in column 9 General numbe against Sl. No. 5 for "55" read "455", in column Grant total for "1170.585" read "1177.585";

at page 69 in plot nnumbers to be acquired in village Dhanpuri (part) in line for "1400 (P) read "1447 (P)",

in line 2 for "1487 (P). 1480 (P) 1488 (P) read "1487 (P) 1488 (P)";

in line 3 for "1953 (P)" read "1533 (P) and for "1569 to 1505" read "1569 to 1575";

in line 4 "17 6(P)", read "1726 (P) and for "1735 to 1042" read "1735 to 1742";

in line 5 for "1743 (P)" read "1747 (P)" and for "1961 to 1971" read "1967 to 1971";

in plot numbers to be acquired in village Karkati (part),

in line 1, for "274 to 304" read "294 to 304" and for "300 (P)" read "309 (P)";

in line 2, for "440 (P)" read "447(P)";

in line 3, for "500(P) read "507(P)";

in plot number to be acquired in village Bimhori (part),

in line 3, for "509(P)" read "549(P)";

in Boundary Description, in A-B, in line 3 for "1780" read 1787";

in F-G in line 4 for "350" read "359" and for "203" read "293";

in G-A, in line 1, for "575" read "505";

in line 3, for "757" read "759";

in line 4, for "1724, 1726, 1726" read "1724, 1727, 1726",

in line 5, for "1033" read "1733" and for "1407, 1483" read "1487, 1493".

Any person interested in any land in respect of which the above amendment has been issued, may within thirty days of the issue of this notification, object to the acquisition of the whole or any part of the said land, or any right in or over such land in terms of sub-section (1) of section 8 of the said Act;

The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

Explanation.—In respect of plot numbers amended through this notification only, the said period of thirty days in terms of section 8(1) of the said Act starts running from the date of issue of this notification.

[No. 43015/9/90-ISW)

नई दिल्ली, 14 मई, 1991

शुद्धि पत्र

का.आ. 1450.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 30 दिसम्बर, 1989 के पृष्ठ क्रमांक 3958-3959 पर प्रकाशित भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग की अधिसूचना का आ. सं. 3238 तारीख 3 दिसम्बर, 1989 में—

पृष्ठ क्र० 3958 पर अधिसूचना में

पंक्ति 3 में : "देन" के स्थान पर "देती" पढ़ें।

पंक्ति 4 में : "(प रयोजना)" के स्थान पर "(परियोजना)" पढ़ें

पंक्ति 7 में : "13 का" के स्थान पर "13 की" पढ़ें।

पृष्ठ क्र. 3959 पर सीमा वर्णन में

रेखा क–ख "होकर गजरती" के स्थान पर "से होकर गुजरती" पढ़ें।

रेखा ग–क "वन प्रखंड" के स्थान पर "वन प्रकोष्ठ" पढ़ें।

[फा.सं. 43015/18/89-एल एस डब्ल्यू]

बी.बी. राव, अवर सचिव

नई दिल्ली, 14 मई, 1991

का.आ. 1451.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई और भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 17 जून, 1989 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1372, तारीख 15 मई, 1989 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 1185.00 हैक्टर (लगभग) या 2928.25 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने के आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त भूमि की बाबत, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के आशय की सूचना नहीं दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक वर्ष की ऐसी और अतिरिक्त अवधि को, 17 जून, 1991 को प्रारम्भ होगी, ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें केन्द्रीय सरकार उक्त उपधारा के अधीन सूचना दे सकेगी।

[फा.सं. 43015/1/89-एल.एस.डब्ल्यू.]

New Delhi, the 14th May, 1991

S.O. 1451.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) number S.O. 1372, dated the 15th May, 1989 issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), and published in part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 17th June, 1989, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 1185.00 hectares (approximately) or 2928.25 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended thereto;

And whereas in respect of the said lands, no notice of the Central Government's intention to acquire the whole or any part of the said land or of any rights in or over such land under sub-section (1) of section 7 of the said Act has been given;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section (1), the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing on the 17th June, 1991 as the period within which the Central Government may give notice under the said sub-section.

[No. 43015/1/89-LSW]

नई दिल्ली, 15 मई, 1991

शुद्धिपत्र

का.आ. 1452.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 29-9-1990 के पृष्ठ 4320-4321 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं.का.आ. 2550, तारीख 12-9-90 में—

पृष्ठ 4321 पर—

अनुसूची में—"क्षेत्र हैक्टरों में स्तम्भ में क्रम संख्या 1 में—

"129.43 भाग" के स्थान पर "129.48 भाग" पढ़ें।

[फा.सं. 43015/1/90-एलएस डब्ल्यू]

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 15 मई, 1991

अधिसूचना

का.आ. 1453—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई और भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 4 जून, 1988 में पृष्ठ 2193 से 2195 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 1696, तारीख 11 मई, 1988 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की 4485.08 हेक्टर (लगभग) या 11082.86 एकड़ (लगभग) भूमि में, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 30 मई, 1990 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 418(अ), तारीख 30 मई 1990 द्वारा 4 जून 1990 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट किया था, जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमियों या ऐसी भूमियों में या उन पर किन्हीं अधिकारों के अर्जन के अपने आशय की सूचना दे सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्त है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए;

(क) इस संलग्न अनुसूची "क" और "क1" में वर्णित 1050.84 हेक्टर (लगभग) या 2596.63 एकड़ (लगभग) माप की भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों का;

(ख) इससे संलग्न अनुसूची "ख" में वर्णित भूमि में, 26.27 हेक्टर (लगभग) अथवा 64.91 एकड़ (लगभग) माप की भूमि में खनिजों के खनन, खदान, और करने, उनका खुदाई करने और तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का;

अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है।

टिप्पण 1: इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सी-1(ई) III एफ. आर. 463-0490 तारीख 10 अप्रैल, 1990 का निरीक्षण कलक्टर, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (राजस्व विभाग), कोयला एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर-1 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण 2: पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं:

8. अर्जन के प्रति आपत्तियां—

(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता का स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।

टिप्पण :—3 भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का. आ. सं. 2519, तारीख 11 जून 1983 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना सं. 19/41/78; सी.एल. तारीख 27 मई, 1983 द्वारा कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता को अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची "क"

मकरधोकरा ब्लाक

नागपुर क्षेत्र

जिला नागपुर (महाराष्ट्र राज्य)

सभी अधिकार

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टरों में	टिप्पणी
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मकरधोकरा	17	उमरेर	नागपुर	270.15	भाग
2.	बोपेश्वर	17	उमरेर	नागपुर	151.45	भाग
3.	गनपावली	22	उमरेर	नागपुर	28.68	भाग
4.	कटरा	22	उमरेर	नागपुर	53.67	भाग
				अनुसूची "क" का कुल क्षेत्र	503 हैक्टर (लगभग)	या (1245.26) एकड़ लगभग

ग्राम मकरधोकरा में अर्जित जाने वाले प्लाट संख्यांक :— 70 से 83, 116 से 119, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 137 से 141, 145 से 155, 161 से 165, 166/1, 166/2, 166/3, 167 से 171, 172/1, 172/2, 173 से 175, 185, 192, 193 (भाग), 195 से 203, 204/1, 204/2, 205 से 223, 243 से 257, 315 से 317, 322 से 339, 342, 544, 559, 574, 581, 588, 589, 591 से 594, 596/1, 596/2, 597, 598, 601 से 610, सड़क भाग और नाला भाग।

ग्राम बोपेश्वर में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 17 से 19, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 22, 63 से 68, 69/1, 69/2, 70 से 73, 78 से 84, 85/1, 85/2, 86 से 90, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 92, 93 भाग, 94 भाग, 97/1, 92/2, 97/3, 97/4, 98/1, 98/2, 98/3, 99 से 101, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 106 से 110, 111/1, 111/2, 112, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 117 से 124, सड़क भाग, नाला भाग ।

ग्राम गनपावली में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :—

26, 27/1, 27/2, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/2, 40 से 49, सड़क भाग।

ग्राम कटारा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

6, 7, 8/1, 8/2, 9 से 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 14 से 33, 132, सड़क भाग।

सीमा वर्णन:—

क—ट:— रेखा, बिन्दु "क" से आरम्भ होती है और ग्राम मकरधोकरा से गुजरते हुए रेल लाइन क्रॉसिंग रोड़ और नाला की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ट" पर मिलती है।

ट—ठ:— रेखा, प्लाट संख्यांक 78, 83 की बाहरी सीमा के साथ-साथ चलकर ग्राम मकरधोकरा से गुजरती है, नाला पार करती है और बिन्दु "ठ" पर मिलती है।

ठ—ड:— रेखा, प्लाट संख्यांक 82, 589, 588, 591, 592, 81 की बाहरी सीमा के साथ-साथ चलकर ग्राम मकरधोकरा से होकर जाती है, सड़क पार करती है, प्लाट संख्यांक 116, 141 की बाहरी सीमा के साथ-साथ जाती है, सड़क पार करती है, प्लाट संख्यांक 603, 145 146, 147, 174, 175, के साथ-साथ जाती है, नाला पार करती है, फिर प्लाट संख्यांक 192, 172/2, 173 की बाहरी सीमा के साथ-साथ, प्लाट संख्यांक 193 में जाती है, सड़क पार करती है, प्लाट संख्यांक 185, 559, 223, 222, 243, 244, 257, की बाहरी सीमा के साथ-साथ जाती है, सड़क पार करती है, प्लाट संख्यांक 315, 317, 322, 323 की बाहरी सीमा के साथ-साथ जाती है और ग्राम मकरधोकरा और बोपेश्वर की सम्मिलित ग्राम सीमा पर बिन्दु "ड" पर मिलती है।

ड—ढ:— रेखा, प्लाट संख्यांक 100, 97/4, 97/2, 97/1, 97/3, 98/1, की बाहरी सीमा के साथ-साथ ग्राम बोपेश्वर से होकर प्लाट संख्यांक 93, 94 जाती है, प्लाट संख्यांक 17, 22, 84, 83, 78, 73, 71, 70, 69/1, 63 की बाहरी सीमा के साथ-साथ जाती है, फिर प्लाट संख्यांक 26, 27/1, 27/2 की बाहरी सीमा के साथ-साथ चलकर ग्राम गनपावली से होकर जाती है और बिन्दु "ढ" पर मिलती है।

ढ—ण:— रेखा, प्लाट संख्यांक 27/1, 27/2, 29/1, 39/2, 30, 37/1, 37/2, 46 की बाहरी सीमा के साथ साथ चलकर ग्राम गनपावली से से होकर जाती है और बिन्दु "ण" पर मिलती मिलती है।

ण—त—क :— रेखा, रेलवे लाइन की उत्तरी सीमा सीमा के साथ-साथ चलते हुए ग्राम गनपावली, कटरा, बोपेश्वर, मकरधोकरा से होकर जाती है और बिन्दु "क" पर मिलती है ।

अनुसूची "क 1"

मकरधोकरा ब्लाक

नागपुर क्षेत्र

जिला नागपुर (महाराष्ट्र राज्य)

सभी अधिकार :—

क्रम सं	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टरों में	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मकरधोकरा	17	उमरेर	नागपुर	37.24	भाग
2.	बोपेश्वर	17	उमरेर	नागपुर	3.88	भाग
3.	गनपावली	22	उमरेर	नागपुर	5.29	भाग
4.	कटरा	22	उमरेर	नागपुर	259.14	भाग
5.	सीरपुर	22	उमरेर	नागपुर	144.87	भाग
6.	कन्हाना	22	उमरेर	नागपुर	96.48	भाग

अनुसूची "क1"

का कुल क्षेत्र 546.89 हैक्टर (लगभग)

या 1351.37 एकड़ (लगभग)

अनुसूची "क" + "क1" के सभी अधिकार-क्षेत्र

का कुल योग :—503.95 + 546.89 = 1050.84 हैक्टर (लगभग)

या 1245.26 + 1351.37 = 2590.63 एकड़ (लगभग)

ग्राम मकरधोकरा में अर्जित किये जाने वाले प्लाट संख्यांक :—

160, 340, 341, 343 से 347, 377 भाग, 572, 578, सड़क भाग

ग्राम बोमेश्वर में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :
125 से 129

ग्राम गनपावली में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :—
51 से 55

ग्राम कटारा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

1, 2/1, 2/2, 3,4,34 से 41, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 43/2, 44 से 112, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 116, 117, 130, 133, से 143 सड़क भाग नाला।

ग्राम सीरपुर में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :— 6 से 22, 25, 26, 39से 80, 81/1, 81/2,81/3, 82, से 93, 94/1, 94/2, 95, 116 से 118, 122 से 128, 129/1, 129/2, 129/3, 130, सड़क भाग, नाला भाग।

ग्राम कन्हुवा में अर्जित किए जने वाले प्लाट संख्यांक :—

90 से 116, 120 से 122, 123 भाग, 124 भाग, 134, 135 भाग, सड़क भाग, नाला भाग।

सीमा वर्णन :—

क—ख— रेखा, बिन्दु "क" से प्रारंभ होती है और रेल लाइन पर दक्षिणी रेखा के साथ साथ चलता हुई ग्राम मकरधोकरा, बोमेश्वर कटारा, गनपावली और कन्हुवा से गुजरती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख—ख1-ग-घ—रेखा 1 रेल लाइन की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ चलती हुई ग्राम कन्हुवा से होकर जाती है, फिर सड़क की बाहरी सीमा, प्लाट संख्यांक 134, प्लाट संख्यांक 135, 124 के साथ साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है)

घ—ङ:— रेखा, प्लाट संख्यांक 122 की बाहरी सीमा के साथ-साथ चलकर प्लाट संख्यांक 124, 123 में ग्राम कन्हुवा से होकर जाती है, सड़क पार करती है और सड़क की बाहरी सीमा के साथ साथ चलते हुए, प्लाट संख्यांक 114, 110 से जाती है और बिन्दु "ङ" पर मिलती है।

ङ—च:—रेखा, ग्राम कन्हुवा से होकर जाती है और प्लाट संख्यांक 110, 115, 114, सड़क 113, 90 की बाहरी सीमा के साथ-साथ जाती है, नाला पार करती है, फिर प्लाट संख्यांक 95 की बाहरी सीमा के साथ-साथ ग्राम सीरपुर से होकर जाती है, सड़क पार करती है और बिन्दु "च" पर मिलती है।

च—छ.— रेखा, सड़क प्लाट संख्यांक 116, 118, 122 129/1=129/2, 129/3, 130 की बाहरी सीमा के साथ-साथ ग्राम सीरपुर से होकर जाती है और बिन्दु "छ" पर मिलती है।

छ—ज.— रेखा, प्लाट संख्यांक 130, 6 की बाहरी सीमा के साथ-साथ ग्राम सीरपुर से होकर जाती है, सड़क पार करती है, प्लाट संख्यांक 14 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 47, 46, 40 की बाहरी सीमा के साथ साथ जाती है, प्लाट संख्यांक 39 की बाहरी सीमा के साथ साथ नाला पार करती है, फिर ग्राम सीरपुर और कटारा की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ज" पर मिलती है।

ज—झ.— रेखा, प्लाट संख्यांक 110, 113/1—113/2, 113/3, 113 ए/4, 116, 117, 38 की बाहरी सीमा के साथ साथ ग्राम कटारा से होकर जाती है और बिन्दु "झ" पर मिलती है।

झ—क :—रेखा प्लाट संख्यांक 377 में ग्राम मकरधोकरा से होकर जाती है, सड़क पार करती है, फिर प्लाट संख्यांक 578, 342 345, 244, 160 की बाहरी सीमा के साथ साथ जाती है और प्रारंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

अनुसूची "ख"

मकरधोकरा ब्लाक

नागपुर क्षेत्र

जिला नागपुर (महाराष्ट्र राज्य)

खनन अधिकार

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टरों में	टिप्पणियां
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मकरधोकरा	17	उमरेर	नागपुर	10.50	भाग
2.	बोपेश्वर	17	उमरेर	नागपुर	1.55	भाग
3.	गनपावली	22	उमरेर	नागपुर	5.49	भाग
4.	कटारा	22	उमरेर	नागपुर	8.70	भाग
5.	कन्हवा	22	उमरेर	नागपुर	0.03	भाग

कुल क्षेत्र : 26.27 हैक्टर (लगभग) या 64.9 एकड़ (लगभग)

ग्राम मकरधोकरा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

रेल भाग

ग्राम बोपेश्वर में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

ग्राम गनपावली में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

50

ग्राम कटारा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

5

ग्राम कन्हवा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

203

सीमा वर्णन :

क—ख—रेखा, बिन्दु "क" से आरम्भ होती है और रेल लाइन की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ चलकर ग्राम मकरधोकरा, बोपेश्वर, कटारा, गनपावली और कन्हवा से होकर जाती है और बिंदु "ख" पर मिलती है।

ख—त—रेखा ग्राम कन्हवा और गनपावली की सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है, रेल लाइन पार करती है और बिन्दु "त" पर मिलती है।

त—ण—ध—ञ—रेखा ग्राम गनपावली, कटारा, बोपेश्वर और मकरधोकरा में होकर रेल लाइन की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ङ" पर मिलती है।

ञ—क—रेखा, ग्राम मकरधोकरा में होकर जाती है, रेल लाइन पार करती है और प्रारंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं. 13015/4/88—ओ. एस. डब्ल्यू.]

बी. बी. राव, अवर सचिव

S.O. 1453.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Coal No. S.O. 1696, dated the 11th May, 1988 issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and published in part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 4th June, 1988 at pages 2193 to 2195 the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 4485.08 hectares (approximately) or 11082.86 acres (approximately) of the lands to the locality specified in the Schedule annexed to that notification ;

And whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 418(E) dated the 30th May, 1990 issued under sub-section (1) Gazette of India part II, section 3, sub-section (ii) dated the Gazette of India part II, section 3, sub-section (ii) dated the 30th May, 1990, the Central Government specified a further periods of one year commencing on 4th June, 1990 as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 f the said Act, the Central Gvernment hereby gives notice of its intention to acquire;

(a) the lands measuring 1050.84 hectares (approximately) or 2596.63 acres (approximately) described in Schedule 'A' & 'A1' appended hereto and the rights in or over such land;

(b) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, Win, work and carry away minerals in the lands measuring 26.27 hectares (approximately) or 64.91

aeres (approximately) described in Schedule 'B' appended hereto;

Note—1 : The plan bearing No. C-1(E)/III/FR/463-0490 dated 10th April, 1990 of the areas covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Nagpur (Maharashtra) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-1 (Maharashtra).

Note—2 : Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the aforesaid Act which provides as follows:

Objection to acquisition.—

"8(1)—Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall afer hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land to the Central Government, containing his recommendations on the objections tgether with the record of the proceedings held by him for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in of over such land were acquired under this Act."

Note—3 : The Coal Controller, 1 Council House Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act vide notification No. 19|41|78-CL dated 27th May, 1983 published in part II section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India under S.O. No. 2519 dated 11th June, 1983.

SCHEDULE 'A'

MAKARDHOKRA BLOCK

NAGPUR AREA

DISTRICT NAGPUR (MAHARASTRA STATE)

All Rights

Serial number	Name of village	Patwari circle number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Makardhokra	17	Umrer	Nagpur	270.15	Part
2.	Bopeshwar	17	Umrer	Nagpur	151.45	Part
3.	Ganpawali	22	Umrer	Nagpur	28.68	Part
4.	Katara	22	Umrer	Nagpur	53.67	Part
	Total area of schedule 'A'—				503.95 hectares (approximately) or 1245.26 acres (Approximately)	

Plot numbers to be acquired in village Makardhokra : 70 to 83, 116 to 119, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 137 to 141, 145 to 155, 161 to 165, 166/1, 166/2, 166/3, 167 to 171, 172/1, 172/2, 173 to 175, 185, 192 193 Part, 195 to 203, 204/1, 204/2, 205 to 223, 243 to 257, 315 to 317, 322 to 339, 342, 544, 559, 574 581, 588, 589, 591 to 594, 596/1, 596/2, 597, 598, 601 to 610, roads Part and Nallah Part.

Plot numbers to be acquired in village Ganpawali : 26, 27/1, 27/2, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/2, 40 to 49 Road Part.

Plot numbers to be acquired in village Bopeshwar : 17 to 19 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 22, 63 to 68 69/1, 69/2, 70 to 73, 78 to 84, 85/1, 85/2, 86 to 90, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 92, 93 Part, 94 Part, 97/1, 97/2 97/3, 97/4, 98/1, 98/2, 98/3, 99 to 101, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 106 to 110, 111/1, 111/2, 112, 113/1, 113 , 114/1, 114/2, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 117 to 124, Road Part, Nallah Part.

Plot numbers to be acquired in village Katara : 6, 7, 8/1, 8/2, 9 to 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 14 to 33, 132, Road, part.

Boundary description :

J–K Line starts from point 'J' through village Makardhokra and passes along the northern boundary of railway line crossing road and nallah and meets at point 'K'.

K–L	Line passes through village Makardhokra along the outer boundary of plot numbers 78 83, crosses nallah and meets at point 'L'.
L–M	Line passes through village Makardhokra along the outer boundary of plot numbers 82, 589. 588, 591, 592, 81, crosses road, along the outer boundary of plot numbers 116, 141, crosses road, along the outer boundary of plot numbers 603, 145, 146, 147, 174, 175 crosses nallah, then along the outer boundary of plot numbers 192, 172/2, 173, in plot number 193, crosses road, along the outer boundary of plot numbers 185, 559, 223, 222, 243, 244, 257, crosses road, along the outer boundary of plot numbers 315, 317, 322, 323 and meets on the comon village boundary of villages Makardhokra and Bopeswar at point 'M'.
M–N	Line passes through village Bopeshwar along the outer boundary of plot numbers 100, 97/4, 97/2, 97/1, 97/3, 98/1, in plot numbers 93, 94, along the outer boundary of plot numbers 17, 22, 84, 83, 78, 73, 71, 70, 69/1, 63, then proceeds through village Ganpawali along the outer boundary of plot numbers 26, 27/1-27/2 and meets at point 'N'.
N–O	Line passes through village Ganpawali along the outer boundary of plot numbers 27/1-27/2, 39/1-39/2, 38, 37/1-37/2, 46 and meets at point 'O'.
O–Q–J	Line passes through villages Ganpawali Katara, Bopeshwar, Makardhokra along the northern boundary of Railway line and meets at starting point 'J'.

SCHEDULE 'A1'

MAKARDHOKRA BLOCK

NAGPUR AREA

DISTRICT NAGPUR (MAHARASHTRA STATE)

All Rights

Serial number	Name of village	Patwari circle number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	Makardhokra	17	Umrer	Nagpur	37.24	Part
2	Bopeshwar	17	Umrer	Nagpur	3.88	Part
3.	Ganpawali	22	Umrer	Nagpur	5.29	Part
4.	Katara	22	Umrer	Nagpur	259.13	Part
5.	Sirpur	22	Umrer	Nagpur	144.87	Part
6.	Kanhwa	22	Umrer	Nagpur	96.48	Part
	Total area of schedule 'A1'—				546.89 hectares (approximately) or 1351.37 acres (approximately)	
	Grand total All Rights area of Schedule 'A'+'A1'				—503.95+546.89=1050.84 Hectartes (approximately) or 1245.26+1351.37=2596.63 acres (approximately)	

Plot numbers to be acquired in village Makardhokra : 160, 340, 341, 343 to 347, 377 Part, 572, 578, Road Part.

Plot numbers to be acquired in village Bopeshwar : 125 to 129.

Plot numbers to be acquired in village Ganapawali : 51 to 55.

Plot numbers to be acquired in village Katara : 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 34 to 41, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 43/2, 44 to 112, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 116, 117, 130, 133 to 143, Road Part, Nallah.

Plot numbers to be acquired in village Sirpur : 6 to 22, 25, 26, 39 to 80, 81/1, 81/2, 81/3, 82 to 93 94/1, 94/2, 95, 116 to 118, 122 to 128, 129/1, 129/2, 129/3, 130, Road Part, Nallah Part.

Plot numbers to be acquired in village Kanhwa : 90 to 116, 120 to 122, 123 Part, 124 Part, 134, 135 Part Road Part, Nallah Part.

Boundary description :

A–B	Line starts from point 'A' and passes through villages Makardhokra, Bopeshwar, Katara Ganpawali and Kanhwa along the southern boundary of Railway line and meets at point 'B'.
B–B1–C–D	Line passes through village Kanhwa along the soutern boundary of Railway line, the proceeds along the outer boundary of road, plot number 134 in plot numbers 135, 124 and meets at point 'D'.
D–E	Line passes through village Kanhwa in plot numbers 124, 123 along the outer boundary of plot number 122, crosses road and proceeds along the outer boundary of road, 114, 116, and meets at point 'E'.
E–F	Line passes through village Kanhwa and passes along the outer boundary of plot numbers 116, 115, 114, road, 113, 90, crosses nallah, then proceeds through village Sirpur along the outer boundary of plot number 95, crosses road and meets at ponint 'F'.
F–R	Line passes through village Sirpur along the outer boundary of road, plot numbers 116 118, 122, 129/1-129/2–129/3, 130 and meets at point 'G'.
M	Line passes through village Sirpur along the outer boundary of plot numbers 130, 6, crosses road, along the outer boundary of plot numbers 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26 47, 46, 40, crosses nallah along the outer boundary of plot number 39, then proceed along the common boundary of villages Sirpur and Katara and metets at point 'H'.
H–I	Line passes through village Katara along the outer boundary of plot numbers 110, 113/-1 113/2-113/3-113/4, 116, 117, 38 and meets at point 'I'.
I–A	Line passes through village Makardhokra in plot number 377, crosses road, then proceeds along the outer boundary of plot numbers 578, 347, 345, 344, 160 and meets at starting point 'A'.

SCHEDULE 'B'

MAKAR DHOKRA BLOCK
NAGPUR AREA
DISTRICT NAGPUR (MAHARASHTRA STATE)

Mining Rights

Serial number	Name of village	Patwari circle number	Tahsil	District	Area in hectors	Remarks
1.	Makardhokra	17	Umrer	Nagpur	10.50	Part
2.	Bopershwar	17	Umrer	Nagpur	1.55	Part

1	2	3	4	5	6	7
3. Ganpawali		22	Umrer	Nagpur	5.49	Part
4. Katara		22	Umrer	Nagpur	87.70	Part
5. Kanhwa		22	Umrer	Nagpur	0.03	Part
				Total area :	26.27 hectares (approximately) or 64.91 acres (apprxoima ely)	

Plot numbers to be acquired in village Makardhokra : Railway Part.

Plot numbers to be acquired in village Bopeshwar : 7

Plot numbers to be acquired in village Ganpawali : 50

Plot numbers to be acquired in village Katara : 5

Plot numbers to be acquired in village Kanhwa : 203

Boundary description :

A–B	Line starts from point 'A' and passes through villages Makardhokra, Bopeshwar, katara, Ganpawali and Kanhwa along the southern boundary of Railway line and meets at point 'B'.
B–P	Line passes along the common boundary of villages Kanhwa and Ganpawali, crosses the railway line and meets at point 'P'.
P–O–Q–J–	Line passes along the northern boundary of Railway line through villages Ganpawali Katara, Bopeshwar and Makardhokra and meets at point 'J'.
J–A	Line passes through village Makardhokra and crosses the Railway line and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/4/88-LSW]

B.B. RAO, Under Secy.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग)

नई दिल्ली, 3 मई, 1991

का. आ. 1454 :— केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 3 की उपधारा 3 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री डी.सी. गुप्ता, संयुक्त सचिव (पी एफ-II), (व्यय विभाग), वित्त मंत्रालय को तेल उद्योग विकास बोर्ड में एक सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से और दो वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए या जब तक वे संयुक्त सचिव (पी एफ-II) के पद का त्याग करते हैं, इनमें से जो पहले हो, नियुक्त करती है।

[संख्या जी-35012/1/91-वित्त-II]

राजीव शर्मा, निदेशक (वित्त)

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Deptt. of Petroleum and Natural Gas)

New Delhi, the 3rd May, 1991

S.O. 1454.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 3 of the Oil Industry Development Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri D. C. Gupta, Joint Secretary (PF-II), (Deptt. of Expenditure), Ministry of Finance as a Member of the Oil Industry Development Board with immediate effect and for a period of two years or till he demits the post of Joint Secretary (PF-II), whichever is earlier.

[No. G-35012[2]91-Fin. II]

RAJIB SHARMA, Director (Finance)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मई, 1991

का.आ. 1455 :—दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय दंत परिषद से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग-1 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची के भाग-I में केरल विश्वविद्यालय से संबंधित क्रम संख्यांक 14 के सामने स्तंभ 2 और स्तंभ 3 में मद (ii) में की विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"(iii) मास्टर आफ डेंटल सर्जरी (ओरल पैथोलाजी एण्ड माइक्रोबायलोजी)	एम.डी.एस. (ओरल पैथोलाजी एण्ड माइक्रोबायालोजी) केरल"	

[संख्या वी–12018/6/86–पी.एम.एस.]

आर. श्रीनिवासन, अवर सचिव

टिप्पणी : —अनुसूची में बाद में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :—

1. का.आ. संख्या 1548, दिनांक 3 मई, 1988
2. का.आ. संख्या 2255, दिनांक 1 जुलाई, 1988
3. का.आ. संख्या 79, दिनांक 22 दिसम्बर, 1988
4. का.आ. संख्या 2672, दिनांक 26 सितम्बर, 1989
5. का.आ. संख्या 3138, दिनांक 15 नवम्बर, 1989
6. का.आ. संख्या 3282, दिनांक 12 दिसम्बर, 1989
7. का.आ. संख्या 668, दिनांक 26 फरवरी, 1990
8. का.आ. संख्या 1502, दिनांक 3 मई, 1990
9. का.आ. संख्या 1762, दिनांक 5 जून, 1990
10. का.आ. संख्या 1763, दिनांक 13 जून, 1990
11. का.आ० संख्या 3427, दिनांक 19 नवम्बर, 1990
12. का.आ. संख्या 3338, दिनांक 27 नवम्बर, 1990

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 1st May, 1991

S.O. 1455.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Central Government, after consulting the Dental Council of India, hereby makes the following further amendment in Part I of the Schedule to the said Act, namely :—

In Part I of the said Schedule, against serial number 14 relating to the Kerala University, in columns 2 and 3, against item (ii), after the existing entries, the following entries shall respectively be added, namely :—

"(iii) Master of Dental Surgery (Oral Pathology and Microbiology)	—M.D.S. ((Oral Pathology and Microbiology) Kerala."

[No. V-12018/6/86-PMS]

R. SRINIVASAN, Under Secy.

FOOT NOTE.—Part I of the Schedule was subsequently amended vide :—

1. S.O. number 1548 dated the 3rd May, 1988.
2. S.O. number 2255 dated the 1st July, 1988.
3. S.O. number 79 dated the 22nd December, 1988.
4. S.O. number 2672 dated the 26th September, 1989.
5. S.O. number 3138 dated the 15th November, 1989.
6. S.O. number 3282 dated the 12th December, 1989.
7. S.O. number 668 dated the 26th February, 1990.
8. S.O. number 1502 dated the 3rd May 1990
9. S.O. number 1762 dated the 5th June, 1990.
10. S.O. number 1763 dated the 13th June, 1990.
11. S.O. number 3427 dated the 19th November, 1990.
12. S.O. number 3338 dated the 27th November, 1990.

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली क्षेत्र)

नई दिल्ली, 10 मई 1991

का. आ. 1456.—चूंकि निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कतिपय संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार नीचे वर्णित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली बृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है, जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61 की धारा 44 के अनुसार दिनांक 10 नवम्बर, 1990 के नोटिस सं० एफ० 20 (16)/89 एम० पी० द्वारा प्रकाशित किये गये थे, जिसमें उक्त धारा 11-क की उपधारा (3) में अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन की अवधि के भीतर आमंत्रित किये गये थे;

और क्योंकि उक्त प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जनता से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है, चूंकि केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली बृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

अतः; अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11—क की उप धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त वृहद योजना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन

"700 हेक्टेयर (1729 एकड़) भूमि क्षेत्र जो रोहिणी योजना के पश्चिम में, मौजूदा नांगलोई नाले के पार और उत्तर में गांव प्रहलादपुर बांगर की राजस्व संपदाओं पश्चिमों में पंसाली बेगम पुर और मोहम्मदपुर माजरा गांवों की राजस्व सम्पदाओं, दक्षिण-पश्चिमी गांव में गांव निथारी की राजस्व सम्पदाओं दक्षिण में पूठकला गांव की मौजूदा आबादी और उत्तर पूर्व में मौजूदा नांगलोई नाले से घिरे हुए क्षेत्र के भूमि उपयोग को ग्रामीण उपयोग से निम्नलिखित में परिवर्तित किया जाता है:—

(क) आवासीय	395 हेक्टेयर
(ख) व्यावसायिक	35 हेक्टेयर
(ग) सार्वजनिक और अर्धसार्वजनिक सुविधाएं	63 हेक्टेयर
(घ) मनोरंजनात्मक	105 हेक्टेयर
(ङ) परिचालन	102 हेक्टेयर

[सं० के 13011/19/90—डी डी आई बी)]

अर्जुन देव, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi, Division)

New Delhi, the 10th May, 1991

S.O. 1456.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi|Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 20(16)|89-MP dated 10-11-1990 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting obejections|suggestions as required by sub-section (3) of Section II-A of the said Act within thirty days from the date of the said notice.

And whereas no objection|suggestions were received from the Public with regard to the said proposed modifications and whereas the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi|Zonal Development Plan;

Now, whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section II-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATIONS :

"The land use of an areas measuring 700 hect. (1729 Areas) located in the west of Rohini Scheme, across the existing Nangloi drain and bounded by revenue, estates of village Prahladpur Bangar in the North, revenue estate of villages Pansali, Begampur and Mohammadpur Mazra in the West revenue estates of village Nithari in the South West existing village abadi Poothkalan in the South and existing Nangloi drain in the North-East is changed from 'Rural Use' to :—

(a) Residential	395 hects.
(b) Commercial	—35 hects.
(c) Public & Semi Public Facilities	—63 hects.
(d) Recreational	—105 hects.
(e) Circulation	—102 hects.

[No. K-13011/19/90-DDIB]]

ARJAN DEV, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1991

का. आ. 1457 .—चलचित्र अधिनियम 1952 (37 का 1952) की धारा 5 की उपधारा (1) तथा चलचित्र (प्रमाणन) के नियम 1983 के नियम 7 और 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के त्रिवेंद्रम सलाहकार पैनल में श्रीमती डी. सांता कुमारी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करती है।

[फाइल सं. 814/10/90-एफ. (सी)]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 24th April, 1991

S.O. 1457.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), and rules 7 and 8 of the Cinematograph (Certification) Rules 1983, the Central Government directs that Smt. D. Santha Kumari will cease to be member of the Trivandrum Advisory Panel of the Central Board of Film certification with immediate effect.

[File No. 814|10|90-F(C)]

नई दिल्ली, 2 मई, 1991

का. आ. 1458 —चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 7 और 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि श्रीमती नंदिनी कृष्णन और श्रीमती भामाराय कृष्णन तत्काल प्रभाव से केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के तिरुवंतपुरम सलाहकार पैनल के सदस्य नहीं रहेंगी ।

[फाइल सं. 814/10/90-एफ. (सी.)]

एम. एम. सेठी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd May, 1991

S.O. 1458.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), read with rule 7 and 8 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, the Central Government directs that Smt. Nandini Krishan and Smt. Bhanja Ramakrishnan shall cease to be members of the Thiruvananthapuram advisory Panel of the Central Board of Film Certification with immediate effect.

[File No. 814/10/90-F(c)]

M. S. SETHI, Desk Officer

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1991

का. आ. 1459.—केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में इस मंत्रालय की दि. दिनांक 19-2-1991 की अधिसूचना संख्या 809/1/91-एफ (सी.) में "3. श्री राकेश सिन्हा" को "3. श्री आर. के सिन्हा" पढ़ा जाये।

[फा. सं. 809/1/91-एफ (सी)]

एस लक्ष्मी नारायणन, संयुक्त सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th April, 1991

S.O. 1459.—In this Ministry's Notification No. 809/1/91-F(C) dated 19-2-91 regarding reconstitution of the Central Board of Film Certification for "3. Shri Rakesh Sinha"" read "3. Shri R. K. Sinha".

[File No. 809/1/91-F(c)]

S. LAKSHMI NARAYANAN, Joint Secy.

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1991

का. आ. 1460.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के, पर्यटन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3758 तारीख 30 सितम्बर 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है,

अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सारणी और प्रविष्टियां रखी जाएंगी,

अर्थात्:—

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थान के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
"प्रबंधक (कार्मिक), भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, अशोक रेडिसन होटल, हाई ग्राउंड्स, कुमारा कृपा, बंगलौर।	कर्नाटक राज्य में स्थित भारतीय पर्यटन विकास लिमिटेड के या उस के द्वारा पट्टे पर लिए गए सभी स्थान"।

[सं. 6/21/91-पीएसयू(टी)]

एस. के. राव, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi, the 30th April 1991

S.O. 1460—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Tourism No. S.O. 3758 dated the 30th September, 1982, namely:—

In the said notification, for the table as the entries relating thereto the following Table as entries shall be substituted, namely:—

TABLE

Designation of the Officer	Categories of Public premises and local limits of the jurisdiction.
1	2
"Manager (Personnel), India Tourism Development Corporation Limited, Ashok Radison Hotel, High Grounds, Kumara Krupa, Bangalore.	All premises belonging to or taken on lease by India Tourism Development Corporation Ltd. and situated in the State of Karnataka'.

[No. 6/21/91-PSU (T)]

S.K. Rao, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1991

का.आ. 1461 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, इसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-क के अधीन श्री अवध बिहारी, रावनवाड़ा खास कोलियरी, डाकघर-डिघवानी, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) द्वारा उप-क्षेत्रीय प्रबन्धक, पेंच-पूर्वी उपक्षेत्र, पेंच वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) के विरुद्ध शिकायत दायर करने पर, जो कि केन्द्रीय सरकार को 23 अप्रैल, 1991 को प्राप्त हुई थी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.) का (अनुबन्ध में यथानिर्दिष्ट पंचाट प्रकाशित करती है।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 30th April, 1991

S.O. 1461.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur (M.P.) as shown in the Annexure, on the complaint filed by Shri Awadh Bihari, Rawanwara Khas Colliery, P.O. Dighwani, Dist. Chhindwara (M.P.) against the Sub-Area Manager, Pench East Sub Area, Pench Area, Western Coalfields Ltd., Distt. Chhindwara (M.P.) under Section 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947, which was received by the Central Government on the 23rd April, 1991.

ANNEXURE

BEFORE SHRI V. N. SHUKLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(A)(5)/1982

PARTIES :

Shri Awadh Bihari, Rawanwara Kahs Colliery, P.O. Dighwani, District Chhindwara (M.P.) Complainant

Versus

The Sub-Area Manager, Pench East Sub-Area, Pench Area, Western Coalfields Limited, District Chhindwara (M.P.) ...Opposite Party.

APPEARANCES :

For Complainant—Shri R. K. Gupta, Advocate.

For Opposite Party—Shri Rajendra Menon, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mining DISTRICT : Chhindwara (M.P).

AWARD

Dated, the 10th April, 1991

This is a Complaint filed by Shri Awadh Bihari under Section 33-A of the I. D. Act, 1947.

2. The workman/complainant was a Head Clerk with the management and was retired from service with effect from 1-11-1981 on attaining the age of 60 years. He said to have been in service from 1939.

3. The Complainant says that there is no provision under which he could be retired at the age of 60 years. That a reference was pending before this Tribunal being No. CGIT/LC(R)(29)/81. The terms of the reference are as follows:

"Whether the action of the management of (Rawanwara Khas Colliery of Messrs Western Coalfields Limited), in not regularising Shri Awadh Bihari as Head Clerk, and in transferring him to Pench East Colliery as Despatch Clerk from 16-3-1980 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

Hence no change in his service condition could be made pending a decision of the reference and permission of the Tribunal was necessary before retiring the workman. It amounts to retrenchment and in the circumstances he is entitled to retrenchment compensation under Sec. 25F of the I.D. Act.

4. According to the management, the reference matter was a distinct matter not connected with this case. He was rightly retired at the age of superannuation i.e. 60 years. He has not been retrenched. He is not entitled to any compensation or any relief whatsoever. The complaint is not maintainable under Sec. 33-A of the I.D. Act and therefore it be rejected.

5. Following issues were framed by my learned predecessor and my findings are recorded as under.

ISSUES

1. Whether under circumstances of the case the workman could be retired at the age of 60 years?
2. Whether or not retirement of the workman militates against the terms of reference pending before the Industrial Tribunal for adjudication?
3. Whether it is necessary to obtain permission of the Tribunal before retiring the workman?
4. Whether the retirement of the petitioner would amount to retrenchment?
5. Whether in the present circumstances the complaint is maintainable under Section 33-A of the I.D. Act?

FINDINGS :

6. Issues No. 1 to 5.—I will deal with all these issues together for the purpose of gravity and convenience. The Award arising out of the Reference is Ex. W/1 and the application of the workman addressed to the Deputy Chief Mining Engineer is Ex. W/2. Management has also filed two documents Ex. M/1 and Ex. M/2. The workman/complainant on his part examined himself in support of his case.

7. At the out set I must point out that the reference relating to the Award Ex. W/1 is entirely different and is not connected with the superannuation of the workman concerned. The terms of reference are reproduced above. I need not reproduce the facts of the case in Reference No. 29/81. However, I reproduce the relevant part of the order made in the Award in Case No. 29/81 which is as under :—

"I, therefore, answer the question referred by saying that the workman was entitled to be regularised on the post of a Head Clerk from May, 1977 onwards and his transfer to another colliery as a Despatch Clerk was unjustified. He would, therefore, be entitled to the salary and all other benefits of a Head Clerk till his date of retirement. The workman is entitled to costs of Rs. 100 from the management."

Thus this reference relates to entirely different issues altogether and would not come in the way of issuing the order of retirement at the age of superannuation. The workman has admitted that while he was working in the private colliery there was no agreement to the effect that particular age shall be the age of superannuation. He was not given any fresh appointment by the present management who had taken over the mines at the time of nationalisation. Thus the rules or the direction issued by the competent authority in this regard would be binding on the workman concerned and as per Ex. M/1 the age of superannuation

was enhanced from 58 to 60 years and the workman was retired on the age of superannuation i.e. when he attained the age of 60 years. Thus there is no retrenchment of the workman. It was not necessary to obtain the permission of the Tribunal before retiring the workman. The retirement certainly does not amount to retrenchment. The Complaint is not tenable in the circumstances. Complaint under Sec. 33A of the I.D Act is accordingly dismissed with no order as to costs. I answer the issues accordingly. Award is also made accordingly.

V. N. SHUKLA, Presiding Officer

[No. L-22013/6/91-IR (C-II)]

नई दिल्ली, 1 मई, 1991

का.आ. 1462 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पारसकोल कोलयिरी आफ मै. ई.सी.लि. के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद मे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-4-91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 1st May, 1991

S.O. 1462.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the empoyers in relation to the management of Parascole Colliery of M/s. E.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 30-4-91.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL

Referneec No. 55/88

PARTIES :

Employers in relation to the Management Parascole Colliery of M/s. E.C. Ltd.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri P. K. Das, Advocate.

For the Workman—Shri B. Kumar, Joint Secretary of the Union.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal

Dated, the 22nd April, 1991

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-24012(248)/87-D.IV(B) dated the 28th July, 1988.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Parascole Colliery of M/s. E.C. Ltd., in not referring the case of Shri Gopal Paul to the Appex Medical Board prior to his retirement i.e. 10-3-87 and not giving employment to his dependant when he remained idle from October, 1985 to 10-3-87 on account of his not being able to resume duty, is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

2. Today (22-4-91) Sri B. Kumar, Joint Secretary of the union submits that he has no instruction to proceed with the case. The concerned workman has also not turned up. It appears to me that no dispute exists. Accordingly a no dispute award is passed in this case.

N. K. SAHA, Presiding Officer

[No. L-24012/248/87-D IV(B)]

का.आ. 1463 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार माधायपुर कोलियरी आफ मै. ई.सी.लि. के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-4-91 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1463.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the the management of Madhaipur Colliery of M/s. E.C. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 30-4-91.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL

Reference No. 50/89

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Madhaipur Colliery of M/s. E.C. Ltd.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri P. Banerjee, Advocate.

For the Workmen—Shri M. Mukherjee, Advocate.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

Dated, the 22nd April, 1991

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-22012(197)/89-IR (C.II) dated the 5th/6th December, 1989.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Madhaipur Colliery of M/s. E.C. Ltd., in retrenching S/Sri Nanda Lal Kurmi and 21 others (listed below) on and from 9-1-79 is justified? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?"

LIST OF THE WORKMEN

Pl. see Annexure for list)

2. Today (22-4-91) Sri M. Mukherjee, learned Advocate for the union submits that he has no instruction to proceed with the case. The concerned workmen have also not turned up. It appears to me that no dispute exists. Accordingly a no dispute award is passed in this case.

N. K. SAHA, Presiding Officer

[No. L-22012/197/89-IR (C-II)]

RAJA LAL, Desk Officer

Enc : List of Workmen

ANNEXURE-A

Part of the Award

1. Shri Nandalal Kurmi—Black Smith
2. Shri Ram Mistry—Black Smith
3. Shri Chittranjan Karmakar—Welder
4. Shri Jaikanto Roy—Mason Mistry
5. Shri Id. Mahamman- Stone cutters
6. Shri Md. Mohasin—Stone cutter
7. Shri Sk. Sardar Ali Khan—Stone cutter
8. Shri Balram Bouri—Stone cutter
9. Shri Sk. Murtuja Ali—Stone cutter
10. Shri Moor Haru—Stone cutter
11. Shri Sk. Mohiuddin—Stone cutters
12. Shri Abdul Alim—Stone cutter
13. Shri Md. Illiss—Stone cutter
14. Shri Meer Anwar—Stone cutter
15. Shri Chanek Bouri—Stone cutter
16. Shri Arun Kr. Mondal—Stone cutter
17. Shri Jitan Dome—Stone cutter
18. Shri Shyam Dome—Stone cutter
19. Shri Pather Bagdi—Stone cutter
20. Shri Sudan Bagdi—Stone cutter
21. Shri Dulal Patra—Stone cutter
22. Shri Chakradhar Pandey—Stone cutter.

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1991

का.आ. 1464 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कैंट बोर्ड, पूना के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-4-91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 30th April, 1991

S.O. 1464.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Cantt. Board Pune and their workmen, which was received by the Central Government on 29-4-91.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/3 of 1991

PARTIES :

Employers in relation to the management of Cantonment Board, Pune.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employer—1. Shri G. S. Sohal, Cantonment Executive Officer|

2. Shri S. N. Kurpe, Advocate..

For the Workmen—Shri M. S. Shivane, General Secretary, Pune Cantonment Karmachari Sangh.

INDUSTRY : Cantonment Board STATE : Maharashtra

Bombay dated the 19th April, 1991

AWARD

The Central Government by their order No. L-13011/8/90-IR(DU), dated 23-1-1991 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudicaiton under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :

"Whether the action of the Cantonment Board, Pune in relation to all its workmen at Pune in cancelling the 1st, 3rd and 5th saturday holidays of a month w.e.f. 16-9-88 and not making payment of overtime to the workmen entitled for these holidays is justified? If not, to what relief the workmen are entitled?"

2. A notice of this reference was duly served upon both the parties. Both the parties appeared before this Tribunal. However, the Union did not file its Statement of Claim challenging the said action of the Cantonment Board, and the Cantonment Board also did not file its Written Statement in support of its action.

3. However, on 11-4-1991 the General Secretary of the Union (Sangh) filed his application stating that the Union does not want to proceed further in the matter, as they want the said question to be discussed in the J.C.M. Meeting and they may be allowed to withdraw the present reference. The representative of the Cantonment Board made an endorsement on that application that Cantonment Board has no objection for the withdrawal of this reference.

4. Therefore, as the Union does not want to proceed further in the matter, the present reference stands disposed off The parties to bear their own costs of the reference.

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer

[No. L-13011/2/90-IR (DU) (Pt.)]

का.आ. 1465 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार खादी एण्ड विलेज इन्डस्ट्री कमीशन, बीकानेर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण बीकानेर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-4-91 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1465.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Bikaner as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Khadi & Village Industries Commission Bikaner and their workmen, which was received by the Central Government on 30-4-91.

औद्योगिक न्यायाधिकरण, बीकानेर

केन्द्रीय औद्योगिक विवाद प्रसंग सं. 1 सन् 1988

खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन, बीकानेर

—प्रार्थी/यूनियन

बनाम

खादी एंड विलेज इण्डस्ट्रीज कमिशनर, बाम्बे

—प्रार्थी/नियोजक

रैफरेन्स अन्तर्गत धारा 10 (1) (घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

उपस्थिति

न्यायाधीश—श्री पी.एस. शुक्ला, आर.एच.जे.एस.

1. श्री कन्हैयालाल जोशी —स्वयं श्रमिक.

2. श्री विपिनचन्द गोयल, अधिवक्ता विपक्षी नियोजक की ओर से

अवार्ड

दिनांक 14 जनवरी, 1991

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक 42012/8/83-डी-II/बी. दिनांक 9-12-1983 के द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर को प्रेषित प्रसंग के अन्तर्गत निम्न विवाद निपटारे हेतु भेजा था :—

Whether the action of Khadi and Village Industries Commission, Bikaner denying an opportunity of Interview to Shri K. L. Joshi, U.D.C. for the post of Assistant Director (Gen. Admn/Training/HBT-WSA) before the selection Board during June 1980 isjustified ? If not, to what relief is Shri Joshi entitled ?

तदुपरान्त श्रम मंत्रालय के आदेश दिनांक 6-11-87 द्वारा यह प्रकरण इस न्यायाधिकरण को भेजा गया है।

2. इस प्रसंग के अन्तर्गत प्रार्थी श्रमिक ने अपना क्लेम प्रस्तुत करते हुए यह पक्ष रखा कि वह औद्योगिक कर्मकार है और उसकी योग्यता एम.ए. लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र में है तथा वह हील एण्ड बोर्डर एरिया में कार्यरत है जिससे अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता के कारण उच्च पद पर नियुक्ति का अधिकारी है। उसका यह पक्ष है कि विपक्षी खादी कमीशन ने उच्च पदों पर भर्ती के लिये एक सेवा मण्डल बना रखा है तथा प्रार्थी खादी कमिशन कर्मचारी यूनियन का सक्रिय व प्रभासणाली कार्यकर्ता रहा है तथा आफिस बियरर रहा है जिससे विपक्षीगण अप्रसन्न रहते है और उसके साथ भेदभाव की नीति अपनाते थे। प्रार्थी ने यह क्लेम प्रस्तुत किया है कि विज्ञापन दिनांक 30-6-80 के आधार पर उसने सहायक निदेशक, जी.ए.,एच.बी.टी. डब्ल्यू.एस.ए. व सहायक निदेशक प्रशिक्षण के पदों हेतु आवेदन पत्र भिजवाये थे। किन्तु, साक्षात्कार में उसे नहीं बुलाकर अन्य व्यक्ति जो योग्यता एवं अनुभव में न्यून थे, उन्हें मनमानीपूर्ण कार्यवाही कर मनमानी छूट देकर पदों को भरने की कार्यवाही कर ली। उसने यह भी पक्ष रखा कि वरिष्ठ लिपिक होते हुए उसने कई बार अधीक्षक का कार्य किया है और उसे साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं करने की कार्यवाही बदनीयति पर आधारित है, स्वेच्छाचारी है, जो बिना मस्तिष्क लगाये व बिना न्यायसंगत विचार किये विधि विरुद्ध की गई है। उसने यह प्रार्थना की कि उसको विज्ञापन दिनांक 20-6-80 के आधार पर साक्षात्कार में सम्मिलित किये जाने का आदेश पारित किया जाये अथवा उसे सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जावे।

3. विपक्षी ने जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी को कर्मकार और स्वयं को औद्योगिक संस्थान होना नकारा है। उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि प्रार्थी वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य कर रहा है किन्तु यह पक्ष रखा कि केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही उसको उच्च पद का अधिकारी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह सहायक निदेशक पद की कोई योग्यता या अनुभव नहीं रखता है और विपक्षी साक्षात्कार हेतु उसको बुलाये जाने के लिये बाध्य नहीं था। अन्य आपत्तियों के साथ यह भी आपत्ति उठाई गई कि साक्षात्कार हेतु बुलाने अथवा न बुलाने का विवाद "औद्योगिक विवाद" की परिभाषा में नहीं आता है जिससे ऐसा विवाद न्यायालय में चल सकने योग्य नहीं है। यह भी कि प्रार्थी को उपयुक्त अनुभव प्राप्त नहीं है जिससे कि उसको साक्षात्कार के लिये विचारणीय माना जाए तथा यह भी आपत्ति उठाई गई कि खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन एक स्वायत्तशासी संगठन है।

4. उपर्युक्त वाद-प्रतिवाद के आधार पर निम्न विचारणीय बिन्दु प्रकट होते हैं :—

1. क्या प्रार्थी श्रमिक एवं विपक्षी उद्योग है एवं उनके मध्य कर्मकार और नियोजक का सम्बन्ध स्थापित है ?

2. क्या साक्षात्कार में बुलाने अथवा न बुलाने का विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है, जिससे ऐसा विवाद इस न्यायालय में चल सकने योग्य नहीं है ?

3. क्या प्रार्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाने की सुविधा न देना अनुचित है ?

4. प्रतिकार ?

उपर्युक्त बिन्दुओं को सिद्ध करने हेतु प्रार्थी श्रमिक कन्हैयालाल जोशी ने स्वयं को साक्ष्य गृह में बतौर डब्ल्यू डब्ल्यू 1 पेश किया है और विपक्षी की ओर से श्री वेदप्रकाश आर्य एम.डब्ल्यू. 1 साक्ष्य गृह में प्रस्तुत हुए है। इन साक्षीगण के कथन, पत्रावली व प्रपत्रों के अवलोकन तथा पक्षकारों के तर्क श्रवण के पश्चात् मेरे विचारित निष्कर्ष निम्न है :—

बिन्दु सं. 1

5. इस बिन्दु के अन्तर्गत विपक्षी का यह पक्ष है कि सहायक निदेशक को वेतन श्रृंखला में लगभग 1600-1700-

सम्पूर्ण वेतन व भत्तों सहित प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सहायक निदेशक का पद कर्मकार की परिभाषा में नहीं आता है। किन्तु, उनका यह तर्क उपयुक्त नहीं है। प्रार्थी ने स्वयं को वरिष्ठ लिपिक होना वर्णित किया है और यह तथ्य स्वीकृत है कि प्रार्थी विपक्षी नियोजक के अधीन वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य कर रहा है। इस प्रकार प्रार्थी वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य करने वाला कर्मकार है क्योंकि विवाद के समय प्रार्थी की स्थिति ही विचारित किये जाने योग्य होती है और यह केवल काल्पनिक है कि पदोन्नत पद पर प्रार्थी कर्मकार रहेगा अथवा नहीं क्योंकि पदोन्नति का पद कर्मकार की परिधि के बाहर है और पर्यवेक्षकीय पद है। फलस्वरूप प्रार्थी स्वीकृत स्थिति के अनुसार वरिष्ट लिपिक है, कर्मकार है, ऐसा सुरक्षापूर्वक अभिनिर्णीत किया जा सकता है।

6. विपक्षी अभिभाषक का यह भी तर्क है कि खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन स्वायत्त शासी संगठन है जिसका गठन भारत सरकार द्वारा किया जाता है और भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही इसके अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सचिव व सदस्य होते हैं जिससे भी विपक्षी एक औद्योगिक संस्थान नहीं है। किन्तु बेंगलोर वाटर सप्लाई एण्ड सिवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा-1978 लेब आई सी -467 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के उपरान्त अब यह विवाद शांत हो गया है। बेंगलोर वाटर सप्लाई एण्ड सिवरेज बोर्ड वाले इस प्रकरण में यह व्यवस्था दी गई है कि जहां व्यवस्थित क्रिया कलाप, नियोजक और कर्मकार के पद पर सहयोग से मानवीय इच्छा पूर्ति हेतु किसी वस्तु का विनिर्माण अथवा वितरण किया जाता है, "उद्योग" की परिभाषा में जायेगा। इस प्रकार इस दृष्टि से विपक्षी नियोजक संस्थान एक "औद्योगिक संस्थान" है। इस प्रकरण में प्रार्थी कर्मकार है और इन दोनों के मध्य नियोजक और कर्मकार का आपसी सम्बन्ध स्थापित है जिससे यह बिन्दु सकारात्मक रूप में अभिनिर्णीत किया जाता है।

बिन्दु सं. 2

7. विपक्षी ने यह आपत्ति उठाई है कि किसी कर्मकार को साक्षात्कार हेतु बुलाने अथवा न बुलाने का विवाद "औद्योगिक विवाद" की परिभाषा में नहीं आता है। जिससे यह विवाद इस न्यायालय के समक्ष चल सकने योग्य नहीं है। श्रमिक कन्हैयालाल जोशी ने स्वयं तर्क प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष यह रखा कि उनका विवाद अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के खण्ड 6 तथा तृतीय अनुसूची के खण्ड II के अधीन है। किन्तु द्वितीय अनुसूचि का खंड 6 यह प्रावधान करता है कि ऐसे सभी मामले जो तृतीय सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है जो श्रम न्यायालय के अधिक्षेत्र में विचारणीय माने जा सकते हैं। प्रथम तो यह न्यायालय औद्योगिक न्यायालय है जिसके समक्ष यह प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय, यह कि यह खण्ड केवल यह प्रावधान करता है कि जो विवाद तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है उनको द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत श्रम न्यायालय द्वारा विचारित किये जा सकता है। प्रकट रूप से खण्ड-6 उन निःशेष मामलों से सम्बन्धित है जो तृतीय अनुसूची में विशिष्ट रूप से वर्णित नहीं किये गये हैं। इस प्रकार खण्ड-6 सकारात्मक रूप में यह प्रावधान नहीं करता कि साक्षात्कार का विषय "औद्योगिक विवाद" है बल्कि यह खण्ड तो यह वर्णित करता है कि जो मामले तृतीय अनसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, उन मामलों को श्रम न्यायालय विचारित कर सकता है। वास्तव में यह द्वितीय अनसूची तो श्रम न्यायालय के अधिक्षेत्र में आने वाले मामलों से सम्बन्धित है जिससे व उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का पक्ष स्थापित नहीं रहता है कि उसका यह विवाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र के अधीन आता है।

8. तृतीय अनुसूची धारा 7-ए के अन्तर्गत उन मामलों का सम्बन्ध है जो औद्योगिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तृतीय अनुसूची के खण्ड-II में जिस पर कि प्रार्थी ने स्वयं को आधारित किया है, यह प्रावधान किया गया है कि कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए। फलस्वरूप इस खण्ड का सीधा सादा तात्पर्य यह है कि कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए तो उस पर भी औद्योगिक न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। प्रार्थी श्रमिक यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि उसको साक्षात्कार में न बुलाने का मामला उपयुक्त सरकार ने विहित (Prescribed) किया है। वह यह भी स्पष्ट नहीं कर पाया है कि उसका मामला किस प्रकार विहित मामले की परिधि में आता है। परिणाम यह है कि प्रार्थी को साक्षात्कार के लिये बुलाया जाए अथवा नहीं, तृतीय अनुसूची के अन्तर्गत भी नहीं आता है क्योंकि खण्ड-II इसके लिये कोई प्रावधान नहीं करता है।

9. प्रार्थी श्री कन्हैयालाल जोशी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है कि वह यूनियन का सक्रिय कार्यकर्ता रहा है जिससे उसको दमित करने के प्रयोजन श्रम प्रक्रिया के अन्तर्गत साक्षात्कार के लिये उसको नहीं बुलाया गया। किन्तु जहां कर्मकार यह आक्षेपित करें कि विपक्षी ने दुर्भावना की है अथवा अनुचित श्रम प्रक्रिया अपनाई है अथवा दमनकारी कार्य किया है तो यह अपेक्षा है कि वह पर्याप्त व समुचित साक्ष्य से इसे साबित करें। ओ.पी. मल्होत्रा द्वारा रचित "दी लॉ आफ इण्डस्ट्रियल डिस्प्युट्स" चतुर्थ संस्करण के पृष्ठ सं. 249 में यह उल्लेखनीय किया गया है कि केवल मात्र यह आक्षेपित करना ही पर्याप्त नहीं है अपितु उसको उपयुक्त साक्ष्य द्वारा सिद्ध भी किया जाना चाहिये। न्यायमूर्ति बांच ने 1966 (1) एल.एल.जे. (एस.सी.) 402 में यह अभिनिर्णित किया है कि अधिकरण बिना सापेक्ष पर विचार के किसी निष्कर्ष पर किन्हीं बाहरी तत्वों के आधार पर पहुंचे तो अधिकरण का ऐसा निष्कर्ष दूषित है और निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने साक्ष्य में यह अवश्य कहा है कि वह मान्यताप्राप्त यूनियन का आफिस बियरर है। किन्तु उसने यह बताया है कि वह यूनियन की केन्द्रीय कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष पिछले चार वर्षों से है अर्थात् 1985 से है जबकि यह विवाद 1980 का है। यद्यपि उसने यह अनभिज्ञता प्रकट की है कि राज्य खादी।

कमिशन कर्मचारी यूनियन राजस्थान में मान्यता प्राप्त है या नहीं और उसने यह भी नकारा है कि उसकी यूनियन में मात्र 2-3 सदस्य ही हो। किन्तु प्रार्थी के कथन से यह अत्यन्त स्पष्ट है कि प्रार्थी यूनियन का सक्रिय कार्यकर्ता अथवा आफिस बियरर नहीं था जिससे उसके विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण कार्य किये जाने अथवा दमन कर अनुचित श्रम प्रक्रिया अपनाने का प्रश्न ही नहीं है। इस विश्लेषण का यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा उठाया गया यह विवाद द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची अथवा पंचम अनुसूची की परिधि में नहीं आता है जिसके परिणामस्वरूप यह विवाद कि श्रमिक को किसी साक्षात्कार के लिये बुलाया जाय अथवा नहीं यह "औद्योगिक विवाद" की परिधि में नहीं आता है क्योंकि साक्षात्कार के उपरान्त भी एक लम्बी प्रक्रिया के पश्चात चयन सम्पूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार हेतु न बुलाया जाना पदोन्नति नकराने के समकक्ष नहीं है। जिसमें किसी व्यक्ति को या किसी श्रमिक को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने अथवा न बुलाये जाने का विवाद किसी भी प्रकार "औद्योगिक विवाद" की परिधि में नहीं आता है फलस्वरूप यह बिन्दु भी नकारात्मक रूप में अनिर्णित किया जाता है।

बिन्दु सं 3

10. प्रार्थी का यह पक्ष है कि योग्य होते हुए भी उसको साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया और अन्य उम्मीदवारों में श्री आर. पी. लेपचा को मात्र 33 प्रतिशत अंक बी. कॉम में प्राप्त करने व किसी अनजान डेयरी में कार्यरत होने पर उसे अनुभव व शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई जो उचित नहीं है। उनका तर्क यह है कि श्री. सुब्रहृमनियम श्री आर. एल. गुप्ता, श्री सी. जी. मदान, श्री पी. नारायण, श्री टी. एस. कृष्णन, श्री एस. एन. चौधरी आदि आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते थे फिर भी उनको साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया। किन्तु इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि सेवामण्डल ने शैक्षणिक योग्यता में चार आदमियों को छूट दी। श्री लेपचा को डेयरी मेनेजमेन्ट में तीन साल का अनुभव था और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी थे जिन्हें विशेष छूट प्रदान की गई थी। ऐसा साक्ष्य विपक्षी साक्षी श्री वेदप्रकाश आर्य एम. डब्ल्यू. ने प्रदान किया है। उन्होंने यह भी साक्ष्य प्रदान किया है कि श्री गुप्ता इकोनॉमिक इन्वेस्टीगेटर थे जो एम.ए. (इकोनॉमिक्स) थर्ड क्लास थे और इसके अतिरिक्त और भी योग्यताएं रखते थे। उन्होंने यह स्पष्ट साक्ष्य प्रदान किया है कि जिनको बुलाया गया है उनकी योग्यता निर्धारित योग्यता थी जबकि प्रार्थी को अनुभव की योग्यता नहीं थी। प्रदर्श-9 विज्ञापन दिनांक 20-6-80 यह प्रावधान करता है कि शैक्षणिक योग्यता द्वितीय श्रेणी स्नातक के साथ तीन वर्ष का न्यूनतम कार्मिक प्रबन्धकीय अथवा सामान्य प्रबन्धन मे पर्यवेक्षकीय स्थिति में अपेक्षित था। यह भी निर्धारित था कि विशेष योग्यता प्राप्त अथवा अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्यों को योग्यता अथवा अनुभव में छूट प्रदान की जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि चार व्यक्तियों को विशेष छूट देकर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया तो मात्र इससे प्रार्थी के पक्ष को कोई बल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकरण में यह विवाद नहीं है कि प्रार्थी श्रमिक उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता था अर्थात् प्रार्थी श्रमिक शैक्षणिक योग्यता अवश्य रखता था। विवाद केवल यह है कि विपक्षी के अनुसार प्रार्थी को अनुभव प्राप्त नहीं था जिससे उसको साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया। इस स्थल पर प्रार्थी ने अपना दोहरा पक्ष रखने का प्रयत्न किया है। प्रथम तो यह कि कुछ व्यक्तियों को शैक्षणिक योग्यता में छूट देकर भी बुलाया गया है और दूसरा यह कि यदि उसको अनुभव में छूट प्रदान की जाती तो वह भी साक्षात्कार हेतु प्रत्याशी हो सकता था। इस स्थिति को विपक्षी अभिभावक ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि विज्ञापन के अनुसरण में 58 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया जिनमें श्री गोपाल कृष्णन व श्री. सुब्रहृमनियम को भी बुलाया गया था जिन्हें शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई थी क्योंकि विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अनुसार उनके पास विज्ञापित पद से नीचे के पद अर्थात् सामान्य प्रशासन के पद अधीक्षक का लम्बा अनुभव प्राप्त था। उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेद भी बहुत अच्छे थे या असाधारण थे। यह भी पक्ष रखा गया कि अनुसूचित जाति के सदस्यों के एक पद के लिये केवल 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया जिनमें से केवल तीन उपस्थित हुए जिनमें श्री लेपचा भी थे। श्री लेपचा यद्यपि 33 प्रतिशत अंक पाने वाले बी-कॉम योग्यता प्राप्त थे किन्तु उन्हें तीन साल डेयरी मेनेजमेन्ट का अनुभव था तथा वह अनुसूचित जाति का सदस्य था जिससे उसको विशेष छूट प्रदान की गई थी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुसूचित जाति के सदस्यों के सदस्य कम संख्या में उपस्थित होने के कारण भी छूट दिया जाना नितान्त उपयुक्त है और किसी भी प्रकार अवांछनीय नहीं है क्योंकि यह शैक्षणिक योग्यता तो प्राप्त था किन्तु अनुभव में उसे केवल छूट प्रदान की गई थी और ऐसी छूट प्रदान करने के लिये खादी कमिशन ने प्रस्ताव सं. 17 (1) और 17 (2) जनवरी 81 में पारित किये थे। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि सहायक निदेशक केटेगरी सामान्य के लिये विज्ञापन की अनुपालना में कुल 181 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिनमें से 27 अभ्यर्थी अधिकांशतः विभागीय थे जो न केवल शैक्षणिक योग्यता प्राप्त थे अपितु उन्हें पर्यवेक्षकीय पद पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त थे उनमें से कुछ अधीक्षक थे, कुछ व्याख्याता थे अथवा प्रिंसीपल पद पर कार्य कर रहे थे और दो अभ्यर्थी कार्यकारी सहायक निदेशक के पद पर भी कार्य कर रहे थे। ऐसी स्थिति में सामान्य अभ्यर्थियों में अपेक्षाकृत ऐसे अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जाना नितान्त उपयुक्त समझा गया था उनका यह भी तर्क है कि ऐसी अवस्था में श्री के. एल. जोशी मात्र वरिष्ठ लिपिक थे और जिनको कोई अनुभव नहीं प्राप्त था किसी छूट दिये जाने की न तो आवश्यकता थी और न वांछनीयता जिससे श्री के. एल. जोशी को उपयुक्त ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित नहीं किया गया।

प्रार्थी से यह अपेक्षा है कि स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो। प्रार्थी यद्यपि शैक्षणिक योग्यता तो रखता था। किन्तु

उसको अनुभव प्राप्त नहीं था । प्रार्थी ने यद्यपि साक्ष्य में यह कहा है कि वह समय-समय पर अधीक्षक का कार्य करता था किन्तु विपक्षी साक्षी श्री वेदप्रकाश आर्य ने यह स्पष्ट कहा है कि प्रार्थी द्वारा अधीक्षक के पद पर नियमित रूप से अथवा अधीक्षक की गैर हाजिरी में उनकी एवज में कभी भी एक माह के लिये अस्थाई कार्य भी नहीं किया । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अनुभव की निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं थी। जिससे प्रार्थी न्यूनतम योग्यता ही नहीं रखता था तो केवल मात्र इस आधार पर साक्षात्कार के लिये न बुलाया जाना उपयुक्त नहीं है । प्रार्थी ने यह पक्ष नहीं रखा है कि उसको भी छूट प्रदान की जानी चाहिये थी अपितु उसने तो यह पक्ष रखा है कि कुछ व्यक्तियों को छूट दे कर पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है। किन्तु, जिन चार व्यक्तियों को छूट प्रदान की गई है उनके अनुभव प्राप्त हैं । ऐसी स्थिति में विज्ञापन प्रदर्ण-9 के आधार पर नियोजक को छूट देने का अधिकार होने से छूट दिया जाना अनुपयुक्त नहीं है । इस विश्लेषण का सारांश यह है कि प्रार्थी यह स्पष्ट साबित नहीं कर पाया है कि उसको साक्षात्कार हेतु न बुलाया जाना न केवल अनुचित था अपितु उसको साक्षात्कार हेतु अवश्य बुलाया जाना चाहिये था । परिणाम यह है कि यह बिन्दू नकारात्मक रूप में अभिनिर्णित किया जाता है ।

बिन्दू सं. 4

11. उपर्युक्त बिन्दुओं के निष्कर्षों के आधार पर यह तो प्रकट होता है कि प्रार्थी कर्मकार है और विपक्षी नियोजक औद्योगिक संस्थान है किन्तु यह स्थापित हुआ है कि प्रार्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने अथवा न बुलाये जाने का विवाद ऐसा विवाद नहीं है जो औद्योगिक न्यायालय में विचारणीय मामलों की परिधि में आता हो । फलस्वरूप ऐसे विवाद में श्रवणाधिकार क्षेत्र इस न्यायलय को प्राप्त नहीं है । गुणावगुण पर भी, प्रार्थी यह स्थापित नहीं कर पाया है कि उसको साक्षात्कार हेतु बुलाया जाना अपेक्षित था और साक्षात्कार हेतु न बुलाया जाना अनुचित है । परिणामस्वरूप प्रार्थी किसी प्रतिकार को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । जिससे यह प्रसंग नकारात्मक रूप में उत्तरित किये जाने योग्य है ।

आज्ञा :—

12. फलस्वरूप इस प्रसंग के अन्तर्गत यह पंचाट पारित किया जाता है कि :—

प्रार्थी श्रमिक को सहायक निदेशक, जी.ए.एच.डी.टी. डब्ल्यू.एस. व सहायक निदेशक प्रशिक्षण के पद हेतु साक्षात्कार की सुविधा न देना अनुचित नहीं है जिसके फलस्वरूप प्रार्थी किसी राहत को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

उपयुक्त पंचाट प्रकाशनार्थ भारत सरकार को भेजा जावे ।

13. आज्ञा आज दिनांक 14-1-1991 को सरे इजलास लिखाई व सुनाई गई।

पी.एस. शुक्ला., न्यायाधीश

[सं. एल.-42012/8/83-डी-2 (बी) (पीटी)]

का.आ. 1466:— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार खादी एवं विलेज इन्डस्ट्रिज कमीशन, बम्बई के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद औद्योगिक अधिकरण बीकानेर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-4-91 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 1466.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Bikaner as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Khadi & Village Industries Commission, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on 30-4-1991.

औद्योगिक न्यायाधिकरण, बीकानेर

1. केन्द्रीय औद्योगिक विवाद प्रसंग सं 3/1988

जोनल सैक्रेटरी/सैक्रेटरी, खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन, बाहेती भवन, रानी बाजार, बीकानेर एवं अन्य कर्मचारीगण

—प्रार्थी/यूनियन

बनाम

1. खादी कमीशन जरिये अध्यक्ष, खादी एवं ग्रयोद्योग आयोग, इर्ला रोड विले पार्ले, बम्बई-56

2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, खादी कमीशन इर्ला रोड विले पार्ले बम्बई-56

3. निदेशक, खादी कमीशन इर्ला रोड विले पार्ले बम्बई-56

4. सहायक निदेशक, खादी कमीशन, बाहेती भवन, रानी बाजार, बीकानेर.

विपक्षीगण/नियोजक

2. केन्द्रीय औद्योगिक विवाद प्रसंग सं 1 1089

खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन, बाहेती भवन, रानी बाजार, बीकानेर

—प्रार्थी/यूनियन

बनाम

खादी ग्रामोद्योग आयोग, जरिये इसके मुख्य प्रशासनाधिकारी, खादी ग्रामों आयोग, इर्ला रोड विले पार्ले (प.) बम्बई-56

—विपक्षी/नियोजक

रेफरेन्स धारा 10(1) (घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

उपस्थिति

न्यायाधीश—श्री पी एस शुक्ला, आर एच जे एस.

1. श्री कन्हैया लाल जोशी, अधिकृत प्रतिनिधि कर्मचारी यूनियन की ओर से,

2. श्री विपिनचन्द्र गोयल, अधिवक्ता नियोजक की ओर से

अवार्ड

दिनांक 21 जनवरी, 1991

केन्द्रीय सरकार के श्रम विभाग ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एल. 42011/19/83डी. II(बी) दिनांक 24-2-1984 द्वारा निम्न विवाद निर्णयार्थ प्रेषित किया था ।

"Whether the Khadi and Village Industries Commission, Bombay is justified in discontinuing the Hill and Border Area Allowance to its employee with effect from 1-4-1976 ? If not, to what relief they are entitled ?"

"Whether the Khadi and Village Industries Commission, Bombay is justified in curtailing the facility of supply of 4-shoes and goggles to its employees in Hill and Border Areas ? If not, to what relief the Hill and Border Area Employees are entitled ?"

उपर्युक्त विवाद जयपुर औद्योगिक न्यायाधिकरण में सी. आई. टी. 38/84 पंजीकृत हुआ तत्पश्चात् समसंख्यक आदेश दिनांक 6-11-1987 द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायाधिकरण को दिनांक 23-1-1988 को प्राप्त हुआ ।

2. केन्द्रीय सरकार के श्रम विभाग ने अपनी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 मार्च, 1989 के द्वारा निम्न विवाद निर्णायार्थ इस अधिकरण को प्रेषित किया है :—

"Whether the demand of Khadi Commission Karamchari Union, Bikaner for grant of special compensatory allowance to all the employees recruited and posted to the Hill and Border Area establishment of the Khadi and Village Industries Commission in 1965 and afterwards is justified ? If yes to what relief the concerned employees are entitled to and from what date."

3. ये दोनों ही प्रसंग केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) (घ) सपठित धारा 7-ए के अन्तर्गत विनिश्चय हेतु प्रेषित किये गये है । किन्तु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 31-1-90 के द्वारा यह उपयुक्त पाया गया कि इन दोनों प्रसंगों को समेकित किया जाए क्योंकि इनके अन्तर्गत चाहे गये अनुतोष की प्रकृति एक ही जैसी है । जिससे प्रसंग सं. 1/89 को 3/88 के अन्तर्गत समेकित किया गया ।

इन दोनों प्रसंगों के अन्तर्गत प्रार्थी यूनियन द्वारा यह क्लेम प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी के स्थाई आदेश सं. 422 दिनांक 30-1-64 के द्वारा खादी कमीशन के हिल और बोर्डर एरिया में कार्यरत कर्मचारियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि के बराबर विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता दिलाया जाता था । किन्तु, तह भत्ता आदेश सं० 11/32 दिनांक 27-4-76 के द्वारा दिया जाना बन्द कर दिया गया । यह वर्णित करते हुए कि पहाड़ी और सीमान्त क्षेत्र में विषम भौगोलिक स्थिति है, जिससे अपेक्षाकृत कठोर क्षेत्र में कठिनाईपूर्ण कार्य किया जाना दृष्टिगत रखते हुए आदेश सं. 422 के द्वारा यह क्षतिपूर्ति भत्ता दिलाया जाता था । किन्तु, इस सुविधा को धारा 9-ए (बी) की पालना किए बिना अर्थात बिना किसी नोटिस दिये यह भत्ता बन्द कर दिया गया, जो अनुचित है । यह भी वर्णित किया गया कि यद्यपि यह भत्ता कुछ शर्तों के साथ दिया जाना आदिष्ट किया गया था किन्तु उन शर्तों पर कोई ध्यान न देकर भारत भर के पहाड़ी व सीमान्त क्षेत्र में कार्यरत सभी कार्यकर्ताओं को यह भत्ता दिया जाने लगा, किन्तु, बाद में बन्द कर दिया गया । फलस्वरूप यह प्रार्थना की गई कि सभी कार्यकर्ताओं को इस क्षेत्र में विशेष नियुक्ति की तारीख पर विचार किए यह भत्ता आदेश सं. 422 के द्वारा निरन्तर दिया जाना चाहिये । यह भी पक्ष रखा गया कि विपक्षी ने अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये दो साल में एक चश्मा और प्रत्येक साल में एक जोड़ी रेगीस्तानी जूते देना स्वीकार किया था किन्तु बाद में बिना नोटिस दिए इन सुविधाओं में कमी करके पूरे सेवाकाल में एक चश्मा मूल्य 32 रुपए और दो साल में एक जोड़ी जूता मूल्य 60- रु. दिया जाना आदिष्ट किया गया जो कार्यवाही न केवल स्वेच्छाचारी है अपितु बिना न्यायसंगत और बिना मस्तिष्क लगाए विधि एवं नियमों के विरुद्ध की गई है । फलस्वरूप यह भी प्रार्थना की गई कि रेगिस्तानी कार्यकर्ताओं को एक वर्ष में एक जोड़ी जूता मूल्य 200 रु. और प्रत्येक दो वर्ष में एक चश्मा मूल्य 60 रु. दिलाया जाय ।

5. विपक्षीगण की ओर से कुछ प्रारंभिक आपत्तियां उठाई गई कि विपक्षीगण का कार्य एक स्वायतशाक्षी संगठन के रूप में केन्द्रीय सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विकास के लिए किया जाने वाला कार्य है जो भारत सरकार द्वारा घोषित बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी समाविष्ट है । इस प्रकार यह पक्ष रखा गया कि विपक्षी कोई औद्योगिक संस्थान नहीं है अपितु, वह भारत सरकार द्वारा संचालित स्वायत्त शासी संगठन है और यह भी कि प्रार्थी यूनियन की ओर से ऐसा विवाद उठाने के लिए अधिकृत भी नहीं है । यह भी पक्ष रखा गया कि 1976 में समाप्त की गई सुविधा का विवाद 1984 में उठाना विलंबित है और पुनः यह भी पक्ष रखा गया कि कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के समान अन्य सुविधाएँ दी जाती है जिनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है । विपक्षीगण ने यह तो स्वीकार किया कि आदेश सं. 422 के द्वारा क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाता था और 1-4-76 से ऐसा भत्ता बन्द कर दिया गया । किन्तु, यह पक्ष रखा कि इस सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9-ए प्रभावशील नहीं होती है क्योंकि विपक्षीगण के कर्मचारी भारत सरकार के कर्मचारियों पर लागू फण्डामेंण्टल एण्ड सप्लीमण्टरी रुल्स

से शामित होते हैं। चश्मा और जूते दिये जाने की सुविधा का तथ्य भी स्वीकारा गया है किन्तु यह पक्ष रखा गया कि सुविधा अभी भी कुछ शर्तों के साथ चालू है और ऐसे मामले में धारा 9-ए. या अन्य किसी धारा के अन्तर्गत नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं थी। विपक्षीगण का यह पक्ष है कि जब योग्य कार्यकर्ताओं की हिल एवं बोर्डर एरिया में कमी महसूस की गई तो योग्य कर्मचारियों को कार्य पर रख जाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप ऐसे कर्मचारियों को जो अन्य क्षेत्रों स्थानान्तरित होकर पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य करने को इच्छुक थे, उन्हें तीन अग्रिम वेतन वृद्धि दिया जाना आदेश सं. 422 के द्वारा स्वीकार किया गया था किन्तु यह विचारित करते हुए कि ऐसा आदेश भारत सरकार के अन्य कर्मचारियों और खादी कमीशन के कर्मचारियों में मतभेद पैदा करेगा जिससे 6-9-65 के पश्चात् पदस्थापित कर्मचारियों को उक्त सुविधा स्वीकार नहीं की गई और 1-4-1976 से आदेश सं. 1112 दि. 27-4-76 के द्वारा यह सुविधा बन्द कर दी गई।

6. उपर्युक्त प्रसंगों के अन्तर्गत फलस्वरूप विचारणीय बिन्दु मात्र निम्न हैं :—

1. क्या विपक्षी औद्योगिक संस्थान नहीं है जिसमें यह प्रसंग चल सकने योग्य नहीं है ?

2. क्या विपक्षीगण का अपने कर्मचारियों को हिल एण्ड बोर्डर एरिया भत्ता दिनांक 1-4-76 से दिया जाना बन्द किए जाने का आदेश उचित है ?

3. क्या विपक्षीगण के सभी कर्मचारियों को जो 1965 या पश्चात् हिल एण्ड बोर्डर एरिया में पदस्थापित हुए, को ऐसा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है ?

4. क्या विपक्षीगण द्वारा अपने कर्मचारियों को जूते एवं चश्मे की सुविधा में कमी किया जाना उपयुक्त है ?

5. क्या प्रार्थी द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत किया गया यह क्लेम दूषित है ?

6. प्रतिकार ?

7. उपयुक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत प्रार्थी की ओर से श्री के. एल. जोशी डब्लू. डब्लू. 1 साक्षी-गृह में प्रस्तुत हुआ है जबकि विपक्षीगण की ओर से श्री वेदप्रकाश आर्य एम. डब्लू. 1 साक्षी-गृह में प्रस्तुत हुआ है। उपर्युक्त साक्ष्यावलोकन, पत्रावली का अवलोकन तथा प्रार्थी प्रतिनिधि एवं विपक्षी अभिभाषक के तर्क श्रवण के पश्चात् प्रत्येक बिन्दु पर मेरे विचारित निष्कर्ष निम्न है :—

बिन्दु सं. 1

8. विपक्षी का यह पक्ष है कि केन्द्रीय सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग कमीशन एक स्वायतशाक्षी संगठन है जिसका प्रमुख कार्य खादी व ग्रामोद्योग का प्रसार व विकास है और इस प्रकार यह कोई औद्योगिक संस्थान नहीं है। यह भी पक्ष रखा गया कि वास्तव में भारत सरकार द्वारा ही आयोग का गठन किया जाता है और इस आयोग के अधिकारी भी भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, जिससे, यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक स्वायतशासी संगठन है, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। पुनः यह भी पक्ष रखा गया कि इस विवाद को उठाने हेतु कोई ट्रेड यूनियन नहीं है और प्रार्थी यूनियन अधिकृत भी नहीं है कि ऐसा विवाद उठाए।

9. विपक्षी संस्थान "उद्योग" है अथवा नहीं, यह विवाद तो बंगलौर वाटर सप्लाई एण्ड सिवेरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा 1978 (सुप्रीम कोर्ट) 2 एस.सी.सी. 213 के द्वारा अन्तिम रूप से अभिनिर्णित हो चुका है। इस निर्णय के अनुसार जहां किसी भी विभाग में नियमित प्रक्रिया के अनुरूप कर्मकार व नियोजक के मध्य सहयोग के आधार पर कोई कार्य किया जाता है अथवा उत्पादन और वितरण का कार्य किया जाता है तो ऐसा कार्य "उद्योग" की परिधि में आता है। यह स्वीकृत स्थिति है कि विपक्षीगण खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास के कार्य में लगे हुए हैं, जो इस कार्य में सहायता के लिये कर्मचारी नियुक्त करते हैं और विभिन्न केन्द्रों पर ग्रामोद्योग में उत्पादित माल तथा औजार का भण्डारण, कम दर पर माल की आपूर्ति, ग्रामोद्योग उत्पादन में शुद्धता के विनिश्चय आदि कार्यों में रत है। फलस्वरूप विपक्षीगण एक नियमित प्रक्रिया के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों के सहयोग से ऐसा उत्पादन व वितरण का कार्य करते हैं जो स्पष्ट रूप से उन्हें "उद्योग" के अन्तर्गत ला देता है। 1983 (2) एस.सी.सी. 4 गोपालजी झा शास्त्री बनाम बिहार संघ में भी बिहार आदी ग्रामोद्योग संघ को भी उद्योग माना गया था। ऐसी स्थिति में यह प्रकट है कि उपर्युक्त विशलेषण के अन्तर्गत उठाये गये बिन्दुओं को विपक्षीगण विचलित नहीं कर पाये। विपक्षीगण के अभिभावक के तर्क है कि आयोग केवल स्वायतशाषी संगठन है, मात्र इसके आधार पर ही यह स्थापित नहीं होता कि यह "औद्योगिक संस्थान" नहीं है। जहां विपक्षीगण नियमित प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्पादन व वितरण का कार्य अपने कर्मचारियों के सहयोग से कर रहा है तो वे उपर्युक्त विनिश्चियों के आधार पर स्पष्ट रूप से उद्योग की परिधि में आते हैं और इस प्रकार विपक्षीगण एक औद्योगिक संस्थान है।

10. इस प्रकरण में ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन ट्रेड यूनियन नहीं है अथवा ऐसी यूनियन प्रसंग के अन्तर्गत विवाद उठाने के लिये सक्षम नहीं है। श्री के. एल. जोशी ने अपने कथनों में यह बताया है कि खादी कमीशन से मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय स्तर की एक मात्र यूनियन खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन है और इस तथ्य को सफलतापूर्वक विफल्लित नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट होता है कि प्रार्थी खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन ऐसा विवाद उठाने के लिए सक्षम भी है। परिणाम यह है कि यह बिन्दु विपक्षीगण के

विरुद्ध और प्रार्थी के पक्ष में अभिनिर्णित किया जाता है कि विपक्षी "औद्योगिक संस्थान" है और प्रार्थी कर्मचारी यूनियन और नियोजक के बीच उठे विवाद का विनिश्चयन किया जा सकता है ।

बिन्दु सं० 2 व 3

11. यद्यपि ये दोनों बिन्दु पृथक-पृथक प्रसंग के अन्तर्गत है किन्तु इनके अन्तर्गत विचारणीय तथ्य केवल मात्र यह है कि क्या विपक्षीगण के कर्मचारी हिल एवं बोर्डर एरिया भत्ता प्राप्त कर सकने के अधिकारी हैं। यह स्वीकृत स्थिति है कि आदेश सं. 422 के द्वारा ऐसा भत्ता प्रदान किया जाना आदिष्ट किया गया था । सुविधा के लिए आदेश सं. 422 को उद्धृत किया जाना उपयुक्त है :—

STANDING ORDER No. 422

"The Commission has considered the question of granting some financial relief to the staff posted in the Hill and Border Area consequent on the intensive developmental work taken up by the Commission in these areas. It has been decided that the following benefits should be extended to the officers and staff of the commission posted in the Hill and Border Area of the places mentioned in para (2) below—

(i) The Officers and staff who are posted to the Hill and Border Areas from outside areas will be given special compensatory allowance equal to 3 advance increment subject to a minimum of Rs. 10 p.m. This special compensatory allowance will be paid to them from the date of their posting in the Hill and Border Areas and will be withdrawn when the officers and staff are transferred to areas outside the Hill and Border Areas. The term 'from ouside areas' should be taken to mean 'from areas outside the district in the Hill and Border Areas to which they are posted.

(ii) The special compensatory allowance mentioned above would be paid on furnishing an undertaking to the effect that they would be agree to serve in those areas for a minimum period of 2 years unless transferred elsewhere in the interest of Commission's work.

(iii) In addition to the special compensatory allowance indicated above, officers and staff in the Hill and Border Areas will also be entitled to the grant of special allowance it may be applicable to the Central Government employees located at the different places in those areas. As regards special allowances admissible at Tripura orders have been issued under S.O. No. 315 dated 18-6-63.

These orders will apply in the case of Commission's employees in the Hill and Border areas of the following places :—

(i) Kashmir
(ii) Himachal Pradesh
(iii) Punjab
(iv) Uttarakhand division
(v) Tripura and Manipur
(vi) Rajasthan
(vii) Gujarat.

This issues with the concurrence of the Financial adviser to the Commission.'

यह स्थिति भी विवादित नहीं है कि आदेश सं. 1112 के द्वारा उक्त सुविधायें समस्त कर्मचारियों को दिनांक 1-4-76 से देना बन्द करदी गई । यह स्थिति भी विवादित नहीं है कि दिनांक 6-7-65 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों को यह सुविधा स्वीकार नहीं की गई थी और तत्पश्चात् 1-4-76 से यह भत्ता बन्द कर दिया गया । ऐसी स्थिति में आदेश सं. 1112 का अवलोकन किया जाना अभिष्ट है :—

STANDING ORDER NO. 1112

'Refence is invited to Standing Order No. 422 dated 30-1-64 and the Director (HBA)'s Circular letter No. HBA/Gen/16-3 dated 5-8-71 according to which the Commission's employee posted in the specified areas in Hill and Border areas before 6-9-65 were permitted to continue to draw the aforesaid allowance. The question of continuing the said allowance was reviewed by the Commission in their meeting held on 24-3-76 and decided to discontinue the said allowance in future. However, wherever it was sanctioned and drawn at present, the same shall be adjusted against the increment earned on 1-4-76 on immediately after 1-4-76, and thereafter when the employee earns his subsequent two increments, and shall be fully absorbed within a span of 3 year's time. During the interim period from 1-4-76 till it is fully adjusted against the increments the said concession shall be termed as 'Personal allowance.'

विपक्षीगण के अभिभावक का यह तर्क है कि भारत सरकार के कर्मचारियों और कमीशन के कर्मचारियों के वेतनमान व अन्य सुविधाओं में एक रूपता लाने के लिए ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है । उनका कहना है कि आदेश सं. 422 के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाली सुविधा अनुमोदन हेतु भारत सरकार को अग्रेषित की गई । किन्तु, सरकार द्वारा यह आपत्ति उठाई गई कि ऐसा निर्णय भारत सरकार के कर्मचारियों और कमीशन के कर्मचारियों में मतभेद पैदा करेगी जिससे 6-9-65 के पश्चात् पदस्थापित कर्मचारियों को उक्त सुविधा स्वीकार नहीं की गई और 1-4-1976 से समस्त कर्मचारियों को यह सुविधा देना बन्द कर दी गई। इस मामले में प्रार्थी प्रतिनिधि का सीधा सा पक्ष यह है कि यह भत्ता आदेश सं. 422 के द्वारा प्रदान की जी रही थी अधिनियम की धारा-9 ए. के अन्तर्गत बिना नोटिस दिये यह भत्ता बन्द किया गया है, अनुचित है । विपक्षीगण ने यह पक्ष रखा है कि धारा-9-ए. के अन्तर्ग नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं था क्योंकि विपक्षीगण के कर्मचारी भारत सरकार के कर्मचारियों पर लागू फण्डामेण्टल एण्ड सप्लीमेण्टरी रूल्स से शामिल होते हैं।

17. किन्तु यह स्वीकृत स्थिति है कि विपक्षीगण की ओर से धारा 9-ए. के अन्तर्गत कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया है । उनका तो यह तर्क है कि धारा 9-ए. इस मामले में प्रभावशील ही नहीं है । फलस्वरूप यह विचारित किया जाना आवश्यक है कि क्या इस प्रकरण में धारा 9-ए, का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।

18. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 9-ए. यह प्रावधित करती है कि जहां कोई नियोजक अपने कर्मकारों की सेवाशर्तों में परिवर्तन प्रस्तावित करें तो चतुर्थ अनुसूची में वर्णित ऐसे मामलों में परिवर्तन से पूर्व 21 दिवस का नोटिस दिये जाने के उपरान्त ही ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है । नोटिस दिये जाने की प्रक्रिया औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 के नियम 34 के अन्तर्गत वर्णित

की गई है जिसमें यह अपेक्षा है कि सेवा शर्तों में ऐसा प्रस्तावित परिवर्तन का नोटिस फार्म "ई" में दिया जायेगा और उसको किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा। फार्म "ई" यह भी प्रावधित करता है कि सेवा शर्तों में परिवर्तन का नोटिस यूनियन के साथ-साथ सहायक श्रम आयुक्त, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त और मुख्य श्रम आयुक्त को भी भेजा जाना अपेक्षित है। जैसा, ऊपर उल्लेख किया गया है कि स्वीकृत स्थिति है कि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई नोटिस किसी भी पक्ष को नहीं प्रदान किया गया है।

14. अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ यह प्रावधित करती है कि इन मामलों में जो कि सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जाने के पूर्व नोटिस दिया जाना अपेक्षित है, उसमें खण्ड सं. 3 यह प्रावधित करता है कि क्षतिपूर्ति व अन्य भत्तों के मामलों में परिवर्तन हेतु नोटिस दिया जाना अपेक्षित है। यह स्थिति अत्यन्त स्पष्ट है कि आदेश सं. 422 के द्वारा विपक्षीगण ने हिल एण्ड बोर्डर एरिया में क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाना स्वीकार किया था। अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ के खंड 3 की परिधि में क्षतिपूर्ति का यह भत्ता स्पष्ट रूप से आता है। दूसरे शब्दों में, ऐसी क्षतिपूर्ति का भत्ता सेवा शर्तों का एक भाग है और यदि ऐसे भत्ते में परिवर्तन किया जाता है तो उसका स्पष्ट आशय है कि सेवा शर्तों में परिवर्तन किया गया है, जिससे परिवर्तन से पूर्व नोटिस दिया जाना अपेक्षित है। जिसके फलस्वरूप इस प्रकरण में अर्थात क्षतिपूर्ति भत्ते के परिवर्तन के मामले में धारा 9-ए एवं नियम 34 तथा फार्म "ई" के प्रावधान प्रभावशील हो जाते हैं।

15. यह संभव है कि विपक्षीगण के कर्मचारियों पर प्रशासनिक मामलों में फण्डामेण्टल एण्ड सप्लीमेण्टरी रूल्स प्रभावशील होते हों किन्तु जहां, नियोजक तथा कर्मकारों के मध्य किसी औद्योगिक विवाद का मामला हो तो वहां स्पष्ट रूप से धारा 9-ए भी प्रभावशील हो जाती है जिसके फलस्वरूप धारा 9-ए की अनुपालना किये बिना चतुर्थ अनुसूची में वर्णित किसी मामले में, किसी सेवा शर्त में परिवर्तन किया जाना उपयुक्त नहीं है। विपक्षी अभिभावक यह संतुष्ट करने में नितान्त असमर्थ रहे हैं कि इस मामले में धारा 9-ए प्रभावशील नहीं रहती है। अनुसूची चतुर्थ के खण्ड (3) में स्पष्ट किया गया है कि क्षतिपूर्ति भत्ता भी ऐसी सेवाशर्तों का एक भाग है और इसमें परिवर्तन के पूर्व धारा 9-ए के अंतर्गत नोटिस दिया जाना अपेक्षित है।

16. इस विवाद में दो भाग है, प्रथम तो यह कि समस्त कर्मचारियों को यह भत्ता 1-4-1976 से दिया जाना बन्द कर दिया गया जबकि इसके पूर्व दि. 6-9-65 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जा रहा था। और दूसरे विवाद में यह पक्ष है कि सभी कर्मचारियों को जो 1965 के पश्चात् नियुक्त व पदस्थापित हुए, यह भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। जहां तक, प्रथम विवाद का प्रश्न है यह तो ऊपर किए गये विश्लेषण से निर्धारित हो चुका है अर्थात् कर्मचारियों को आदेश सं. 422 के द्वारा भत्ता प्रदान किया जा रहा था तो उसे बिना नोटिस दिये 1-4-76 से बन्द किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार यह भी प्रकट है कि आदेश संख्या 422 के द्वारा भत्ता कुछ शर्तों के अधीन दिया जा रहा था। आदेश सं. 422 को ऊपर उद्धृत किया गया है, इसका सीधा आशय यह था कि उन कर्मचारियों को जो हिल एण्ड बोर्डर एरिया से बाहर से इस क्षेत्र में कार्य करने के लिये पदस्थापित होने ही उनको प्रेरणास्वरूप यह भत्ता प्रदान किया जाय। किन्तु, आदेश संख्या 1112 के द्वारा यह आदिष्ट किया गया कि जो कर्मचारी 6-9-65 से पहले इस क्षेत्र में पदस्थापित हुए उन्हें यह भत्ता प्रदान किया जाय। किन्तु 6-9-65 की तिथि का वर्गीकरण आदेश सं. 422 के अन्तर्गत नहीं है। विपक्षीगण के अभिभावक किसी भी प्रकार यह स्पष्ट नहीं कर सके कि 6-9-65 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को भत्ता दिये जाने का आदेश किस आधार पर विचारित किया गया। फलस्वरूप यह तिथि कोई महत्व नहीं रखती। अब स्थिति यह प्रकट होती है कि जिन कर्मचारियों को आदेश सं. 422 के द्वारा भत्ता दिया जा रहा था उन सभी कर्मचारियों को दिनांक 1-4-1976 से भत्ता दिया जाना आदेश सं. 1112 के द्वारा बन्द कर दिया गया। उपर किये गये विश्लेषण से यह सुनिश्चित ठहराया है कि भत्ता दिया जाना एक सेवाशर्त है जो अनुसूची चतुर्थ के चरण सं. 3 के अन्तर्गत है और ऐसी सेवा शर्त में परिवर्तन बिना नोटिस के नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप जहां यह स्वीकृत स्थिति है कि विपक्षीगण द्वारा कोई नोटिस धारा 9-ए अथवा नियम 34 अथवा फार्म "ई" की पालना में नहीं दिया गया है तो सेवा शर्तों में ऐसा परिवर्तन अर्थात क्षतिपूर्ति भत्ता दिये जाने की सुविधा में परिवर्तन विपक्षीगण द्वारा नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप सभी कर्मचारियों को जिन्हें आदेश सं. 422 के अन्तर्गत ऐसा क्षतिपूर्ति भत्ता प्रदान किया जाना योग्य है उनहें आदेश सं. 422 के अन्तर्गत वर्णित शर्तों के अधीन ऐसा भत्ता दिया जाना उपयुक्त है क्योंकि ऐसा भत्ता बिना वैधानिक नोटिस दिये बन्द किया जाना अनुपयुक्त है। फलस्वरूप ये दोनों ही बिन्दु उपर्युक्त प्रकार से अभिनिर्णीत किये जाते हैं।

बिन्दु संख्या-4

17. प्रार्थी यूनियन का यह पक्ष है कि विपक्षी कमीशन द्वारा अपने कर्मचारियों को रेगिस्तान में पड़ने वाली भयंकर गर्मी और आन्धियों एवं इस क्षेत्र में पाये जाने वाले सांप और अन्य जहरीले जानवरों से रक्षा के लिये दो साल में एक चश्मा और प्रत्येक वर्ष में एक जोड़ी रेगिस्तानी जूता दिया जाना स्वीकृत किया गया था। किन्तु, बाद में इस सुविधा को घटाकर सेवा काल में 32 रु. का एक चश्मा और दो वर्ष में एक जोड़ी जूता की सुविधा तक सीमित कर दिया गया। उनका यह तर्क है कि सुविधा में कटौती भी सेवाशर्तों में परिवर्तन स्वरूप है, जिससे बिना नोटिस ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता था।

18. किन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ वे मामले वर्णित करती है जो सेवाशर्तें स्वरूप हैं, जिनमें परिवर्तन के लिए नोटिस की अपेक्षा है । चश्मा और जूतों जैसी सुविधा में कटौती इस अनुसूची की परिधि में नहीं आती है । अनुसूचि चतुर्थ के खण्ड (8) में प्रथागत रियायत या विशेषाधिकार या प्रथागत उपयोग में परिवर्तन से वापिस लिया जाना वर्णित है । दूसरे शब्दों में, कोई प्रथागत रियायत या विशेषाधिकार किसी को प्रदान किए जा रहे हैं तो उसे वापिस लिया जाना अथवा प्रथागत उपयोग को वापिस लिए जाने को परिवर्तन की परिधि में माना गया है। प्रथम तो यह खण्ड (8) सुविधा को वापिस लिए जाने से सम्बन्धित है, सुविधा में कमी किए जाने से नहीं । मेरे समक्ष लंम्बित मामले में चश्में और जूतों की सुविधा को वापिस नहीं लिया गया है । अपितु, उसमें सुविधानुसार कमी की गई है । ऐसी स्थिति में खण्ड (8) सरसरी तौर पर सुविधा में कमी के मामलों में प्रभावशील नहीं होता है क्योंकि यह मामला सुविधा को वापिस लिए जाने का नहीं है । इसके अतिरिक्त चश्में और जूते की सुविधा कोई प्रथागत रियायत या विशेषाधिकार नहीं है । यह सुविधा तो रेगिस्तानी क्षेत्र की परिस्थितियों में कार्य करने के सम्बन्ध में प्रदान की जाने वाली सुविधा है और यह किसी भी प्रकार प्रथागत रियायत या विशेषाधिकार की परिधि (Customary Concession or Privilege) में नहीं आती है । अन्त में चश्मा और जूते की यह सुविधा प्रथागत उपयोग (Change in uses) की परिधि के अन्तर्गत भी नहीं आती है । चश्मा और जूते शारीरिक रक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं जो किसी भी प्रकार प्रथागत उपयोग में परिवर्तन के रूप में नहीं है । ऐसी सुविधा में कमी किया जाना किसी भी प्रकार प्रथागत उपयोग में परिवर्तन के रूप में स्वीकार किए जाने हेतु प्रार्थी अपना पक्ष सफलतापूर्वक नहीं रख सका है । वास्तव में, यह ऐसी सुविधा है जो अनुसूची चतुर्थ की परिधि के अन्तर्गत ही नहीं आती जिससे भी ऐसी सुविधा में परिवर्तन के लिए नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है । किसी भी स्थिति में खण्ड (8) तो सुविधा को वापिस लिए जाने से सम्बन्धित है जबकि मेरे समक्ष मामले में तो चश्में और जूतों की सुविधा में कमी की गई है जो किसी भी प्रकार अनुसूची चतुर्थ की परिधि में नहीं आती है और न किसी भी प्रकार ऐसे मामले में धारा 9-ए के प्रावधान प्रभावशील होने ही प्रकट है । फलस्वरूप चश्में और जूतों की सुविधा में कमी के मामले में औद्योगिक विवाद अधि-नियम की अनुसूची चतुर्थ के प्रभावशील न होने से यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी सुविधा में परिवर्तन के पूर्व विपक्षीगण से यह अपेक्षा थी कि धारा 9-ए के अन्तर्गत नोटिस प्रदान किया जाता। फलस्वरूप विपक्षीगण का इस सुविधा में कमी किए जाने का कार्य अनुचित नहीं है । यह बिन्दु इसी प्रकार अधिनिर्णित किया जाता है ।

बिन्दु संख्या -5

19. विपक्षीगण का यह तर्क है कि यह सुविधा 1976 में समाप्त की गई थी, जिनका विवाद 1984 में उठाने का कोई औचित्य नहीं है जिससे यह क्लेम विलंबित है । इस सम्बन्ध में यद्यपि स्पष्ट साक्ष्य प्रदान नहीं की गई है किन्तु पत्रावली में संलग्न पत्रों से यह प्रकट है कि 1984 में यह प्रसंग प्रेषित किए जाने के पहले भी यह मामला पक्षकारों के मध्य उठता रहा और इसमें समझौता वार्ता भी चली है। विपक्षी के पदाधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर इन सुविधाओं के सम्बन्ध में पत्र लिखे गए हैं । तब किसी भी प्रकार यह कल्पना उपयुक्त नहीं है कि विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण प्रार्थी का पक्ष चल सकने योग्य नहीं है मात्र विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने से ही प्रार्थी यूनियन के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते यदि वे अन्य प्रकार से स्वीकार किए जाने योग्य हों । विपक्षी अभिभावक ऐसा कुछ भी स्पष्ट कर सकने में असमर्थ रहे हैं कि केवल कुछ समय के विलम्ब से प्रस्तुत क्लेम के आधार पर प्रार्थी यूनियन किसी प्रतिकार को प्राप्त करने के अयोग्य है । प्रार्थी की साक्ष्य में यह बताया गया है कि विपक्षीगण को उसने कई अभ्यावेदन भेजे और बाद में केन्द्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से कमीशन के उच्चाधिकारियों को निवेदन कराए किन्तु कोई उपयुक्त उत्तर न मिलने पर केन्द्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर विवाद श्रम विभाग को सौंपना पड़ा और यह भी वर्णित किया गया कि केन्द्रीय कार्यकारिणी के महामंत्री ने दिनांक 2-1-82 को पत्र के द्वारा प्रार्थी को अधिकृत भी किया । प्रार्थी ने यह भी साक्ष्य प्रदान किया है कि उसने 27-7-82 को सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) अजमेर को भी पत्र लिखा था । ऐसी स्थिति में प्रकट है कि प्रार्थी यूनियन निरन्तर इस विवाद को विभिन्न प्रकार से उठाती रही है और यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी का क्लेम विलंबित है और इस आधार पर अस्वीकार किए जाने योग्य है । फलस्वरूप यह बिन्दु भी विपक्षी के विरुद्ध अभिनिर्णित किया जाता है ।

बिन्दु सं 6 प्रतिकार

20. उपर्युक्त विश्लेषण एवं निष्कर्ष के फलस्वरूप यह प्रकट है कि विपक्षी एक औद्योगिक संस्थान है और पक्षकारों के मध्य उठे इन विवादों का इन प्रसंगों के अन्तर्गत अधिकरण द्वारा निपटारा किया जा सकता है । यह भी अभिनिर्णीत ठहरा है कि खादी कमीशन से कर्मचारी हिल एण्ड बोर्डर एरिया भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी है और उनकी यह सुविधा समाप्त किया जाना अनुचित है क्योंकि ऐसी सुविधा समाप्त किए जाने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया । तथा चश्में और जूते की सुविधा में कमी किए जाने का कोई अनौचित्य प्रकट नहीं हुआ है ।

आज्ञा:—

21. फलस्वरूप प्रसंग सं 3/88 और 1/89 के अंतर्गत समेकित विनिश्चय के आधार पर निम्न प्रकार पंचाट पारित किया जाता है :—

1. विपक्षीगण द्वारा दिनांक 1-4-1976 से अपने कर्म-चारियों को हिल एण्ड बोर्डर एरिया भत्ता स्थाई आदेश सं 1112 के द्वारा बन्द किया जाना उपयुक्त नहीं है ।

2 विपक्षीगण द्वारा हिल एण्ड बोर्डर एरिया क्षेत्र में 1965 व पश्चात नियुक्त और पदस्थापित कर्मचारियों को स्थाई आदेश सं 422 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाना उचित है ।

3. विपक्षीगण के कर्मचारी स्थाई आदेश सं 422 की अनुपालना में उसमें वर्णित शर्तों के अधीन हिल और बोर्डर एरिया में कार्य करने के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है ।

4. विपक्षीगण द्वारा हिल और बोर्डर एरिया में अपने कर्मचारियों को जूते और चप्पा प्रदान किए जाने की सुविधा में कटौती किया जाना अनुचित नहीं है और प्रार्थी किसी प्रतिकार को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है ।

उपर्युक्त पंचाट प्रकाशनार्थ केन्द्रीय सरकार को भेजा जाए ।

22. आज्ञा आज दिनांक 21-1-91 को मेरे इजलास लिखाई व सुनाई गई ।

पी. एस. शुक्ला, न्यायाधीश ।

[सं. एल —42011/19/83—डी-2(बी) (भाग)]

का. आ. 1467.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उप-मण्डल अधिकारी (फोन्स) आगरा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-4-91 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 1467.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SDO (Phones) Agra and their workmen, which was received by the Central Government on 30-4-91.

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 245 of 1989

In the matter of dispute between :

Shri Devendra Kumar
15/252 Murli Nagar
Tajganj, Agra,
282001.

AND

The District Manager
Telecom
Agra.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-40012/59/89-IR(DU) dated 5th October 1989, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:—

Whether Sub-Divisional Officer (Phones) II Agra was justified in terminating the services of Shri Devendra Kumar Sharma son of Shri Prem Narain Sharma w.e.f. 1-2-84? If not, what relief the workman is entitled to ?

2. The workman's case in brief is that he was initially appointed in Coaxial Equipment Cell at Agra which is under the control of Telecom Department, as a casual labour in April 1981, and had worked in the said department for 261 days, during April 1981 to March 1982, 365 days during April 1982 to March 1983, and 49 days during April and May 1983, total 675 days, as per statements annexure 1 and 2. Since his work and conduct were satisfactory, his services were requisitioned by SDO (Phones) II Agra in the month of June 1983, in continuity of service rendered by him in the Coaxial Equipment Cable Cell. He worked as casual labour under SDO (Phones) II Agra for 205 days unto 31-1-84 vide statement annexure 3. His services were terminated w.e.f. 1-2-84 in voilation of the provisions of sections 25F & 25G of the Industrial Disputes Act, 1947. At the time of termination of his services persons junior to him were allowed to continue in service and fresh hands were engaged without making an offer of re-employment to him. He alleges that Coaxial Equipment Cable Cell is one of the two wings of the Telecom Department under the District Manager Telecom Agra. His name was sponsored by the employment exchange and thereafter he was duly selected for appointment. During Conciliation Proceedings the maagement set up the case that he had abondoned the job w.e.f. 1-2-84, as he found a better employment. This is far from the truth. He has, therefore, praved for his reinstatement with full back wages and all consequential benefits.

3. In defence the management plead that Telephone Department is not an industry. According to the management the Coaxial Equipment is a separate unit functions under the administrative control of Chief General Manager, Telecom Lucknow. As such the said authority was not a necessary party to the reference. While admitting the fact that during 1983-1984, the workman has worked as a casual labour for 205 days, the management plead that w.e.f. 1-2-84, the workman himself abondoned the job. According to the the management, since Coaxial Equipment does not function under SDO Phones II, Agra, the management have no means to verify the averments made by the workman regarding his working in coaxial equipment. The fact that the workman made no efforts, to approach the employer for 4 years goes to support the fact that he himself abondoned the job.

4. In his rejoinder the workman has challenged the plea set up by the management that Telephone Department is not an industry. According to him during the period of 4 years after his retrenchment he had been repeatedly agitating the matter of his service with the employer.

5. In support of his case, the workman has filed his own affidavit and he has relied on a number of documents. On the other hand, the management have filed the affidavit of Shri R. S. Agarwal, AE Phones (MM), Agra.

6. From the pleadings of the parties it is clear that there is no dispute about the fact that the workman had worked for 205 days under SDO Phones II Agra between June 1983 and 31st January, 1984. The following three points arises for determination in the instant case.

1. Whether the Telecom Department is an Industry?
2. Whether the District Manager, Telecom and Coxaial Equipment Cable Cell are bodies independant of each other, and
3. Whether the workman's services were requisitioned by the SDO Phones II Agra as alleged by the workman?

Point No. 1

7. Although it has been argued by Shri Kushwaha on behalf of the management that Telecom Department is not an industry, I am not prepared to agree with him on it. Such of the employees of the telecom department as are not go-

verned by CCS (Disc. & Appeal), Rules, cannot be said as subject to the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947. The workman was simply a casual labour therefore, so far as he is concerned I hold the Telecom Department as an Industry. Point No. 1 is decided accordingly.

Point No. 2.

8. In his cross examination, the management witness Shri R. S. Agrawal has deposed that Coxaial Wing is not under the District Manager Telecom Agra. According to him Coxaial Wing is one of the wings of Telecom department. There is a bifurcation of these two wings at the Director of Telecom New Delhi. He has also deposed that labourers working in one wing are not subject to transfer to another wing. Even class III employees of one wing are not subject to transfer to another wing. Rarely a class III employee from one wing may be sent on deputation to another wing. He has denied the suggestion that DMT Agra, is also the incharge of Coaxial Wing. There is no evidence from the side of the workman to controvert the facts stated by Shri R. S. Agrawal. All that has been alleged in the claim statement is that Coxaial Equipment Cable (Store) Cell is one of the two wings of the Telecom Department. It has been also alleged in the claim statement that it is under the control of DMT, which fact as stated above, has been denied by Shri R. S. Agrawal, management witness.

9. Hence despite the fact that the Coxaial Equipment Cable Cell is one of the wings of Telecom Department, the two wings are independent of each other. The point is decided accordingly.

Point No. 3

10. The case set up by the workman is that the services were requisitioned by SDO Phones II Agra. In his cross examination, he has not said about requisitioning of his services but he has said about his transfer which according to him was oral. In view of the statements made by Shri R. S. Agrawal, management witness to which I have referred while dealing with point No. 2, the question of his transfer when he was simply a casual labour, from one wing to another did not arise. I am therefore, not prepared to believe that his services were requisitioned by SDO Phones II Agra or he was transferred from Coaxial Wing to the other wing. The point No. 3 is decided accordingly.

11. Admittedly he had worked for 205 days under SDO Phones II Agra having not worked for one continuous year within the meaning of section 25B I.D. Act, the question of violation of section 25F, Section 25G read with Rule 77 and Sec. 25H read with Rule 78 did not arise. All that I can say is his is an unfortunate case. In fact he ought to have raised the dispute against Coaxial Equipment Cable Cell where he claims to have worked for 675 days, as his working having been of more than 240 days during the last period of 12 months preceding the date of his ceasing to work.

12. So even if it is not a case of abandonment of service by the workman as alleged by the management, the action of the SDO Phones II Agra in terminating his services w.e.f. 1-2-84 cannot be held as unjustified. He is therefore held entiled to no relief.

13. The reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

[No. L-40012/59/89-IR(DU)(Pt)]

का. आ. 1468.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पी एण्ड टी डिपार्टमेंट, अजमेर, के प्रबन्धन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-4-91 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 1468.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of P & T Deptt. Ajmer and their workmen, which was received by the Central Government on 30-4-91.

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPAT SHARMA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI

I.D. No. 109/88

In the matter of dispute between :

Shri Narayan Singh S/o Shri Mohan Singh,
H. No. 255, Jawahar Nagar,
Lohagal Road, Shastri Nagar, Ajmer.

Versus

The Assistant Engineer Carrier,

P & T Department,

C/o Telephone Exchange, Ajmer.

APPEARANCES :

Workman in Person.

Shri S. L. Manik A.E. (S.I.)—for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-40012/4/87-D.II(B) dated 13-10-87 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the Asstt. Engineer Carrier P&T Deptt. Ajmer is justified in terminating the services of Shri Narayan Singh, Daily rated driver w.e.f. 12-12-86? If not, to what relief the concerned workman is entiled to ?"

2. The brief facts of the case are that Narain Singh was appointed as daily wage driver w.e.f. 18-12-85 under AEM/W Ajmer and his services were terminated on 12-12-86 without any notice and was not paid any compensation.

3 In reply the Management alleged that the reference was liable to be dismissed for non-joinder and mis-joinder of necessary party. The petitioner had not come with clean hands. It was admitted that the petitioner was employed on muster roll on 18-12-85 and his services were terminated on 12-12-86 when it was detected that the petitioner has caused a loss of one tin containing 4 litre of mobile oil and has misbehaved his carrier Ajmer. Taking into consideration the act and conduct of the petitioner his services were terminated through due process of law. He was also offered one months salary in lieu of notice which he refused to accept. The order passed was not arbitrary nor against the principle of natural justice.

4. The Management examined Krishan Kumar AE as MW1 while the workman himself appeared as WW1.

5. I have heard representative for the parties and have gone through the record.

6. It has been urged by the representative for the Management that the termination of the services of the workman was fully justified because the petitioner had caused loss of one tin of mobile oil containing 4 litre. He also misbehaved with A.E. Carrier Aimer and for that reason the workman services were dispensed with on 12-12-86 when he was offered a salary of one month he refused to acept. It has been urged that the magement was within its right to dispense with his services because he was a casual labour.

7. The representative for the workman on the other hand had urged that the workman had completed more han 200 days and a notice of one month was absolutely necessary to be given to him before his services could be dispensed with.

Moreover, an allegation against him was made that 4 litre of mobile oil had been stolen by him so regular enquiry should have been placed on the record of this case. Mere offering of one months salary later on would not justify the termination of the workman.

8. From careful perusal of the evidence produced before me I am of the opinion that the workman has admittedly worked for 295 days that means he has completed 240 days. This has been so admitted even by the Management in their written arguments filed in the court. No enquiry had been held against the workman. The report of the enquiry officer if any should have been placed on the record, but from the statement of the management witness it appears that the proper procedure has not been complied with by the Management. The management witness has also admitted that the key of the vehicle used to be delivered to the workman in the morning and he used to deliver it back by 5 P.M. The responsibility of the workman, therefore, could not be fixed regarding the loss of the mobile oil and it was only a presumption of the management that since the mobile oil was found missing and it was supposed to be in the custody of the workman so his responsibility was held. This deposition of the management has no legs to stand upon. Prior notice was not given to him nor any compensation was paid to him. A notification of the P&T department regarding casual daily rated mazdoors in that department runs as follows:

> "In order to implement certain judgments in respect of Casual Mazdoors, the question of issuing a notice of one month or payment of wages in lieu thereof to casual mazdoors whose services are terminated by the Department, has been engaging the attention of this Directorate for some time past. It has now been decided that such of the casual mazdoors who serve the Deptt. for at least a total period of 240 days in a year and whose services are proposed to be terminated by the department shall served a notice of one month before termination of their service or one month wages in lieu thereof be paid to them."

9. Since no notice was given nor the provisions of termination were complied in this case by the management and even proper and sufficient evidence has not been led to justify the action of the Management in this court, I am left with no option but to hold that the action of the Management was not justified in terminating his services I, therefore, order that the workman be reinstated and as regards any other relief I do not find him entitled to because no evidence has been led that he was sitting idle since the date of his termination. Parties are, however, left to bear their own costs.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

[No. L-40012/4/87-D.II(B)(Pt.)]

का. आ. 1469.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकाम, हैदराबाद के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-4-91 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 1469.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom, Hyderabad and their workmen which was received by the Central Government on 30-4-91.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 70 of 1990

Dated : 25th April, 1991

BETWEEN :

The Workmen of Telecom, Hyderabad.

AND

The Management of Telecom, Hyderabad.

APPEARANCES :

None—for the Petitioner—workman.

Sri P. Vithal Rao, Advocate—for the Respondent-Management.

AWARD

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by its Order dt. 30-11-1990 in No. L-40012/31/90-IR(DU) for adjudication of the dispute between the employers in relation to the Management of Telecom, Hyderabad and their workman, setting forth the point for adjudication in the schedule appended thereto as follows :—

> "Whether the action of the Management of M/s. Asstt. Engineer, Gowliguda in retrenching the services of Sri T. Sudhakar, Casual Mazdoor is justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled to ?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 70 of 1990 on the file of this Tribunal, and notices were issued to both the parties. Having received the notices issued by this Tribunal, the Petitioner did not put in appearance and remained exparte. The Respondent put in appearance and later did not file counter though several opportunities were given and remained exparte without any representation and therefore, the Respondent was set exparte.

2. It is clear from the conduct of both parties that they have no interest to prosecute the case and therefore, they did not attend the Tribunal and did not file the claim statement and the counter. As per Rule 22 of the Industrial Disputes (Central) Rules 1957 if without sufficient cause being shown any party to proceeding before this Court fails to attend or to be represented, this Court may proceed, as if the party had duly attended or had been represented. So in view of the said provision in Rule 22 of the I.D. (Central) Rules 1957, this Court proceeded exparte of both the parties and found no material to pass the Award on merits, as both parties did not submit the claim statement and the counter and remained exparte. So in the facts and circumstances of the case, a nil Award is to be passed, in my opinion.

3. In the result, a Nil Award is passed.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 25th day of April, 1991.

G. KRISHNA RAO, Industrial Tribunal

[No. L-40012/31/90-IR(DU)(Pt.)]

का. आ. 1479.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 37 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उप मण्डल अधिकारी (टेलीफोन्स), ऋषिकेश के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-4-91 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 1470.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to

the management of SDO Telephones, Rishikesh and their workmen, which was received by the Central Government on 30-4-91.

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL PANDU NAGAR DEOKI PALACE ROAD KANPUR

Industrial Dispute No. 134 of 1989

IN THE MATTER OF DISPUTE BETWEEN :

Shri Shishu Pal Singh,

House No. 64 Subhash Bankhandi,
Rishikesh,
Dehradun.

AND

Sub Divsional Officer Telephones,
District Dehradaun 248001.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-40012/104/88-D-2(B) dated 24-5-89, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

> Kya Up Mandal Adhikari (Telephones) Rishikesh ka Shri Shishu Pal Singh Mazdoor ko dinank 1-2-88 se sewa mukta karna nyayochit hai ? Yadi Nahi to karam kar kis anutosh ka adhikari hai ?

2. The workman's case in brief is that he was engaged on as a daily rated casual labour in 1986 and his services were terminated illegally w.e.f. 1-2-88 in violation of the provisions of section 25F Industrial Disputes Act. He alleges that he had been paid wages at the rate of Rs. 12.50 paisa per day when he ought to have been paid wages at the rate of Rs. 28.25 per day. He has therefore alleged that the workman prayed for his reinstatement with full back wages.

3. In defence the management plead that the workman has engaged as a daily rated casual labour from September 1986. His services and the services of some other daily rated casual labour were terminated w.e.f. 1-2-88 by means of notice dated 21-12-87. The management admit that during the period of one year before the termination of his services he had worked for more than 240 days. According to the management 15 days wages by way of retrenchment compensation were offered to the workman on 31-1-88, but he refused to accept the same. Therefore, the amount was remitted by means of money order to him on 3-2-88 but the money order was received back as unpaid. In fact he was engaged temporarily for temporary work with the clear understanding that when his services would not be needed his services would be liable to termination.

4. In his rejoinder the workman denies services of notice dated 21-12-87 upon him. He also denies that retrenchment compensation was offered to him on 31-1-88. He further denies that he ever refused to accept the money order remitted to him by the management by means of money order. According to him even retrenchment compensation alleged to have been offered fell short of the requirements under section 25F I.D. Act. His retrenchment compensation amounted to Rs. 847.50 paisa. Then he has denied the receipt of arrears of wages alleged to have been paid to him by the management.

5. In support of his case, the workman has filed his own affidavit and some documents. On the other hand, in support of their case, the management have filed the affidavit of Shri Murari Singh SDO(T) and some documents.

6. In his claim statement and rejoinder the workman has not specifically stated as to in which month of 1986 he was engaged as daily rated casual labour. In para 3 of his affidavit he has admitted that he was engaged in September 1986.

7. Ext. W.1 is the copy of certificate dt. 18-7-88 showing the number of his working days. The document has been admitted by the management. From this certificate it appears that in the month of September 1986, he had worked for 30 days. Thus it stands proved that he was engaged as daily rated casual labour w.e.f. 1-9-86.

8. It is the admitted case of the parties that the services of the workman were retrenched w.e.f. 1-2-88. The workman has alleged violation of section 25F in his claim statement and voilation of section 25N in his rejoinder. No argument has been advanced from the side of the workman by his authorised representative on the alleged violation of section 25N Industrial Disputes Act. For the purposes of examining the plea of voilation of the provisions of section 25F I.D. Act, we will have to consider two things. Firstly we have to see whether the workman was given one month's notice and secondly, we have to see whether he was offered retrenchment compensation in terms of section 25F I.D. Act.

9. The management have filed photostat copy of notice dt. 21-12-87 with the written statement as well as with the affidavit of the management witness. During his cross examination the workman was shown his alleged signatures regarding receipt of notice on the original notice but the workman denied his signatures. He was also confronted with his purported signatures on two statement of the month of June and July 1987-1988. The photostat copies of the same were got filed by the management under the orders of the Tribunal. I have compared the disputed signatures of the workman on the notice with his signatures on his statement dt. 15-1-91 as a witness and the signatures admitted by him as appearing on the two statements and find that the disputed and the admitted signatures are identical. I do not agree with the submissions of Shri O. P. Mathur, the auth. representative for the workman that disputed signatures differ with the admitted signatures. Hence on the first point I hold that the workman was duly served with one month's notice as provided by sec. 25F I.D. Act.

10. On the second point the management have set up the case that on 31-1-88, 15 days wages by way of retrenchment compensation were offered to the workman who refused to accept the same whereupon on 3-2-88, the amount was remitted by money order which was received back as unpaid.

11. The management witness has corroborated it and has filed photostat copy of the certificate given by the postal authorities with regard to remmittance of Rs. 186.75 paisa as retrenchment compensation. Both the facts have been denied by the workman.

12. In view of oath against oath, the question will have to be examined in the light of circumstances. Annexure 4 to the affidavit is the photostat copy of the money order coupen. In the space meant for communication it is written as follows :—

> 15 days wages of Shri Shishu Pal Singh Casual Labour dispensed from the Mustor Roll.

Thus we find that there is no mention of the fact that the amount of retrenchment compensation was being remitted by money order on account of workman's refusal to accept the same on 31-1-88.

13. Ext. W.2 is the copy of letter dt. 4-8-88 from the SDO(T) Rishikesh to the workman. Although in it there is a mention of the fact about giving of notice, there is no mention of the fact that retrenchment compensation was offered to the workman by hand on 31-1-88 and he had refused to accept the same. I therefore find no substance in the plea raised by the management that retrenchment compensation was offered by hand to the workman on 31-1-88. It appears that only after the expiry of the period of notice it was realised by the management that retrenchment compensation had not been paid to the workman.

14. Let us see in the alternative whether the compensation alleged to have been offered was in accordance with the provisions of section 25F I.D. Act. From the rejoinder

it appears that the workman should have been paid one month's wages as retrenchment compensation. But this does not seem to be correct when it is seen in the light of the workman's working days given in the certificate copy Ext. W.1. The certificate shows that during the period 1-9-86 to 31-1-88 he had worked for 502 days only i.e. for a period of less than one year six months. After seeing that Shri O. P. Mathur did not press this point.

15. Lastly, I come to the point whether the workman had been paid wages at the rate of Rs. 12.50 paisa per day or at the rate of Rs. 28.25 per day. With their written statement, the management have filed the copy of statement showing payment of arrears of wages to the workman, the copy of statement is Ext. M.1. Shri O. P. Mathur has waived its formal proof on behalf of the workman. From this statement it appears that the workman was paid arrears amounting to Rs. 7855.10 paisa by way of difference of wages. The statement makes it absolutely clear that the workman had been paid wages at the rate of Rs. 26 per day for the period ending 31-12-86, at the rate of Rs. 27 per day for the period ending 30-6-87 and at the rate of Rs. 28.25 paisa w.e.f. 1-7-87. At the time of arguments Shri Murari Singh SDO(T) produced before the Tribunal copy of Telegram dt. 22-2-85 from the General Manager Telecom Lucknow showing the revised rates of daily wages. After seeing it even Shri O. P. Mathur agreed that the arrears had been paid in accordance. So it stands proved that the workman has been paid his wages at the prescribed rate and nothing is due on this count.

16. Since, his services were terminated in violation of section 25F Industrial Disputes Act the order of termination of his services is held as void ab initio.

17. From the copy of notice dated 21-12-87, it appears that the services of daily rated casual labour engaged after 30-3-85, were terminated because of departmental instructions. There is nothing to show on record as to what kind of these instructions are. Therefore, the workman is entitled to reinstatement.

18. Held that the action of the management in terminating the services of the workman w.e.f. 1-2-88 was neither legal nor justified. The workman is consequently held entitled to reinstatement with full back wages. Since he is getting the relief on account of non compliance of full provisions of section 25F I.D. Act, the period w.e.f. 1-2-88 till the date of his reinstatement will not be counted towards seniority. It will be open to the management to dispensed with his services after making full compliance of the provisions of section 25 Industrial Disputes Act, 1947.

19. Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

[No. L-40012|104|88-D.II(B)(Pt.)]

का. आ. 1471.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे लखनऊ के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-4-91 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 1471.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway, Lucknow and their workmen which was received by the Central Government on 29-4-91.

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR KANPUR

Industrial Dispute No. 195 of 1989

In the matter of dispute between :
The Divisional Secretary,
Uttar Railway Karamchari Union,
96|196 Roshan Bajaj Lane,
Ganesh Ganj, Lucknow.

AND

The Divisional Railway Manager,
Northern Railway,
Hazaratganj Lucknow.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-41011|31|88-D-2(B) dated 16th August, 1989, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Whether the Sr. D.P.O. Northern Railway, Lucknow was justified in not allowing S|Shri Parvez Alam, Ashwani Kumar and Anjani Kumar to appear for selection for the post of Material Clerk in the scale of Rs. 950-1500 without assigning any reason thereof ? If not, what relief these workmen were entitled to ?

2. The industrial dispute on behalf of the above named 3 workmen has been raised by Uttar Railway Karamchari Union (hereinafter referred to as Union).

3. The case of the Union in short is that workman Shri Parvez Alam had been working as a Callman in Locoshed Lucknow. By means of letter no. 220-E|6-I|33½ part II dated 5-1-87 management invited applications for selection of material clerks in the scale of Rs. 950-1500. Such applications were also invited from Callmen|Messenger mentioned at serial no. 9 of the said letter. In persuance of the said letter Shri Parvez Alam and two others applied for their promotions as material clerks. However, without any reason they were excluded from being considered for selection to the post of material clerks. No prior information in this regard was given to them by the management. On 19-7-87, on their application they were told that persons belonging to the categories of callmen were not eligible for promotion to the post of material clerks. The relief has been claimed by the Union only in respect of Shri Parvez Alam. It is prayed that Shri Parvez Alam by being promotion as material clerk and paid arrears of wages w.e.f. January 1987.

4. The management admit that the applications were invited for selection of material clerks vide letter dated 5-1-87 referred to by the Union against 33-1|3% quota from amongst class IV eligible categories. According to the management vide letter No. 961E|122-NARMU|GM|123-E|IIA (Union) dated 4-7-83 messenger boys in C&W Department were made eligible for promotion in ministerial cadre. Due to some misunderstanding vide letter dated 5-1-87 Callmen were treated as Messenger Boys and were made eligible for the post of clerks. However, when it came to notice that Messenger Boys of C&W Department were only eligible for selection for the posts of clerks, by means of letter dated 7-7-87, the three workmen were informed accordingly.

5. The management further plead that S|Shri Parvez Alam and Anjani Kumar were only substitute and consequently they could not apply for the above selection until they had become regular employees in class IV category after proper screening. Further Shri Parvez Alam was removed from service under Rule 14(2) of CCS (D&A) Rules 1968. At present his case is pending before the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench. Next it is pleaded by the management that the alleged Union is not a recognised Union and as such it has got no legal

right to raise the industrial dispute. The management also say that there is no post of Zonal Working Presiding in the alleged Union.

6. In its rejoinder, the Union alleges that there is no distinction between the messenger and the call boy Moreover, without issuing show cause notice, the names of the workmen could not have been scored out from the list of candidates to be considered for selection. The Union admits that Shri Parvez Alam was dismissed under Rule 14(2) of the D&A Rules, 1968. But according to the Union the said order of dismissal was set aside by the Industrial Tribunal by means of its award. Even a writ petition filed by the management has been dismissed against the Divisional President of the Union. The Union further alleges that for the purposes of raising industrial dispute it is not necessary that it has been given recognition by the management.

7. In support of its case the Union has filed the affidavit of Shri Parvez Alam and one document. On the other hand the management in support of their case have simply relied upon documentary evidence.

8. At the outset I may make one thing clear that Union has led evidence only with regard to Shri Parvez Alam totally ignoring the case of the two other workmen, namely, S|Shri Ashwani Kumar and Shri Anjani Kumar. They have not been referred by their names in the claim statement and rejoinder.

9. Ext. M-1 is the copy of letter dated 5-1-87, by means of which applications were invited from persons belonging to 10 categories named in it for selection for the post of material clerks. At serial no. 9 the category referred to is of special messenger/callman. Ext. W.3 is the copy of letter dated 7-7-87 from Divisional Railway Manager Lucknow to Loco Foreman Faizabad informing him that while processing the application it was found that Callmen were not eligible for selection to the post of material clerks. Accordingly he was directed to inform the 4 callmen named in the letter who had applied for their selection to the post of material clerks. Ext. M-4 is the copy of similar letter dated 7-7-87 from DRM Lucknow to Locoforman Lucknow, to inform about it all the three workmen covered by the reference order.

10. A few points have been raised by the Union against the action of the management. The first point raised is that before making them ineligible for promotion to the post of material clerks they should have been given a show cause notice. After giving my anxious consideration to it I find that there was no need for giving any such show cause notice to these workmen. The question is whether by any notification of any rule in existence callmen were eligible or not for being considered for selection to the post of Material clerks. It could be that in the letter dated 5-7-87 a clerical error might have occured. Shri Parvez Alam, who appeared at the time of arguments was unable to invite my attention to any such rule. Therefore, it would be considered as a clerical mistake in the letter dt. 5-7-87 and this is what has been pleaded by the management in para 2 of the written statement.

11. The second point raised is that there is practically no distinction between special messenger and callman. If the special messenger was eligible, a call man should have also been made eligible. No doubt both the classes belong to class IV category of employees, but the fact whether there is any distinction between the two classes is one for the management to decide. In this connection I would first refer to Ext. M.2 which is the copy of letter dated 4-7-83 from the Head Quater's Office of the Railway at New Delhi to the DRMs. By means of this letter on the basis of talks between the management and the recognised Union it was decided that messenger boys could seek their promotions in Ministerial Cadre but it was with respect of messenger boys working in C&W Department. There is no documentary evidence from the side of the Union to show that before the issue of letter dt. 5-1-87 special messengers posted in any other departments were made eligible for promotions to the post in ministerial cadre. This is the right of the management to determine as to who amongst from class IV would be eligible for selection to the post of clerks.

12. Ext. W.1, is the copy of letter dated 17-8-90 from the head quarter's office New Delhi to the DRMs of the various Railways on the subject of—

Avenues of promotion for Box Porters, Turn Table Khalasis Store Khalasis & Callmen Etc.

Here again it is evident that the letter was issued in persuance of decision taken by the management after taking into consideration the views of the recognised Unions. By means of this letter six categories of class IV employees including callmen were made eligible for promotion to the post of clerks in the scale of Rs. 950-1500.

13. Thus for the first time by means of the said letter in August 1990, callmen became eligible for promotion to clerical cadre. Being so the action of the management not permitting the three workmen for being considered for selection for the post of material clerk cannot be held as unjustified. In view of the letter dated 17-8-90, referred to above the 3 workmen referred to above on the basis of eligibility criteria can apply for their being considered for promotion to the post of clerks as and when vacancies against quota from amongst class IV eligible categories are invited.

14. In his cross examination Shri Parvez Alam has admitted that he was dismissed from service under rule 14(2) D&A Rules 1968. He has further admitted that the Tribunal by means of its award set aside the order of his dismissal from service. However, against the award the Rly. Administration filed a writ petition before the Hon'ble High Court of Allahabad Lucknow Bench. The Hon'ble High Court has stayed the operation of the award so far as he is concerned by means of order dt. 1-9-88. In view of it under no circumstances relief can be granted to him so long as the writ is pending before the Hon'ble High Court.

15. With the above observation, the reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, *Presiding Officer*

[No. L-41011|31|88-D.II(B)(Pt.)]

का. आ. 1472.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी० पी. डब्ल्यू. डी., जयपुर के प्रबन्धतंत्र के सबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-4-91 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 1472.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of C.P.W.D. Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on 30-4-91.

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 56/89

In the matter of dispute between :

Shri Satya Narayan Sharma, represented by Branch Secretary, CPWD Mazdoor Union, Qtr No. 29, CPWD Colony, Civil Lines, Ajmer-305001.

Versus

The Director General Works, CPWD, Nirman Bhavan, New Delhi.

2. Executive Engineer, Jaipur Central Electrical Division, CPWD, B-7, Moti Marg, Bapu Nagar, Jaipur (Rajasthan).

APPEARANCES :

Shri H. S. Vats—for the workman.

Shri Narinder Chaudhary—for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-42012|121|88-D.II(B) dated 24-5-89 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

'(Whether the action of the Management of Central Public Works Department (Elect.) in not declaring Shri Satya Narayan Sharma, Temp: Khalasi as Quasi-Permanent/Permanent is just and fair ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. The workman in his statement of claim alleged that he was appointed as Khalasi in unskilled category w.e.f. 28-3-72. The Management of the CPWD made applicable CCS (TS) Rules 65 to the temporarily employed work charged staff who opted for pensionary benefits w.e.f. 18-12-75 or the date on which he completed three years of service whichever was later. The workman submitted option for pensionary benefits to the Executive Engineer (Elect.) Faridabad vide application dated 29-10-72 which was duly received by the concerned authorities and receipt thereof was returned duly signed dated 7th February, 1973. Persons junior in the category of Khalasi unskilled were declared quasi-permanent by the said management and the workman concerned even being senior was discriminated against. Persons were declared even permanent who were junior to the workman w.e.f. 1-4-77 whereas the workman was discriminated against in the matter of permanency also. The workman had been continuously and invariably reminding the Management to declare him quasi-permanent/permanent but of no avail. The workman was an active member of CPWD Mazdoor Union and the Management indulged in unfair labour practice by way of teasing, harassing and victimising the workman by not declaring him quasi-permanent w.e.f. 18-12-75 and permanent from 1-4-77. He has been put to extreme financial hardship on account of non-grant of this status and has been deprived of consequential benefits of earned leave, half pay leave seniority etc. etc.

3. The Management in its reply admitted his appointment w.e.f. 28-3-72. He was not found fit by the DPC and hence could not be declared as quasi-permanent. Since he was not found fit even for quasi-permanent the question of declaring him permanent did not arise. He was informed about this fact from his Assistant Engineer vide letters dated 8-1-82 and 4-2-82. Hence no discrimination has been done against the workman in this case.

4. The Management in support of its case produced letter dated 17-3-82 and dated 25-10-89 Ex. M-1 and M-2 in support of its case while the workman representative produced documents Ex. W-1 and W-2, W-3, W-4 and W-5. No oral evidence was, however, produced by any of the parties.

5. I have heard the representative for the parties and have gone through the record.

6. The representative for the management has urged that the Departmental Promotion Committee comprising of officers of the Department have to declare the person fit to be made quasi-permanent. On the scrutiny to recommendation made by the concerned official is put in that category. The workman is question was never recommended for that by the DPC and if he was not declared fit. The question of his absorption in the quasi-permanent or permanent cadre does not arise. He was declared quasi permanent w.e.f. 1-1-88 as per W-5 and from that date onward he is being paid accordingly.

7 The representative for the workman on the other hand has urged that the workman had given his option while Ex. W-1 dated 29-10-72 for the pensionary benefits Persons junior to him were made quasi-permanent and permanent but for reasons best known to the management he was not given that status. The representative has further referred to the circular of the GOI CPWD bearing No. 32/17/77-ECX dated 18-8-87 according to which quasi-permanent status may be granted to the eligible temporary work charge employees w.e.f. 18-12-75, or w.e.f. the date of completion of 3 years of continuous service which ever was later. The workman in question had completed 3 years and, therefore, he should have been given that status immediately on completion of the said period.

8. After having gone through the record of this case produced before me I am of the view that the workman has not come into the witness box to depose about the facts of this case. The circular No. 32|1|77-ECX dated 18-8-81 was also to be made applicable to eligible temporary work charge employees. Whether the workman was eligible or not has not been established on the record of this case. The workman has not come to the witness box to state that he was ever considered by the DPC and was found fit. Later on, when he has been found fit by the DPC he has been declared quasi-permanent from 1-1-88. Eligibility and suitability has to be properly evaluated by the DPC and a person does not become automatically quasi-permanent and permanent. The persons junior to him had been declared quasi-permanent because they were found fit. In the absence of any evidence on record or even the statement of the workman I do not find any ground to hold that the action of the Management of the CPWD was in any way unjust and unfair. Parties are left to bear their own costs.

Dated : February 27, 1991.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

[No. L-42012/121/88-D.II (B) Pt.)]

का. आ. 1473.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कैंट बोर्ड, मेरठ, के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट, औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-4-91 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 1473.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Cantt. Board Meerut and their workmen, which was received by the Central Government on 29-4-91.

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV, PRESIDISG OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL DEOKI PALCE ROAD PANDU NAGAR KANPUR

Industrial Dispute No. 194 of 1989

In the matter of dispute between :

Shri Ramesh Kumar S/o Shri N. C. Jain G-7/6 Lekhanagar Meerut Cantt. Pin-250001.

AND

The Executive Officer Cantonment Board Meerut Cantt. Pin-250001.

AWARD

1 The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-13012/2/88-D.II (B) dated 20th August, 1989, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Kya Cantonment Board Meerut Cantt ke prabandhako dwara bhutpurva asthayi mazdoor Shri Ramesh Kumar Jain putra N. C. Jain ko dinank 1-8-85 se sewa se nishkashit karna nyayochit hai ? Yadi nahi to sambandhit karamkar kis anutosh ka adhikari hai ?

2. The case of the workman is that he had worked as Water Pump Operator in the Cantonment Board Meerut Cantt w.e.f. 1-8-84 to 31-7-85, whereafter his services were illegaly terminated in voilation of the provisions of section 25-F and Section 25-G of the Industrial Disputes Act, 1947. By that time he had worked for more than 240 days. At the time of termination of his services, S/Shri Narendra Kumar, Chandan and Rajiv who were junior to him were retained in service. Not only that after the termination of his services S/Shri Rajiv and Ajal were employed by the Cantonment Board as Pump Attendants. He has, therefore, prayed for his reinstatement with continuity of service, back wages and with all other consequential benefits.

3. With regard to the period of employment and the capacity in which the workman had worked, the management has partly admitted the facts without stating specifically as to what facts have been admitted in para two of the written statement. The management plead that the Cantonement Board has to engage temporary hands from time to time depending on the project. The workman did work on temporary basis. The completion of project necessitate the employer to ask temporary hands not to report for duty any more. All this does not amount to retrenchment or terminate of service. With regard to retention of S|Shri Sanjiv Kumar Chandan and Rajiv and employment of S/Shri Sanjiv and Ajai after the termination of the workmen, the management plead that in July 1985, the Cantonement Board requested the Employment Exchange to recommend the names of persons to be appointed for a period of one year. The names of above named persons were sponsored by the Employment Exchange. The copy of letter sent in this regard to employment exchange is annexure I to the written statement.

4. The workman has filed his rejoinder. He alleges that the management is guilty of unfair labour practice as the management used to employ temporary workman with a view to deprive them of their legitimate benefits. According to him all along he had worked as Pump Attendant. He denies that he had been engaged specifically for any particular project. He also denies that he was engaged for any specific period of time.

5. In support of his case, the workman has filed his affidavit and in support of their case the management have filed the affidavit of Shri Navin Chand Pant Accounts Clerk and one document. Workman has also filed a few documents.

6. Firstly we have to see whether the workman had worked as Water Pump Operator or he had worked in some other capacity.

7. In para 2 of his claim statement he has alleged that he had worked as Water Pump Operator. He has supported it by means of his affidavit. But he has belied his own case by stating in para 1 of his rejoinder that all along he had worked as Water Pump Attendant. In his cross examination he has deposed that he does not possess any Technical qualification. He is simply Intermediate pass.

8. Since in their written statement the management have not stated as to in what capacity the workman had actually worked, I am inclined to hold in view of the facts stated by the workman in para 1 of his rejoinder that he had simply worked as Water Pump Attendant and not as Water Pump Operator. I may state here that in his cross examination, the management witness has deposed that he worked as Assistant to Pump Operator and his job was simply to dig earth and to provide pipes by lifting the same to the Pump Operator. Hence on this point I hold that the workman was simply a Water Pump Attendant.

9. Secondly we have to see for how many days he had worked. The case set up by him in his claim statement and corroborated by him by means of his affidavit is that he had worked from 1-8-84 to 31-7-85. There is no specific denial of this fact by the management in their written statement. For the first time from the side of the management it has been stated by the management witness that the workman had never worked regularly during the period August 1984 to July 1985. In his cross examination, the management witness has deposed that during the period in question he had not worked continuously. In support of this fact no records have been produced by the management. In the absence of primary evidence and in view of any specific denial made by the management in this regard in their written statement I believe the workman and hold that he had worked from 1-8-84 to 31-7-85.

10. It thus becomes clear that during the period of one preceding year from the date of termination of his services he had worked for more than 240 days. On 18-3-91, the workman filed two documents which are the copies of certificates regarding the number of working days. These are Ext. W-1 and W-2. These two certificates show that he had worked for 301 days during the period August 1984 to July 1985. Naturally therefore in his case the provisions of Section 25-F were attached. The management witness has admitted in para 4 of his statement in his cross examination that no notice of termination of service was given to the workman nor he was paid any retrenchment compensation. Thus there was no compliance of the provisions of Section 25-F Industrial Disputes Act. It being so the order of termination is held as illegal.

11. The workman has also alleged violation of Section 25-G Industrial Disputes Act, 1947. His case is that S/Shri Narendra Kumar Chandan and Rajiv who were far junior to him were retained in service while his services were terminated. In his cross examination the workman has deposed that when he was kept on daily wages by the Cantonment Board, his name was sent to the Cantonment Board by the Employment Exchange. He admits that the names of the above named three persons were however sponsored by the employment exchange. Ext. M-1 is the copy of letter written by the Executive Officer, Cantonement Board Meerut Cantt to the Employment Officer Meerut for sponsoring the names of the candidates for filling up temporary posts of Motor Pump Attendant. It was clearly stated that the posts were only upto 31-3-86. For Motor Pump Attendants the requisite qualifications has been described as VIII pass with Trade Certificate in Electrician conversant with the duties of Motor Pump Attendant There is no evidence that these three persons are still continuing in service. From these facts it comes out that their appointment was made by following due procedure of recruitment while no such procedure was followed in the case of workman. So it cannot be held that there was any voilation of the provisions of Section 25-G on the part of the management.

12. It is also the case of the workman that after the termination of his services S/Shri Sanjiv and Ajal were employed as Pump Attendant. On this point he does not seem to have any good case. In his cross examination he has admitted that the names of these two persons were sponsored by the Employment Exchange and further they had worked in the Cantt. Board even prior to 1-8-84. Therefore it is not a case of violation of the above said provisions. is relying on the provisions of Section 25-H Industrial Disputes Act, 1947 read with Rules 78 of the I. D. Rules (Central) 1957. Being employees older than the workman they had a preferential right under the said provision. Therefore it is not a case of violation of the above said provisions.

13. The ordinary relief in case of violation of the provisions of Section 25-F, I. D. Act is of reinstatement with full back wages. However, in the instant case it has been argued by Shri B. C. Tondon, the auth. representative for the management that from the evidence on record it will appear that the workman was employed simply for a particular project and so after the completion of the project he can have no claim of reinstatement. In this connection he has referred to facts deposed to by the management witness in his cross examination. The management witness has admitted that Cantonment Board has its own permanent labour but when the work load increases casual labour is also engaged. In similar circumstances for the project of laying down pipes in ward No. 7 the workman was engaged. His job was simply to help the Pump Operator who lays the pipes. The job consisted of digging earth and handing over pipes to the Pump Operator. According to the witness the work in ward No. 7 had finished.

14. Shri Tondon has also submitted that at the most the workman should be awarded some compensation. From para 6 of the statement in cross examination of the workman it is clear that for the last about 2 years he has been working in Photostudio, Meerut Cantt. on a salary of Rs. 500 per month. He has admitted that while working on daily wage in the Cantt. Board he was simply getting Rs. 390 as wages

per month. Shri Tondon has also drawn my attention to the fact that the workman is also guilty of delay. The reference order it of 17th August, 1989. It means that he had raised the dispute very late.

15. On the other hand, it has been alleged by Shri N. K. Verma the authorised representative for the workman that the work in Cantonment Board never ends. If one project finishes the other project starts.

16. After hearing the two sides and considering the facts and circumstances I am of the view that it is a fit case where instead of reinstatement compensation should be awarded to the workman. Presently he is gainfully employed. Therefore he is awarded Rs. 10,000 as compensation in lieu of reinstatement.

17. Reference is answered accordingly.

Dated : 26th March, 1991.

ARJAN DEV, Presiding Officer

[No. L-13012/2/88-D.II (B) (Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

नई दिल्ली 7 मई, 1991

का० आ० 1474 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल आर्डिनेन्स डिपो जबलपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-5-91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 7th May, 1991

S.O. 1474.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Ordnance Depot Jabalpur and their workmen, which was received by the Central Government on 1-5-1991.

ANNEXURE

BEFORE SHRI V. N. SHUKLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(22)/1988

PARTIES :

Employer in relation to the management of Commandent Central Ordnance Depot, Jabalpur and their workman, Shri D. M. Singh, Ex-Office Supdt. Gr. II, P/No. 20642, Resident of H. No. 200, Chhoti Omti, Oriya Mohalla, Jabalpur (M.P.)

APPEARANCES :

For Workman—Shri R. K. Gupta, Advocate.

For Management—Shri S. S. Jha, Advocate.

INDUSTRY : Ordnance Depot DISTRICT : Jabalpur (M.P.)

AWARD

Dated, 19 April, 1991

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, vide Notification No. L-14012/25/86-D.II (B) dated 11th February, 1988, for adjudication of the following dispute :—

"Whether the action of management of Central Ordance Depot, Jabalpur in compulsory retiring Shri D. M. Singh, Ex-Office Supdt. Gr. II, C.O.D. Jabalpur w.e.f. 12-10-83 vide order No. 20402/OS-1/DC-480/Adm (Civ.) dated 1-10-83 and subsequently refusing his leave encashment is justified ? If not, to what relief, workman concerned is entitled to ?"

2. This is a case one Shri D. M. Singh Ex-Office Superintendent, Grade II, C.O.D. Jabalpur. He was retired with effect from 12-10-1983 on the basis of the chargesheet to the effect that he has made a false L.T.C. claim. The chargesheet is as under :—

Statement of articles of charge framed against Shri D. M. Singh, O|Supdt. Grade-II.

ARTICLE OF CHARGE-I

In that the said Shri D. M. Singh while functioning as O/Supdt. Gde-II in Depot Account Office of COD Jabalpur during the period from October 81 to January 82, had applied for and drew a sum of Rs. 5340 as LTC advance of 65 December 81 in favour of himself and nine family members for proceeding to Madurai and back whereas he submitted an LTC adjustment claim for Rs. 4572 on 21 January 82 for self and five family members only. Shri D. M. Singh thus overdrew LTC advance in favour of 4 family members and failed to refund the excess drawn amount immediately on completion of return journey and even after written demand No. 9302/LTC/ESTT-NI dated 19 March 82 issued to him through the Depot Account Office and he was withholding the said amount in unauthorised manner. The excess drawn amount of Rs. 1778.40 had ultimately to be recovered from his pay and allowances of March and April 82.

Shri D. M. Singh by his above acts exhibited lack of integrity and conduct unbecoming of a Government servant thereby violating rule 3 of the CCS (Conduct) Rules, 1964.

ARTICLE OF CHARGE-II

In that the said Shri D. M. Singh while functioning as O/Supdt. Grade-II in the aforesaid office during the aforesaid period preferred fradulent LTC claim for self and five family members amounting to Rs. 4572 for the journey purported to have been undertaken by them to Madurai and back by First Class rail accommodation during the period 15 to 25 December 81 and in support of the claim quoted first class ticket Nos. 040 to 045 dated 15 December 81 for the onward journey (Ex. Jabalpur to Madurai) and a combined T. No. 115973 for the return journey from Madurai to Jabalpur. When asked to produce the first class reservation tickets, he gave a written statement dated 11 February 82 that he got the reservation through the travelling conductor of first class both during onward and return journey and that the reservation tickets were handed over to the ticket collector at Madurai and Jabalpur along with the tickets. Whereas on verification it has been revealed that though the party had purchased tickets for six adults Ex Jabalpur to Madurai and back on 15 December 81 for Rs. 4572 and that those tickets were cancelled through 2 different counters at Jabalpur Railway Station the same date (15 December 81) itself and collected a net refund of Rs. 4569.

The verification report received from the Railway authorities reveal that Shri D. M. Singh had submitted a false LTC adjustment claim against LTC advance drawn by him and submitted a false statement regarding the reservation tickets with the motive of defrauding public fund to the tune of Rs. 4572.

Shri D. M. Singh by his above act exhibited conduct unbecoming of a Government servant in violation of rule 3 of CCS (Conduct) Rules, 1964.

3. The departmental enquiry was held against the workman and he was compulsory retired with effect from 13th October, 1983. Since leave encashment was also refused.

4. According to the workman, he has been kept under suspension with effect from 27-8-1982 by Brigadier K. R. Nath In C.O.D. He was not the appointing authority and was not competent to suspend the workman and hence the basis of disciplinary enquiry is illegal. He was charge-

sheeted on 9-10-1982 on certain false and frivolous allegations. It was properly replied but a mechanical decision was taken without considering the reply and Major J. K. Mehra was appointed as an Enquiry Officer. But he was replaced by a subordinate officer to the Commandant deliberately chosen to give a finding against the workman. Though one Shri T. M. Chetty was appointed as an Enquiry Officer but his appointment was cancelled without any justification.

5. The workman suffered hardship due to long suspension. The enquiry held against him was illegal. Despite his applications 15-10-82 and 16-12-82 to supply the documents he was not supplied the documents and hence the enquiry was prejudicial and is liable to be quashed.

6. It was hastly closed on 18-5-1983. Even thereafter documents were not supplied to the workman. The charges were baseless. Findings are perverse and not in accordance with law. Conclusions are made against the principles of natural justice and without giving full opportunity to the workman. He has been deliberately held guilty of the charges. There is no application of mind. The punishment was discriminatory because the other employees who were found guilty of similar misconduct have been given minor penalty but the workman has been given severe penalty of compulsory retirement. The punishment is disproportionate and harsh and excessive. He has more than 20 years of clean record. The alleged misconduct has no where been defined under the Rules. The enquiry is liable to be quashed. The punishment is also liable to be set aside and the workman is entitled to reinstatement with full back wages and consequential benefits.

7. Without going into deep long written statement given by the management, it is substance has denied all these averments made by the workman concerned. According to the management, the workman was suspended by the competent authority and no prejudicial enquiry was held. It was just and in accordance with law. He had all the access to the documents and had full liberty to obtain the copy of the said documents or to take extract therefrom. The documents by which Article of Charges was proposed to be submitted was produced by the Presenting Officer before the Enquiry Authority in presence of the workman and his prominent defence assistant Shri B. S. Parihar. The workman and his defence assistant has taken the copies of the required documents in their own hand writing as per their choice. All the allegations made are after thuoght. The misconduct was grave and was nothing short of cheating to the Government. He was a responsible Officer and the punishment was awarded looking to the status, literacy or illiteracy, maturity of the workman. Thus the punishment is adequate. Even otherwise also the case has been brought after lapse of 44 years and even if he was not compulsorily retired he would have superannuated on attaining the age of 58 years on 31 December, 1987. Hence there is no substance in his case and the reference is liable to be rejected.

8. Having gone through the entire D.E. file I find that the points raised challenging the validity of the departmental enquiry and finding there have no force. Management has filed a letter from the Director of Ordnance Services dated 25th October, 1979 to show that in exceptional circumstances a lower authority can place a Government servant under suspension but such an authority shall be required to forthwith report to the appointing authority the circumstances in which the order has been made and obtain his ex-post facto approval in this regard. It is nobody's case that ex-post facto approval was not obtained. Thus it cannot be said that the suspension was illegal and enquiry is vitiated on this point.

9. Other points are not material though D.E. file does not reveal that the documents were supplied to the workman concerned, but it can be seen from parawise comments of the appeal dated 8th November, 1985 page 3, para 9(e) to (h) and (j) that all the documents in original were shown to the workman along with his defence assistant Shri B. S. Parihar. That apart, para 25 at page 5 further disclose that the individual was given full opportunity to obtain the copy of the documents referred to in the enquiry proceedings.

10. It should be kept in mind that this is a case where the workman was compulsorily retired and even otherwise also he would have retired at the age of superannuation on 31 December, 1987 and there is sufficient material to show that the charges framed against the workman have been amply proved by the documents on record. No other specific points were raised to challenge the validity of the equiry. That apart, it cannot be said that the enquiry is perverse. Paras 20 and 21 of the report at page 4 discloses the evidence against the delinquent workman according to which the Railway Authorities had specifically shown that the Ticket Nos. by virtue of which the delinquent has shown to have travelled were returned by him on the same date and the charges are obviously proved. This is nothing short of putting the Government to a monetary loss and cheating the Government. That apart, the money for which purpose it was given was not utilised by the workman and was misappropriated. That being so, he had incurred a criminal liability but he should thank himself that looking to his past record he was compulsorily retired. I need not go into further details of all the case because they do not call for detailed discussions and can be ignored.

11. So far the question of refusing Leave Encashment is concerned, it has to be kept in mind that the workman concerned was compulsorily retired by way of punishment and he was not entitled to the Leave Encashment as per office Memo No. 15(2)/74-76/D'Est. I/Gp. II) dated 19th November, 1977 forwarding therewith Office Memo No. P-14028/1/77-E.IV (A) dated 29th October, 1977 of the Ministry of Finance, copies of which are on record. This benefit was extended to officers who were compulsorily retired on or after 6-2-1987 as per letter of the department of Personnel and Training's OM No. 14028/18/86-Estt (L) dated 22 June 1987. The workman retired with effect from 13th October, 1983 and hence he is not entitled to the benefits of Leave Encashment as per Memo referred to above. The workman is accordingly not entitled to any benefit/ relief as claimed and the reference is answered in negative with no order as to costs.

V. N. SHUKLA, Presiding Officer

[No. L114012/25/86-D.II(B)(Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

नई दिल्ली, 2 मई, 1991

का० आ 1475 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मै बी० सी० सी० एल० का भौरा एरिया सं० 11 के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं 1 धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-4-91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 2nd May, 1991

S.O. 1475.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhowra Area No. XI of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on the 29-4-1991.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

In the matter of a Reference under Section 10(1)(d) of the I. D. Act., 1947.

REFERENCE NO. 64 OF 1990

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhowra Area No. XI of M/s. Bharat Coking Coal Ltd.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri D. K. Dey, Organising Secretary, Colliery Karamchari Sangh.

On behalf of the employers : Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 19th April, 1991

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012/223/89-I. R. (Coal-I) dated, the 6th April, 1990 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :—

"whether the action of the management of Bhowra Area No. XI of M/s. BCCL in not regularising Shri Harish Chandra Saroj as Land Asstt. in Tech. and Supervisory Grade—'C' w.e.f. 25-12-1986 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the basis of terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an Award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the Award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. L-20012/223/89-IR (Coal-I)]
K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1 AT DHANBAD

Reference No. 64/90.

Employers in relation to the Management of Bhowra Area.

AND

Their Workmen.

Petition of Compromise.

The humble petition on beralf of the parties to the above reference most respectfully shewth :—

1. That the above dispute has been amicably settled between the parties trrough the Joint Committee as conveyed vide letter No. BCCL/PER/IR/JC/BCKS/SLK/91/2441, dated 14/16th Feb. 1991 from Shri AD Shukla, Dy. CPM (IR) on the following terms :—

Terms of Settlement

(a) That the concerned workman Shri Harish Chandra Saroj will be regularised as Land Assistant in Technical and Supervisory Grade "C" with effect from 19-2-1987.

(b) That the concerned workman will be paid 50 per cent of the amount that will accrue on computation of difference of wages between grade "C" and the amount actually received by him from 19-2-87 till the date of implementation of the Settlement in full and final payment of all his claim from 19-2-87.

(c) That the concerned workman will shoulder higher responsibility of Grade "C" fixed for Land Assistants as will be presented from time to time.

2. That in view of the above Settlement there remains nothing to be adjudicated.

Under the facts and circumstances stated above the Hon'ble Tribunal will be graciously pleased to accept the Settlement as fair and proper and be pleased to pass the Award in terms of the Settlement.

For the Workmen.

1. Harish Chandra Saroj
Area Office, Bhowra.

For the Employers

1. R.N. Ghosh,
P. M. Bhowra Area,
M/s. B.C.C.L.

2. R. J. Singh,
Dy. P. M. Bhowra Area,
M/s. B.C.C.L.

Witness :

1. Sd./- Illegible
2. Sd./- Illegible

नई दिल्ली, 3 मई, 1991

का० आ० 1476 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार केथोलिक सीरयन बैंक लि० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय ऐरनाकुलम के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 30-4-91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 3rd May, 1991

S.O. 1476.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the following award of the Labour Court Ernakulam as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Catholic Syrian Bank Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 30-4-91.

ANNEXURE

IN THE LABOUR COURT, ERNAKULAM

Tuesday, the 2nd day of April, 1991

PRESENT :

Shri R. Raveendran, B.A., B.L., Presiding Officer.

Industrial Dispute No. 9/88(C)

BETWEEN

The employer in relation to the management of Catholic Syrian Bank represented by the Chairman Catholic Syrian Bank Ltd., H.O. Trichur, Kerala.

AND

The workman Shri A. N. K. Devassy, S/o Kunhu Varu, Arakkal Nellissery House, P.O. Valappad, Trichur Dist. Kerala.

REPRESENTATIONS :

Shri M. Venugopalan, Advocate Thrissur : For Management
Shri K. Sidharathan, Advocate, Thrissur : For Workman

AWARD

The justifiability of dismissal of Shri A. N. K. Devassy, sub-staff in the Perinnanam Branch of the Catholic Syrian Bank Limited was originally referred to the Labour Court, Kozhikode as per Order No. L-12011|26|88-D.1(B) dated 29-9-1988 of the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi. The issue covered by the reference is the as per Order No. 12011|26|88.D.I(B) dated 2-11-1988 of the Government of India.

II. The dismissal was inflicted as a punishment after a domestic enquiry. The validity of the domestic enquiry was tried by me as a preliminary issue. I found on that aspect as per my order dated 27-2-1991 that there was a proper and valid domestic enquiry. I found further that the findings of guilt rendered by the Enquiry Officer are correct. Facts necessary for disposal of the case have been narrated in that order which I shall here extract in full :—

"PRELIMINARY ORDER

This industrial dispute was originally referred to the Labour Court, Kozhikode as per Order No. L-12011|26|88-D.I(B) dated 29-9-1988 of the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi. Subsequently it was transferred to this court at per Order No. L-12011/26/88. D.I(B), dated 2-11-1988 of the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi. The issue covered by the reference is the following :—

"Whether the action of the Management of M/s. Catholic Syrian Bank Ltd., in dismissing Shri A. N. K. Devassy, Sub-staff in the Perinnanam branch from service w.e.f. 9-6-1987 is justified ? If not, to what relief the workman concerned entitled ?"

2. The workman has filed a claim statement stating as follows :—

The workman was working in the Perinnanam Branch of the Management Bank from 1-10-1969 as a peon. He was dismissed illegally on 29-6-87. At the time of dismissal he was drawing a salary of Rs. 1554.60 p.m. In October, 1986 Shri Devassy was asked to give a statement admitting that he had stolen some amounts from the bags of some of the Staff members of Periannanam branch of the Bank. When he refused to give such a statement he was threatened to be proceeded against. He was also assured that no steps will be taken on the basis of that statement. So he gave a statement as dictated by the Branch Manager on 4-10-86. But the management suspended the worker on the basis of that statement on 26-12-86 pending enquiry. Subsequently he was served with a charge memo to which he submitted his explanation. Sri K. O. George, Senior Superintendent, Zonal Office of the Bank, Ernakulam conducted an enquiry on 27-3-1987. The worker was not allowed to enlist the help of anyone during the enquiry. He was advised not to take the enquiry seriously, since it was only a procedural affair to close the matter. He was not allowed to cross-examine the management witnesses and to adduce his own evidence. The enquiry officer had recorded only what he wanted and not all the evidence in full. Ultimately the enquiry officer found the worker guilty and as a consequence the management dismissed the worker on 29-6-87. The charges are flimsy and the punishment largely disproportionate with the alleged offence. The so-called inquiry was not at all impartial. The dismissal is to be set aside and the worker is to be reinstated without break of service and with all other benefits.

3. The management has filed a written statement contending as follows :—

The workman was employed as a sub-staff in the Bank. While working as a sub-staff attached to Perinnanam branch of the bank he pilferred amounts from the drawer and bags of other staff members of the branch kept in the dining room. On enquiries it was detected that Devassy was the culprit. When it was found out, Devassy admitted in the presence of all other staff members that he had pilfered amounts as alleged. He also gave it in writing to the branch manager and later repaid the amounts taken by him. The workman was kept under suspension pending enquiry and he was also chargesheeted. Nobody gave any assurance to the workman that he would not be proceeded against. All attacks made against the enquiry and the enquiry officer are baseless and wrong. The enquiry held is quite fair, proper and valid. The finding of the enquiry officer is based on the evidence recorded in the enquiry. The punishment awarded is not disproportionate to the gravity of the misconduct established. Pilfering of amounts belonging to co-workers and that too within the premises of the bank is a very grave misconuct. The punishment meted out to Devassy is quite commesurate with the seriousness of the offence proved. The workman is not entitled for any of the reliefs claimed by him.

4. The workman has filed a replication reiterating his claims in the claim statement and refuting the contentions in the written statement filed by the management.

5. The points that arise for consideration are whether the enquiry conducted by the enquiry officer is legal and proper and whether the findings entered into by the enquiry officer are supported by legal evidence.

6. The enquiry officer was examined as MW1 and the file relating to the domestic enquiry was marked as Ext. M-1.

7. The delinquent Devassy was employed as a substaff in the Management Bank. While working as a sub-staff in the Perinnanam Branch of the Bank he committed theft of amount from the drawer and bags of other staff members of the Bank kept in the dining room. On the basis of the complaints received from the various members of staff, viz. N. L. Francis, P. V. Davis P. V. Joy etc., the Branch Manager made enquiry and attempted to find out the culprit. He kept marked currency notes in the bag of one lady staff and he bag was placed in the dining room. Then it was found out that Sri Devassy was the culprit. Sri Devassy admitted in the presence of all other staff members of the branch that he has committed the theft and he also gave it in writing to the Branch Manager as is evidenced by Ext. M2 marked in the enquiry and later on he repaid the amount taken by him. On the basis of these allegations the delinquent was charge-sheeted for the misconduct of theft of cash totalling Rs. 172 from the bags of staff members kept in the dining room of the bank and he was called upon to explain why disciplinary action should not be taken against him. He submitted his explanation admitting the misconduct of theft of Rs. 172 as is evidence by Ext. M-3 (marked in enquiry). Not satisfied with the explanation submitted by the delinquent, tre masagement ordered a dimestic enquiry. Tre enquiry officer submitted his report Ext. M1 finding the delinquent guilty of the charge. Accepting the finding of the Enquiry Officer, the management dismissed the delinquent from service. Aggrieved by the said dismissal, the workman raised an industrial dispute which culminated in this reference.

8. It can be seen that the workman is not seriously disputing the mode of enquiry conducted by the Enquiry Officer. The Enquiry Officer was examined as MW1 who would depose that he conducted the enquiry following the principles of natural justice by afforidng ample opportunity to the deliquent of being heard and the delinquent was also given opportunity to cross-examine the witness of the management and to examine his own witnesses to prove his innocence. He would further depose that the delinquent has earnestly and actively participated in the enquiry and cross-examined the witnesses of the management. On perusal of the testimony of MW1 and the proceedings of the enquiry contained in Ext. M1 file it can be seen that the enquiry officer has conducted the enquiry following the principles of natural justice by giving proper and sufficient opportunity to the delinquent of being heard and he was served with list of witnesses and documents sufficiently early and then he was given ample opportunity to defend his case. In these circumstances, I find that the enquiry conducted by the Enquiry

Officer is legal and proper adhering to the principles of natural justice.

9. Concerning the finding of the Enquiry Officer, it is pertinent to note as per Exts. M2 and M3 (in the enquiry) the delinquent has admitted that he has committed the misconduct of theft as alleged. Now the delinquent has attempted to prove that Exts. M2 and M3 were written by him to the Branch Manager on account of coercion and undue influence exerted by the Manager on him. But there is absolutely no evidence in this case to show that the Branch Manager has exerted any influence or coercion on him or obtaining Exts. M2 and M3. It is to be noted that the delinquent has explained that the crime was committed by him because of the financial crisis he was then confronting and Exts. M2 and M3 were written by the delinquent in his own hand writing. In these circumstances I find that the contention of the delinquent that he has written Exs. M2 and M3 on account of coercion and undue influence exerted by the Branch Manager on him will not hold good. On perusal of the testimony of MW1, the Manager of the Branch (in the enquiry) under whom the delinquent was working as a peon and the deposition of MW2 (in the enquiry), the Senior Superintendent, Thrissur Zonal Office, would amply prove that the delinquent has committed the misconduct of theft and their versions are corroborated with the testimony of MWs. 3 to 6 (in the enquiry) on all material particulars of the misconduct. As held by the enquiry officer, there is no reason to disbelieve the version of these witnesses. Exts. M4, M5 and M6 in the enquiry are specific complaint letters addressed to the Branch Manager, by the complainants Sri George T. Parambeth, Shri N. L. Francis and Smt. K. N. Valsala Kumari respectively. Ext. M7 is also a complaint letter written by seven staff members of the Bank to the Manager regarding the theft of Shri A. N. K. Devassy, and Exts. M2 and M3 are the letters written by the delinquent in his own handwriting the misconduct. In these circumstances, in the light of the depositions of witnesses MWs. 1 to 6 and Exts. M2 and M3 it can safely come to the conclusion that the delinquent has committed the misconduct as alleged. Therefore the finding of the Enquiry Officer that the delinquent was guilty of the charge is fully supported by legal and proper evidence and so the finding of the enquiry officer is also correct.

10. In the result it is hereby found that there was a proper and valid domestic enquiry and the finding of the enquiry officer is also correct."

III. The question remains to be adjudicated is regarding the justifiability and the propriety of the punishment of dismissal imposed on the delinquent for the misconduct of pilferring amounts from the drawer and bags of other staff members of the bank kept in the dining room. In the enquiry it is proved that the delinquent was pilferring amounts belonging to other co-workers and that too within the premises of the Bank and this act of the workman is a grave misconduct. In view of the fact that the delinquent has committed the misconduct of theft of money belonging to other co-workers, he is not deserved any lenient punishment and the punishment imposed on him cannot be said to be disproportionate to the gravity of the misconduct committed by him. The order dismissal is only commesurable with the misconduct committed by him. Hence I find that there is no reason for invoking Sec. 11-A of the I.D. Act for interfering in the matter of punishment imposed on the delinquent in this case.

IV. In the result an award is passed conforming the dismissal of Shri A.N.K. Devassy from service w.e.f. 9-6-1987 Shri Devassy is not entitled to any relief in this reference.

R. RAVEENDRAN, Presiding Officer

[No. L-12011/26/88-DI(B)]

S. C. SHARMA, Desk Officer

Ernakulam, 2-4-1991

APPENDIX

Witness examined on the Management's side :
MW-1. Shri K. O. George.

Exhibit marked on the Management's side :
Ext. M-1. File relating to the domestic enquiry held against Shri A.N.K. Devassy.

R. R. RAVEENDRAM, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 6 मई, 1991

का. आ. 1477 :—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सर्वश्री अखिलेश कुमार, मोहन सिंह, अनूप विश्वास को अगले आदेशों तक मुख्य खान निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक नियुक्त करती है ।

[फा० सं ए-12025/1/87-खान-I/आई० एस० एच०-I]

राम तिलक पाण्डेय, उप सचिव

New Delhi, the 6th May, 1991

S.O. 1477.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) the Central Government hereby appoints S/Shri Akhilesh Kumar, Mohan Singh and Anup Biswas as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines, until further Orders.

[No. A-12025/1/87/M.I/ISH.I]

R. T. PANDEY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 1991

का. आ. 1478 :—यतः मैसर्स राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड आनन्द, गुजरात—388001 तथा इसकी बम्बई दिल्ली, कलकत्ता और बंगलौर स्थित शाखायें (इसके आगे जहां कहीं भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो इससे अभिप्राय उक्त स्थापना से है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) इसके आगे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

यह केन्द्र सरकार की राय है उक्त स्थापना के कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए भविष्य निधि नियमों में अंशदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित कर्मचारी अंशदान की दर से कम नहीं है तथा इसके कर्मचारियों को मिलने वाले भविष्य निधि लाभ उक्त अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (इसके आगे जहां कहीं भी स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है उससे अभिप्राय उक्त स्कीम से है) में उल्लिखित लाभों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है जो इस वर्ग की स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध है।

अब इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा एक के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनुसूची में वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापना को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के लागू होने से 1-12-1987 से छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना से संबंधित नियोक्ता केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर दिए गए निवेश के अनुसार उक्त

अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) में उल्लिखित निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार की अदायगी प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा।

2. न-छूट प्राप्त स्थापनाओं के संबंध में उक्त अधिनियम और उनके अधीन सृजित उक्त स्कीम के अंतर्गत देय अंशदान के दर से स्थापना के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत देय अंशदान का दर किसी समय भी कम न होगा।

3. पेशगियों के मामले में छूट प्राप्त स्थापना की स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 से कम हितकारी नहीं होगी।

4. उक्त स्कीम में कोई भी संशोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमों से अधिक लाभकारी है उन पर अपने आप लागू किया जाएगा। उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित के प्रतिकूल प्रभावी होने की सम्भावना है वहां अपनी अनुमति देने से पूर्व, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा।

5. यदि स्थापना को छूट न दी जाती तो वे सभी कर्मचारी (जैसे उक्त अधिनियम की धारा 2 (च) में निश्चित किया गया है) जो सदस्य बनने के पात्र होते, सदस्य बनाए जाएंगे।

6. जहां एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी) या किसी अन्य छूट प्राप्त स्थापना का पहले से सदस्य है, को अपनी स्थापना में काम पर लगाया जाता है तो नियोक्ता उसे निधि का तुरन्त सदस्य बनाएगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले नियोक्ता के पास भविष्य निधि में लेखे में संचयों को अंतरित करने और उसके लेखे में जमा कराने की व्यवस्था करेगा।

7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के द्वारा जैसे भी मामला हो, समय समय पर दिए गए आदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबन्ध के लिए नियोक्ता न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा।

8. भविष्य निधि, न्यासी बोर्ड में निहित होगा जो अन्य बातों के होते हुए भविष्य निधि में आय के उचित लेखों और भविष्य निधि से अदायगियों और उनकी अभिरक्षा में गोपी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उत्तरदायी होगा।

9. न्यासी बोर्ड कम से कम 3 माह में एक बार बैठक करेंगे और केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक से खातों को दुबारा लेखा परीक्षा कराए और ऐसे पुनः लेखा-परीक्षा के खर्च नियोक्ता वहन करेगा।

10. न्यासी बोर्ड द्वारा रखे गए भविष्य निधि लेखे अर्हता प्राप्त निष्पक्ष चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन होंगे। जहां आवश्यक समझा जाए, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किसी अन्य अर्हता प्राप्त लेखा-परीक्षा द्वारा लेखों की पुनः लेखा परीक्षा कराने का अधिकार होगा और इस पर हुआ व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

11. प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक भविष्य निधि लेखों की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

12. नियोक्ता प्रतिमाह भविष्य निधि के देय अपने कर्मचारियों के अंशदानों की आगामी माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित कर देगा। अंशदानों की विलम्ब से अदायगी करने के लिए समान परिस्थितियों में नियोक्ता मुकशानी देने का उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार एक न-छट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती है।

13. न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा समय-समय दिए गए निदेशों के अनुसार निधिमें जमा राशियों का निवेश करेगा। प्रतिभूतियां न्यासी बोर्ड के नाम पर प्राप्त की जाएगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा नियन्त्रण में अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

14. सरकार के निदेशों के अनुसार निवेश न करने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग रूप से और एक साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए अधिक प्रभार का उत्तरदायी होगा।

15. न्यासी बोर्ड एक वस्तु-ब्यौरा रजिस्टर तैयार करेगा और ब्याज और विमोचन आय को समय पर वसूली सुनिश्चित करेगा।

16. जमा किए गए अंशदानों, निकाले गए और प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित ब्याज को दिखाने के लिए न्यासी बोर्ड विस्तृत लेखे तैयार करेगा।

17. वित्तीय/लेखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा।

18. बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर पासबुक जारी कर सकता है। ये पास-बुकें कर्म-

धारियों की अभिरक्षा में रहेंगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतीकरण पर बोर्ड के द्वारा उन्हें अद्यतन किया जाएगा।

19. लेखा वर्ष के पहले दिन आदि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के लेखे में ब्याज उस दर से जमा किया जाएगा जिसका न्यासी बोर्ड निर्णय करे परन्तु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा।

20. यदि न्यासी बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ब्याज की दर इस कारण से कि निदेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से अर्जा करने में असमर्थ है तो इस कमी को नियोक्ता पूरा करेगा।

21. नियोक्ता भविष्य निधि की चोरी के कारण लटख सोतब्या नत गबन अथवा किसी अन्य कारण से हुई हानि को पूरा करेगा।

22. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियों प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित करें।

23. उक्त स्कीम के पैरा 69 की शैली पर किसी कर्मचारी को निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापना के भविष्य निधि नियमों में नियोक्ताओं के अंशदानों को जब्त करने की व्यवस्था है तो न्यासी बोर्ड इस प्रकार जब्त की गई राशियों का अलग से लेखा तैयार करेगा और उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति से सुनिश्चित किया गया हो।

24. स्थापना के भविष्य निधि नियमों में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति की सेवा निवृत्ति होने के फलस्वरूप या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नौकरी करने पर निधि की सदस्यता समाप्त हो जाती है यह पता लगता है कि प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अंशदान की दर समपहरण की दर आदि संविधिक योजना के अन्तर्गत दी गई दरों की तुलना में कम अनुकूल है तो अन्तर का वहन नियोक्ता द्वारा किया जायेगा।

25. नियोक्ता, भविष्य निधि के प्रशासन से संबंधित सभी खर्चे जिसमें लेखों के रखरखाव रिटर्न प्रस्तुत किए जाने, राशियों का अन्तरण शामिल है वहन करेगा।

26. नियोक्ता समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति तथा जब भी कोई संशोधन होता है उसकी मुख्य बातों को कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में अनुवाद करके स्थापना के बोर्ड पर लगाएगा।

27. "समुचित सरकार" स्थापना की चालू छूट पर और शर्तें लगा सकती है।

28. यदि उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापना वर्ग जिसमें उसकी स्थापना आती है पर अंशदान की दर बढ़ायी जाती है नियोक्ता भविष्य निधि अंशदान की दर उचित रूप में बढ़ाएगा ताकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों से स्थापना की स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले भविष्य निधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हों।

29. उक्त शर्तों में से किसी एक के उल्लंघन पर छूट रद्द की जा सकती है।

[संख्या एस-35015/3/91-एस एस II]

New Delhi, the 6th May, 1991

S.O. 1478.—Whereas Messrs National Dairy Development Board, Anand (Gujarat) 388001 and its branches at Bombay, Delhi, Calcutta & Bangalore (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act).

And whereas in the opinion of the Central Government the rules of the Provident Fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in Section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

THE SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of said Act within 15 days from the close of every month.

2. The rate of contribution payable under the provident fund rules of the establishment shall at no time be lower than those payable under the said Act in respect of the unexempted establishments and the said Scheme framed thereunder;

3. In the matter of advances, the scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees Provident Fund Scheme, 1952.

4. Any amendment to the said scheme this is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically no amendment of the rules of the provident fund of the said establishment shall be made without the previous approval of the Regional Provident Fund Commissioner and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees of the said establishment, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

5. All employees (as defined in section 2(f) of the said Act) who would have been eligible to become members of the Provident Fund had the establishment not been granted exemption shall be enrolled as members.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory) or a Provident Fund

of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the fund and arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transferred and credited to his account.

7. The employer shall establish a Board of Trustees for the management of the provident fund according to such directions as may be given by the Central Provident Fund Commissioner or by the Central Government, as the case may be, from time to time.

8. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees' Provident Fund Organisation inter alia for proper accounts of the receipts into and payments from the Provident Fund and the balance in their custody.

9. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner or an officer authorised by him.

10. The accounts of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified Independent Chartered Accountant annually. Where considered necessary, the Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

11. A copy of the audited annual provident fund accounts together with the audited balance sheet of the establishment for each accounting year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner within six months after the close of the financial year. For this purpose the financial year of the provident fund shall be from the 1st of April to the 31st of March.

12. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions pafable to the provident Fund by himself and the employees by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay damages to the Board of Trustees for any delay in payment of the contributions in the same manner as an unexempted establishment is liable under similar circumstances.

13. The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per directions that may be given by the Government from time to time. The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees and shall be kept in the custody of a Scheduled Bank under the Credit Central of the Reserve Bank of India.

14. Failure to make the investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees severally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.

15. The Board of Trustees shall maintain a script-wise register and ensure timely realisation of interest and ensure timely realisation of interest and redemption proceeds.

16. The Board Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee.

17. The Board shall issue an annual statement of account to every employee within six months of the close of financial accounting year.

18. The Board may, instead of the annual statement of accounts, issue pass books to every employee. These pass books shall remain in the custody of the employees and will be brought uptodate by the Board on presentation by the employees.

19. The account of each employee shall be credited interest calculated on the opening balance as on the 1st day of the accounting year at such date may be decided by the Board of Trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme.

20. If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason, than the deficiency shall be made good by the employer.

21. The employer shall also make good any other loss that may be caused to the Provident Fund due to theft burglary, defalcation, mis-appropriation or any other reason.

22. The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government/Central Provident Fund Commissioner may prescribed from time to time.

23. If the Provident Fund rules of the establishment provide for forfeiture of the employers' contribution in cases where an employee ceases to be a member of the fund on the lines of para 69 of the said Scheme, the Board of Trustees shall maintain a separate account of the amounts so forfeited and may utilised the same for such purposes as may be determined with the prior approval of the Central Proxident Fund Commissioner.

24. Notwithstanding anything contained in the provident fund rules of the establishment, if on the cessation of any individual, from the membership of the fund consequent on retiring from service or on taking up the employment in some other establishment, it is found that the rate of contribution, rate of forfeiture etc. under the provident fund rules of the establishment are less favourable as compared to those under the statutory scheme, the difference shall be borne by the employer.

25. The employer shall bear all the expenses of the administration of the Provident Fund including the maintenance of Accounts submission of returns, transfer of accumulations.

26. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto alongwith a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.

27. The "appropriate Government" may lay down any further conditions for continued exemption of the establishment.

28. The employee shall enhance the rate of provident fund contributions appropriately if the rate of provident fund contribution for the class of establishments in which his establishment falls is enhanced under the said Act so that the benefits under the Provident Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act.

29. The exemption is liable to be cancelled for violation of any of the above conditions.

[No. S-35015(3)/91-SS-II]

नई दिल्ली, 9 मई, 1991

का. आ. 1473:— केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, अजमेर, अलवर भरतपुर, चितौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर एवम् जयपुर में स्थित बीज संसाधन एकक में तैनात नियमित कर्मचारियों को प्रथम मई, 1988 से 30 सितम्बर, 1991 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की

अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे,

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी, उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते,

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे,

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी,

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी :—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिटियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा-अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं है जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं, या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए, कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध, प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेजें, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है हैं कि वह कर्मचारी है परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[सं. एस.38014/4/90 एस.एस—I]

ए के भट्टाराई, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पत्र देरी से प्राप्त हुआ था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 9th May, 1991

S.O. 1479.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby exempts the regular employees of the Regional office at Jaipur and Seeds Processing Units at Ajmer, Bharatpur, Chittorgarh, Jodhpur, Kota, Alwar, Sriganganagar, Udaipur & Jaipur of M/s. National Seeds Corporation Ltd., New Delhi from the operation of the said Act for a period with effect from 1st May, 1988 upto and inclusive of the 30th September, 1991.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid establishment wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory/establishment shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purpose of :—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to sider necessary ; or

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/4/90/S.S.I]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption has received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

नई दिल्ली 8 मई, 1991

का. आ. 1480.— केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा चलाए जा रहे बैंकिंग उद्योग की जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद 2 के अन्तर्गत आता है, उक्त अधीनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए।

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए छः मास की कालावधि के लिए तत्काल प्रभाव से लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस. 11017/2/85-डी-1 (ए)]
वी० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th May, 1991

S.O. 1480.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the Banking Industry as carried on by a regional rural bank established under section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976, which is covered by item 2 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/2/85-D.I(A)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 8 मई, 1991

का. आ. 1481—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उत्प्रवासी संरक्षी कार्यालय, त्रिवेन्द्रम में नियुक्त सहायक श्रीमती तेसी फ्रैंको को दिनांक 8 मई, 1991 के लिए उत्प्रवासी संरक्षी, त्रिवेन्द्रम के सभी कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[संख्या ए. 22012/1/90—उत्प्र]
आर. के. गुप्ता, अवर सचिव

S.O. 1481.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Smt. Tessy Franco, Assistant in the Office of POE, Trivandrum to perform all functions of POE, Trivandrum in the Office of POE, Trivandrum on 8th May, 1991.

[No. A-22012/1/91-Emig.]
R. K. GUPTA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991